बिहार के बाद बंगाल की रणनीति

₹ 20

सही सोच-नई धार

DELHIN/2016/71433
वर्ष:06 अंक:07 दिसंबर 2020

रविवार

दिल्ली

www.ravivardelhi.com

काश वो मिल जाता!

कैसे रहेंगे रिश्ते?

बहुत कठिन है डगर कांग्रेस की

जनभावना के नायक योगी

VISIT…

INDIA GATE™

बासमती हर घर के लिए

AGED RICE

India ki Puraani Aadat

Available in 1kg / 5kg / 10kg / 25kg

DELHIN/2016/71433
वर्ष:06 अंक:07 दिसंबर 2020

रविवार
दिल्ली

Dcp Licensing-F.32(R9)Press2016

चेयरमैन : डॉ. गोपाल त्रिपाठी

मुख्य संपादक : प्रमोद कुमार शर्मा

कार्यकारी संपादक : राकेश गुप्ता

प्रबंध संपादक : धर्मेंद्र मिश्रा

संपादक (प्लानिंग एण्ड कंटेंट) : संदीप ठाकुर
राजनीतिक संपादक : आलोक कुमार

स्थानीय ब्यूरो :
उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड : जेपी पाल
बिहार :
छत्तीसगढ़ :
राजस्थान :
हिमाचल प्रदेश :
हरियाणा :
चंडीगढ़ :
झारखण्ड :
मध्य प्रदेश :

कानूनी सलाहकार : विकास नागवान

कला : ज्योत्स्ना

संपादकीय कार्यालय
एलजी-40, लूसा टॉवर, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, रिंग रोड, आजादपुर, दिल्ली-110033
मोबाईल : 7503333111, 9873161501

मुख्य कार्यालय
रविवार दिल्ली, 10 टॉप फ्लोर, नेहरू रोड, केवल पार्क, आजादपुर, दिल्ली-110033

स्वामी, संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा अर्चना प्रिंटर्स, डी-127, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, नई दिल्ली-1100204 से मुद्रित कराकर 10 टॉप फ्लोर, नेहरू रोड, अपोजिट रामलीला ग्राउंड, केवल पार्क, आजादपुर, दिल्ली-33 से प्रकाशित किया।

*संपादक : प्रमोद कुमार शर्मा

इस अंक में प्रकाशित रचनाओं के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं, पत्रिका में छापे किसी भी लेख के लिए संपादक उत्तरदायी नहीं है।

प्रकाशित सामग्री या विज्ञापन से संपादक प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं। इससे संबंधित किसी प्रकार की कार्यवाही या पूछताछ प्रकाशन तिथि से तीन माह के अंदर की जा सकती है। उसके बाद किसी भी प्रकार का कार्यवाही या पूछताछ का जवाब देने के लिए हम बाध्य नहीं हैं।

प्रेषित स्पष्टीकरण प्रकाशित किया जाएगा। विवाद की स्थिति में न्यायश्लोत्र दिल्ली होगा।

ravivardelhi1@gmailÜcom

इस बार

www.ravivardelhi.com

आवरण कथा :

कैसे रहेंगे रिश्ते?

10

अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ने जिस तरह अपने सामरिक हितों को भारत के साथ जोड कर देखा है उससे लगता है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घरेलू नीतियों को जरुरत से ज्यादा उछालकर भारत अमेरिका के सामरिक साझेदारी के रिश्तों को प्रभावित नहीं होने देंगे।

कोरोना-काल 06

कोरोना का राजनीतिकरण बन रहा जानलेवा

कोरोना से निपटने की तैयारियां फुस्स पड़ने लगी है। सरकारों को कोविड टेस्टिंग की सुविधा को सुगम बनाने में थोड़ी सफलता जरुर मिली है लेकिन उससे हताश निराश मरीजों की बढती तादाद को सम्हालना मुश्किल हुआ जा रहा है।

पश्चिम बंगाल 14

अबकी बार बंगाल में बीजेपी सरकार का नारा

बीजेपी के लिए बंगाल प्रतिष्ठा का प्रश्न है और केन्द्रिय आला कमान ने ऐसी व्यूह रचना की कि लोकसभा में इतनी बड़ी तादाद में सीटें बीजेपी की झोली में आ गईं।अब बीजेपी की नजर विधानसभा पर है...

बिहार 24

चुनौतियों का पहाड़, कैसे टिकेगें नीतीश

सात की संख्या बेशक नीतीश कुमार के लिए लकी साबित होती हो, लेकिन सातवीं पार मुख्यमंत्री की पारी उनके लिए आसान नहीं दिखती है। यह पहली बार हुआ है कि वे छोटे भाई की भूमिका में हैं।

सियासत 26

दो कट्टर विचारधाराओं के उदय से झुलस रही भारतीय लोकतंत्रीय राजनीति?

दिल्ली प्रदूषण 28

दिल्ली में खुद हवा को सांस लेने में तकलीफ

देश की राजधानी दिल्ली के लिए अब यह आम बात होती जा रही है। हर साल नवंबर के महीने में दिल्लीवासियों की आंखें जलने लगती हैं, फेफड़े चोक हो जाते हैं और लोगों का खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस तरह दिल्लीवासियों के लिए सर्दियों की शुरूआत होती है। इस साल भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन इस बार कोरोना का कहर भी बरपा है।

अपराध 30

रसूखदार अरबपति आईपीएस का मायालोक

दिल्ली पुलिस में तैनात रहे डीसीपी के आगे बौने हुए आयकर व ईडी जैसे महकमें

संपादकीय

कोरोना के कारण स्कूल से दूर हो गए बच्चे, कहीं पढ़ाई से भी दूर न हो जाएं

प्रमोद शर्मा

कोविड-19 के कारण आठ महीने से भी अधिक समय हो गया देश के स्कूल,कॉलेज व तमाम शैक्षणिक संस्थान बंद पड़े हैं। ये पूरी तरह कब खुलेंगे किसी को नहीं पता। बीच बीच में प्रयोग के तौर पर इक्का दुक्का राज्य स्कूल खोलते हैं लेकिन छात्रों के निगेटिव पॉजेटिव हो जाने पर स्कूल बंद करने पड़ते हैं। लाखों छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। कई बोर्ड बिना परीक्षा के ही बच्चों को अगली कक्षा के लिए प्रोमोट कर रहे हैं। नया शैक्षणिक सत्र अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में अभिभावकों को बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंता हो गई है।

भविष्य को लेकर चिंतित होने के बावजूद एक रिपोर्ट के अनुसार अधिकांश माता-पिता ऐसे हैं,जो बच्चों को तब तक स्कूल नहीं भेजना चाहते जब तक कि इस महामारी का कोई ठोस इलाज न सामने आ जाए। बेशक उन्हें बच्चों को घर पर ही क्यों न रखना पड़े। ऐनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन ने विगत सितंबर में एक सर्वे किया था। रिपोर्ट स्कूली शिक्षा खास तौर से ग्रामीण शिक्षा की बेहद चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के कारण ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 20 फीसदी बच्चों के पास पाठ्यपुस्तकें ही नहीं हैं। यह राष्ट्रीय औसत है। अलग-अलग राज्यों के हालात अलग अलग हैं।

राजस्थान में पाठ्यपुस्तकों से वंचित बच्चों का प्रतिशत 40 है जबकि आंध्र प्रदेश में 65 से भी ज्यादा। लाइव ऑनलाइन कक्षाओं की बड़ी चर्चा है, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक हर पांच में से दो माता-पिता के पास बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के सेटअप के लिए जरूरी सामान ही नहीं है। लेकिन वे फिर भी बच्चों को घर बिठा कर ही रखना चाहते हैं।

अभिभावकों के मन में बैठा डर उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने से रोक रहा है। उन्हें पता है कि बच्चों को लाख ध्यान दिलाया जाए तो भी वे न तो मुंह पर मास्क लगाए रख पाएंगे, न ही दोस्तों से डिस्टेंस मेनटेन करेंगे। यह डर वास्तविक है और रातोंरात नहीं छंटने वाला।

यानी देश के ज्यादातर बच्चों के कोरोना से पहले वाले स्तर की शिक्षा तक दोबारा पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। और यह स्थिति उन बच्चों की है जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था के दायरे में शामिल हैं। विकल्प के तौर पर ऑन लाइन क्लासेज ली जा रही हैं लेकिन उसकी पहुंच भी शत प्रतिशत छात्रों तक नहीं है।

लोकल सर्कल नाम की एक गैर सरकारी संस्था ने हाल ही में एक सर्वेक्षण किया है। इसमें देश भर के विभिन्न राज्यों के 203 ज़िलों के 23 हजार लोगों ने हिस्सा लिया। जिनमें से 43% लोगों ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस के लिए उनके पास कम्प्यूटर, टैबलेट, प्रिंटर, राउटर जैसी चीजें नहीं है।

ग्लोबल अध्ययन से पता चलता है कि केवल 24% भारतीयों के पास स्मार्टफोन है। सर्वे के अनुसार केवल 24% भारतीय घरों में इंटरनेट की सुविधा है, जिसमें शहरी घरों में इसका प्रतिशत 42 और ग्रामीण घरों में केवल 15% ही इंटरनेट सेवाओं की पहुँच है।

इंटरनेट की उपयोगिता भी राज्य दर राज्य अलग हो जाती है। मसलन, दिल्ली, केरल, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में 40% से अधिक घरों में इंटरनेट का उपयोग होता है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में यह अनुपात 20% से कम है।

वैसे भी जब भारत में केवल 24 फीसदी घरों तक ही इंटरनेट की उपलब्धता है तो ऑनलाइन शिक्षा की सार्थकता पर स्वयं सवाल उठ जाते हैं। बच्चों को भी ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। स्क्रीन पर घंटों बैठना बच्चों के लिए अब सजा बनती जा रही है। उधर निजी शिक्षा संस्थान अभिभावकों पर दबाव बनाकर फीस वसूल करने से बाज नहीं आ रहे हैं।

लेकिन कोरोना के कारण लोग इतना डरे हुए हैं या इस कदर परहेज कर रहे हैं कि वे अपने बच्चों को घर बिठा स्कूल को फीस देने के लिए तैयार हैं। विशेषज्ञों की यदि माने तो मौजूदा शैक्षणिक सत्र तो ऐसे ही बीतेगा लेकिन अगला शैक्षणिक सत्र भी नियमित हो पाएगा या नहीं,निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कि यह महामारी का दौर कब तक चलेगा। सभी को इसके बीच रहते हुए तैयार करने पर सोचना चाहिए । सब को एजुकेशन कैसे दी जाए, कैसे इसे कॉन्टीन्यू रख सकें, इस पर मंथन की जरूरत है। तकनीक पूरी तरह से अपग्रेड नहीं है, मगर इसका कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। फेस टू फेस हुए बिना पढ़ाई को घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए इस पर मंथन की जरूरत है।

कई राज्य विचार कर रहे हैं कि स्कूल तब तक नहीं खुलेंगे जब तक कि कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती। ऐसे राज्यों में दिल्ली सबसे पहले है। अभिभावकों के मन में बैठा डर उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने से रोक रहा है। उन्हें पता है कि बच्चों को लाख ध्यान दिलाया जाए तो भी वे न तो मुंह पर मास्क लगाए रख पाएंगे, न ही दोस्तों से डिस्टेंस मेनटेन करेंगे। यह डर वास्तविक है और रातोंरात नहीं छंटने वाला।

जनभावना के जन नायक है योगी आदित्यनाथ

जय प्रकाश पाल

भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यो के मुख्यमंत्रियों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद लगातार बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्य नाथ ने उस वक्त उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली थी जब प्रदेश को एक बीमारू राज्य का तमगा मिला हुआ था। मगर अपने चार साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ ही नौकरशाही पर भी अपनी पकड़ मजबूत की है। दरअसल योगी आदित्यनाथ बखौफ, और बेबाक अंदाज में काम करने और बोलने वाले राजनेता है। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने न केवल अफसरशाही पर नेकल कसी बल्कि प्रदेश में माफियाराज अपराधी राजनेताओं पर भी कड़ा अंकुश लगाने का काम किया है।

योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की बागडोर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के इशारे पर प्रदान की गई थी। हालांकि उनकी ताजपोशी के वक्त प्रदेश के शीर्ष भाजपा नेताओं ने अपने सुर में बोलना शुरू किया था मगर जल्दी ही संघ के इशारे पर सब चुप हो गए। उत्तर प्रदेश की बिगडी कानून व्यवस्था और माफिया राज पर अंकुश लगाने के लिए योगी आदित्यराज ने पुलिस को कड़े निर्देश दिए जिनके बाद प्रदेश से गुंडे और माफिया या तो पलायन कर गए या पुलिस मुटभेड़ में मार गिराए गए। प्रदेश की अफसर शाही के भ्रष्टाचार पर योगी आदित्यनाथ न इतना अंकुश लगाया कि किसी भी जिले में सांसद अथवा विधायक की शिकायत लखनऊ तक नहीं पहुंची। लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने प्रदेश में आक्रामक प्रचार शैली के बल पर सपा बसपा गठबंधन को नेस्तानामूंद करने का काम किया जिसके बाद योगी आदित्यनाथ

की गणना भाजपा के कद्दावर नेताओं में होने लगी।

अपने आक्रामक तेवरों के लिए पहचाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने जब प्रदेश में दंगा फैलाने की साजिश रचने वालों की संपत्ति से हजार्ना वसूलने की योजना बनाई तो सारे प्रदेश की जनता वाह-वाह कर उठी। योगी आदित्यनाथ की सरकार को चार साल का वक्त पूरा हो चुका है। ऐसे में अपनी सरकार के अंतिम साल में वह इस तरह के ताबड़तोड़ कार्य कर रहे है जिन्हें सीधे जनता पसंद कर रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्र, बदन सिंह बद्दों जैसे बाहुबलियों की संपत्ति पर बुलडोजर चला कर उन्होंने दिखा दिया कि उनके राज में बाहुबलि और माफिया बीते कल की बात हो चुके है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सीधे उन मुद्दों को उठाते है जो सीधे जनता से जुड़े है और जिन्हें जनता पसंद करती है। योगी आदित्यनाथ की बाहुबलियों पर हो रही कार्यवाही की सारा प्रदेश प्रशंसा कर रहा है। जिन राजनेताओं के घर में जाने से कभी पुलिसवालों को डर लगता था उनकी अवैध संपत्तियों को सरकारी बुलडोजर जमीदोंज कर रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में दो बड़ी विकास परियोजनाओं की शुरूआत करते दिखा दिया आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश कहां पहुंचने वाला है। गोरखपुर से लेकर आगरा एक्प्रेस-वे और गोरखपुर से लेकर मेरठ तक गंगा एक्सप्रेस-वे ऐसी बहु उद्देशिय सड़क योजनाए है जिन पर आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के विकास की योजनाओं का खाका तैयार होगा। बुंदेलखंड डिफेंस कोरिडोर हो या ओपीओडी योजना, या मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना अथवा कन्या सुमंगला योजना यह इस तरह की योजनाएं है जिनका लाभ सीधे प्रदेश के हर ग्रामीण इलाके में पहुंच रहा है नोएडा में नई फिल्म सिटी बनाने की योजना हो अथवा अयोध्या को विश्व पर्यटन के मानचित्र पर लाने की योजना हो योगी आदित्य नाथ ने इन सभी योजनाओं को मूर्त रूप देने का काम किया है। प्रदेश की जनता का दोबारा विश्वास प्राप्त करने के से पूर्व योगी आदित्य नाथ ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के 8 उपचुनावों में से 7 पर विजय पाकर साबित कर दिया है प्रदेश में उनकी लोकप्रियता का ग्राफ अभी भी कायम है। राज्यसभा चुनावों में भाजपा के 8 उम्मीदावरों की जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जिस तरह की योजना बनाई उससे सपा और बसपा की कलई खुल गई और बसपा में सपा व्दारा लगाई सेंध से मायावती का सारा सियासी गणित भी ध्वस्त हो गया।

बिहार विधानसभा चुनावों के वक्त योगी आदित्यनाथ भाजपा के सबसे लोकप्रिय स्टार प्रचारक रहे। बिहार में उन्होंने जहां भी प्रचार किया वहा भाजपा उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश कोरोना संकट के दौरान उन्होंने जिस खूबी के साथ कामकाज संभाला और लाखों प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी कराई उसकी सारे देश में प्रंशसा हुई।

लॉकडॉउन के दौरान जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के छात्रों को राजस्थान के कोटा शहर से लाने के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों को भेजा तो लाखों परिवार उनके मुरिद हो गए। जन कल्याण और जनभावना के साथ काम करने का हुनर योगी आदित्यनाथ को बखूबी आता है वह जनता की नब्ज पहचानते है और उसी के मुताबिक तत्काल कदम भी उठाते है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक वरिष्ठ नेता इन पंक्तियों के लेखक से कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक मंजे हुए राजनेता है खासबात यह हैं कि उनकी छवि बेहद ईमानदार और कठोर है जिस तरह केंद्र में नरेन्द्र मोदी की छवि है उसी तरह से उत्तर प्रदेश मे आदित्यनाथ की छवि है इसी छवि के सहारे भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव भी जितेगी।

आलोक कुमार

कोरोना का राजनीतिकरण बन रहा जानलेवा

यह मानव सभ्यता को रुलाने वाले साल के आखिरी महीने की शुरूआत है। कोविड संक्रमण से लहालोट सब्र जवाब देने लगा है। महामारी का तांडव ऊफान पर है। कातर मानवता खौफ में है। चारों ओर मौत का मंजर पसरा है। माहौल में नकारात्मकता की जहर घुली है। सर्वोच्च न्यायालय इंतजामात की कमी को लेकर सरकारों को लगातार फटकार लगाए जा रही है। सेल्फ आइसोलेशन में रहना और खुद को सकारात्मक रखना ही इससे बचने का फिलहाल उपाय बचा है। लेकिन आइसोलेशन और सकारात्मकता की भी सीमा है। आबादी की बहुलता कोविड संक्रमण से लोगों को बचाने में निष्प्रभावी साबित हो रहा है।उम्मीद की किरण सिर्फ सही वैक्सीन के इजाद से बंधी है। संतोष की बात है कि कोविड से जान बचाने वाली कई वैक्सीन परीक्षण के अंतिम चरण में है। अगले साल की शुरूआत में बचावी वैक्सीन के मेगा टीकाकरण अभियान की शुरूआत होनी है।

वैक्सीन के लिए दुनिया भर में तैयारी है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, रुस सहित तमाम विकसित देश वैक्सीन की अनुमानित कीमतों पर विचार कर रहे हैं। अपने यहां पल्स पोलियो की तरह ही देशभर में मुफ्त टीकाकरण का फैसला लिया है। उस लिहाज से बजटीय प्रावधान किया जाना है। अमेरिका में वैक्सीन को

> **कोरोना से निपटने की तैयारियां फुस्स पड़ने लगी है। सरकारों को कोविड टेस्टिंग की सुविधा को सुगम बनाने में थोड़ी सफलता जरुर मिली है लेकिन उससे हताश निराश मरीजों की बढती तादाद को सम्हालना मुश्किल हुआ जा रहा है।**

विकसित करने में 955 मिलियन डॉलर खर्चने की उम्मीद है। वहां हर व्यक्ति को 32-37 डॉलर यानी करीब 2800 रुपए में वैक्सीन की एक खुराक मिल सकती है। इस कीमत को दस डॉलर से नीचे रखने के लिए जद्दोजहद जारी है। प्रभावी वैक्सीन विकसित करने में लगी प्रमुख कंपनी फाइजर का कहना है कि उसे वैक्सीन विकसित करने में कोई फेडरल फंडिंग नहीं मिली है। जर्मन सरकारी सहायता में बायोएनटेक को 444 मिलियन डॉलर मिले। फाइजर के वैक्सीन की कीमत लगभग 3000 रुपए आंकी गई है। अपने यहां आसीएमआर में विकसित हो रही वैक्सीन की कीमत का लेखाजोखा सार्वजनिक नहीं हो पाया है।

जैसे ही वैक्सीन आएगा सरकार की तरफ से प्राथमिकता की सूची भी जारी होगी। यह माना जा रहा है कि सबसे पहले देश में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। क्योंकि मरीजों के इलाज के दौरान सबसे ज्यादा खतरा उन्हें ही है। इसके बाद महामारी के खतरे के लिहाज से जो मैपिंग होगी उसी लिहाज से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन भी तय होगा।

नीति आयोग को इसकी तैयारी में लगाया गया है। केंद्रीय मंत्रालयों के तालमेल से वैक्सीन पहुंचाने के लिए डाक विभाग के नेटवर्क की मदद ली जाएगी। दूर-दराज तक पहुंचाने के लिए इसके साथ ही लोकल स्तर पर पंचायत में आंगनवाड़ी वर्कर से लेकर दूसरे सरकारी विभागों के कर्मचारियों की जरूरत पड़ने पर नजर दी जाएगी। संचार मंत्रालय को इसके लिए पहले ही कहा जा चुका है कि वह अपने डाक विभाग का नेटवर्क पूरी तरह से तैयार रखें ताकि जरूरत पड़ने पर कोरोना वैक्सीन को दूरदराज के इलाकों में पहुंचाने के लिए उसका उपयोग किया जा सके।

जानकारों की माने तो विदेशी कोविड-19 वैक्सीन खरीदने में सरकार के सामने सबसे मुश्किल सवाल उसके रखरखाव का है। क्योंकि भारत के विभिन्न हिस्सों में बदलते तापमान में उनकी अनुकूलता कायम रखना संभव नहीं होगा। देश में -2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान तक के रखरखाव वाली वैक्सीन ही कारगर होगी, क्योंकि ऐसी कोरोना वैक्सीन को पल्स पोलियो अभियान के तहत बच्चों को पिलायी जाने वाली वैक्सीन की तर्ज पर सहेजकर लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा।

ऐसे में अमेरिका में तैयार की जा रही फाइजर वैक्सीन भारत में कारगर कैसे होगी इसको लेकर चिंता है, क्योंकि उसे माइनस 70 डिग्री तापमान में सहेजना होता है। जबकि मॉडर्ना को माइनस 8 डिग्री तक सहेजा जा सकता है। वहीं रुस में तैयार हो रहे स्पूतनिक-5 का रखरखाव माइनस 20 डिग्री तक है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों की माने तो हर वैक्सीन को सहेजने और दूरस्थ इलाकों में सुगमता से पहुंचाने की प्रभावी तैयारी है। इसमें प्लस पोलियो अभियान की सफलता के अनुभव की सीख काम आ

REXONA®

FAMILY FOOTWEAR

enjoy THE WALK

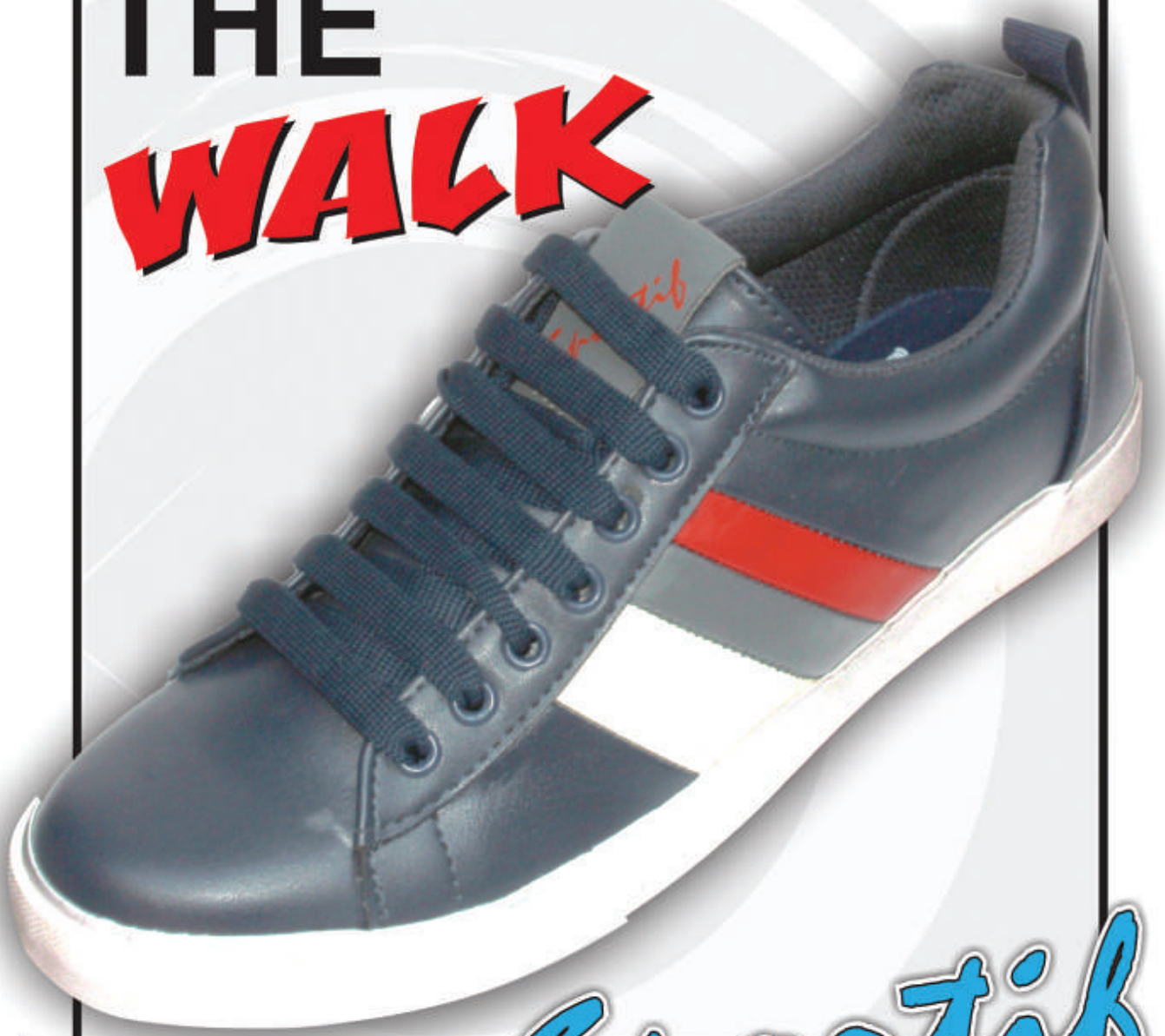

Sportif

E-mail : rexonafootwear@gmail.com, Web : www.rexonafootwear.co.in

रही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सर्वाधिक संक्रमित आठ राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए भरोसा दिया है किवैज्ञानिक वैक्सीन की गुणवत्ता,क्षमता और सुरक्षा परीक्षण के अंतिम चरण में लगे है। वैक्सीन की पहचान तय हो जाने के बाद ही अगले साल किसी वक्त मेगावैक्सीनेशन अभियान से लोगों के जान बचाने के सटीक उपक्रम की शुरूआत हो पाएगी।

यह साल कोविड संक्रमण की टेस्ट बढाने, संक्रमण का दर पांच फीसदी से नीचे रखने की कोशिश में लगे रहने, मृत्यु दर एक फीसद से कम करने और इजाद होने वाले वैक्सीन को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में बीत रहा है। लिहाजा 2020 काटे नहीं कट रहा।

इन सबके बीच सबसे बुरी बात है कि मरीजों को बचाने के लिए डाक्टरों के पास सटीक इलाज नहीं है। चिकित्सा विज्ञान की बेबसी छलक रही है। अबतक बस ट्राइल एंड एरर बेसिस पर ही मरीजों को बचाने की कोशिश जारी है। कोरोना ने सबको हिला रखा है। श्वास पर काम करने वाले योगियों तक को कोविड ने चपेट में ले लिया है। फिर भी आयुर्वेद और होमियोपैथिक चिकित्सकों की राय है कि डीप ब्रीथिंग के व्यायामों और योगासनों ने संक्रमण साधने में काफी हद तक सफलता पाई है। लेकिन डेटाबेस की सुविधा के अभाव में पारंपरिक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रैक्टिसनर्स को एलोपैथ से मुकाबिल होना मुश्किल पड़ा है। राजधानी दिल्ली के कनाट प्लेस में प्रैक्टिस कर रहे होमियोपैथ के डॉक्टर सुधीर तोमर का दावा है कि होमियोपैथ दवाएं कोविड संक्रमण से बचाने में प्रभावी हैं। होमियोपैथ व अन्य पारंपरिक तरीकों को अपनाने की वजह से हीभारत में कोविड संक्रमण से मौत का अनुपात बेहद कम है।

कोविड -19से जुड़ा भयावह तथ्य है कि दिवाली के बाद महामारी से जीवन त्यागने वालों में हर पांचवें शख्स का तालुल्क राजधानी दिल्ली से है। संक्रमण बेकाबू हो चुका है। मौत की संख्या दिल्ली और एनसीआर इलाकेसे निरंतर बढ रही है। मुंबई, चेन्नई,

यह साल कोविड संक्रमण की टेस्ट बढाने, संक्रमण का दर पांच फीसदी से नीचे रखने की कोशिश में लगे रहने, मृत्यु दर एक फीसद से कम करने और इजाद होने वाले वैक्सीन को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने की तैयारी में बीत रहा है। लिहाजा 2020 काटे नहीं कट रहा।

हैदराबाद जैसे महानगर कोविड के अगले लहर की आशंका से कांप रहे हैं। बडों की बेबसी देख छोटे शहर डरे सहमे हैं। लोग गहन चिंता की मुद्रा में हैं।इस दशक में आपसी मेलजोल का सबसे बड़ा साधन बने सोशल मीडिया ने इनदिनों खुद को शोकसभा केजलसोंमें तब्दील कर लिया है। बडे से बड़े नेता व मंत्रियों तक को संक्रमण से बचाना मुश्किल हुआ पड़ा है। खास की बेहाली देखआम आदमी के बचने की उम्मीद पर ग्रहण लगा है।

कोरोना से निपटने की तैयारियां फुस्स पड़ने लगी है। सरकारों को कोविड टेस्टिंग की सुविधा को सुगम बनाने में थोड़ी सफलता जरुर मिली है लेकिन उससे हताश निराश मरीजों की बढती तादाद को सम्हालना मुश्किल हुआ जा रहा है। बडी संख्या में पहुंच रहे मरीजों का अस्पतालों में इलाज के लिए बेड नहीं है। आईसीयू और वेंटीलेटर की कमी का रोना जारी है। मंहगी इलाज के लिए कुख्यात कोरपोरेट अस्पतालों तक में भर्ती के लिए भी पैरवी करने वालों का तांता लगा है।

SUGANDH®

MASALA TEA

Enriched with Real spices

www.sugandhtea.com

अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ने जिस तरह अपने सामरिक हितों को भारत के साथ जोड कर देखा है उससे लगता है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घरेलू नीतियों को जरुरत से ज्यादा उछालकर भारत अमेरिका के सामरिक साझेदारी के रिश्तों को प्रभावित नहीं होने देंगे। अमेरिका को पता है कि दुनिया में चीन की दादागिरी को रोकना है तो हिंद महासागर के इलाके में भारत को साथ रखना जरुरी होगा।

बाइडन के कार्यकाल में कैसे रहेंगे रिश्ते?

रंजीत कुमार

अमेरिका का चुनावी घमासान समाप्त होने के बाद किस्सा कुर्सी का खत्म नहीं हुआ है। जनमत में काफी पीछे रहने के बावजूद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अपनी कुर्सी छोडने को तैयार नहीं हैं। अमेरिकी जनतंत्र पर यह बहुत बडा धब्बा साबित होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि कैसे भी हो राष्टपति ट्रम्प को ह्वाइट हाउस छोडना ही पडेगा लेकिन राष्ट्रपति जैसा जिम्मेदार राजनेता ऐसी ओछी हरकत करे, यह अमेरिकी जनतंत्र के लिये भारी शर्मिंदगी की बात है।

चुनाव नतीजे पता चलने के बाद राष्ट्रपति का विजयी प्रत्याशी सत्ता सम्भालने के लिये अपनी टीम बनाने में जुटता है और प्रशासन की भावी नीतियों को तय करने के लिये अपने सहयोगी राजनेताओं और अधिकारियों के साथ सलाहमशविरा करने में जुटा रहता है। इस प्रक्रिया में निवर्तमान राष्ट्रपति और उनके सहयोगियों को भावी राष्ट्रपति के साथ तालमेल बना कर हर तरह से सहयोग करने की अपेक्षा की जाती है लेकिन निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा नहीं कर रहे।

> **“ अमेरिका की घरेलू और विदेश नीतियों का विश्व राजनीति पर गहरा असर पडता है इसलिये सारी दुनिया की अमेरिकी प्रशासन की अंदरुनी और अंतरराष्टीय नीतियों पर गहरी नजर रहती है। भारत भी अमेरिका के विश्व रंगमंच और देश के अंदर उठाए जाने वाले कदमों से अछूता नहीं रहेगा। वास्तव में भारत का भविष्य और भारत की कूटनीति और समर नीति अमेरिका के कदमों से प्रभावित होगी। इसलिये राष्ट्रपति जोसेफ बाइडन आने वाले सालों में क्या नीतियां अपनाते हैं इस बारे में भारतीय राजनयिक हलकों में गहरी चिंता है।**

डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपतीय प्रत्याशी जोसेफ बाइडन की जीत के नतीजे सबके सामने हैं लेकिन एक सनकी तानाशाह की तरह डोनाल्ड ट्रम्प इन नतीजों को स्वीकार करने को तैयार नहीं। दुनिया के सबसे पुराने जनतांत्रिक देश में हुए राष्ट्रपतीय चुनाव के बाद सत्तारुढ पार्टी द्वारा दिखाए गए गैरजनतांत्रिक रवैये ने दुनिया को हैरान किया है। डोनाल्ड ट्रम्प कुछ भी कहें वह अपने देश और पूरी दुनिया में मजाक के पात्र बन चुके हैं। अमेरिकी सैन्य नेतृत्व ने भी संकेत दिया है कि वह संक्रमण काल के दौरान राष्ट्रपति ट्रम्प के फैसलों को नहीं मानेंगे। इसलिये डोनाल्ड ट्रम्प कितना ही नाटक करें आगामी 20 जनवरी को उन्हें ह्वाइट हाउस छोडना ही पडेगा।

जो भी हो अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडन आगामी 20 जनवरी को ह्वाइट हाउस में प्रवेश करेंगे और दुनिया की सबसे बडी सैन्य और आर्थिक ताकत की सत्ता सम्भालेंगे। अमेरिका की घरेलू और विदेश नीतियों

का विश्व राजनीति पर गहरा असर पडता है इसलिये सारी दुनिया की अमेरिकी प्रशासन की अंदरुनी और अंतरराष्टीय नीतियों पर गहरी नजर रहती है। भारत भी अमेरिका के विश्व रंगमंच और देश के अंदर उठाए जाने वाले कदमों से अछूता नहीं रहेगा। वास्तव में भारत का भविष्य और भारत की कूटनीति और समर नीति अमेरिका के कदमों से प्रभावित होगी। इसलिये राष्ट्रपति जोसेफ बाइडन आने वाले सालों में क्या नीतियां अपनाते हैं इस बारे में भारतीय राजनयिक हलकों में गहरी चिंता है। वैसे तो भारत के साथ रिश्तों को लेकर अमेरिका में सभी हलकों और राजनीतिक दलों में आम राय रही है इसलिये यह माना जा सकता है कि जोसेफ बाइडन भारत के साथ सामरिक रिश्तों की अहमियत को अपने देश के हितों से जोडते हुए समझते हैं और पहले की तरह भारत

“ जोसेफ बाइडन की जनतंत्र के प्रति निष्ठा भारत को लेकर कितनी गम्भीर होगी। पिछले महीनों में जोसेफ बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने या उन्हें असुरक्षित महसूस करने वाली नीतियों के अलावा जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हनन के मसलों को उठाया है इसलिये सत्ता सम्भालने के बाद बाइडन इन मसलों को नजरअंदाज नहीं करेंगे।

के साथ सामरिक साझेदारी के रिश्तों को गहराई देने की नीतियां चलाते रहेंगे। जोसेफ बाइडन पुराने इंडिया हैंड हैं इसलिये उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वह भारत के साथ सहयोगपूर्ण, रचनात्मक और स्नेह का रिश्ता जारी रखेंगे। जोसेफ बाइडन का भारत के हितों के बारे में सोचने और इसे आगे बढाने के लिये सक्रिय भागीदारी करने का लम्बा इतिहास रहा है। 2008 में जब अमेरिका में भारत के साथ शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग समझौता करने पर गहन बहस चल रही थी तब अमेरिकी सीनेट की विदेशी मामलों की समिति के चेयरमैन की हैसियत से उन्होंने भारत की खुब पैरवी की थी।

इसलिये भारत की नजर जो बाइडन की विदेश और घरेलू नीति पर होगी। अब तक जोसेफ बाइडन ने राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान जो बयान दिये हैं उनके आधार पर यही कहा जा सकता है कि जोसेफ बाइडन के अगले चार साल का शासन काल भारत के लिये सुकून देने वाला होगा। चाहे घरेलु स्तर पर आव्रजकों का मसला हो या भारतीय पेशेवरों के लिये एच-1-बी वीजा का मसला हो भारत और भारतीयों को राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। भारत यह भी उम्मीद कर रहा है कि जनरल सिस्टम आफ प्रिफरेंसेंज जैसी भारत को वरीयता देने वाली जिस नीति को राष्टपति ट्रम्प ने अमान्य कर दिया था राष्टपति बाइडन फिर बहाल कर देंगे।

बाइडन और मोदी के रिश्तों में वह तमाशेबाजी देखने को नहीं मिलेगी

जो डोनाल्ड ट्रम्प के शासन काल में हमने देखी है। अमेरिका में नरेन्द्र मोदी के स्वागत में हाउडी मोदी और अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रम्प के लिये रोड शो नमस्ते ट्रम्प के आकर्षक आयोजन ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में फुलझडियों जैसा माहौल पैदा किया लेकिन वह गहराई देखने को नहीं मिली जो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के आठ सालों के शासन काल में हमने देखी है। वास्तव में डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत के लिये आर्थिक मोर्चे से लेकर विदेशी मोर्चे पर मुश्किलें ही पैदा की हैं। भारत के लिये सबसे बडी राहत की बात यही थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान, आतंकवाद और चीन के मसले पर खुलकर भारत का साथ दिया। यही वजह थी कि भारत डोनाल्ड ट्रम्प की कई नीतियों के खिलाफ मुखर नहीं रहा। ट्रम्प की इन नीतियों को भारत ने अमेरिका के साथ

“ अमेरिका में नरेन्द्र मोदी के स्वागत में हाउडी मोदी और अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रम्प के लिये रोड शो नमस्ते ट्रम्प के आकर्षक आयोजन ने भारत और अमेरिका के रिश्तों में फुलझडियों जैसा माहौल पैदा किया लेकिन वह गहराई देखने को नहीं मिली जो पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के आठ सालों के शासन काल में हमने देखी है।

गहराते रिश्तों में आडे नहीं आने दिया।

लेकिन जो बाइडन ने चुनाव प्रचार के दौरान साफ संकेत दिया है कि वह डोनाल्ड ट्रम्प की विदेश नीति की समीक्षा करेंगे। डोनाल्ड ट्र्म्प ने ईरान से रिश्ते नहीं रखने पर जोर दिया और अफगानिस्तान से अपने पांव हटाने का ऐलान किया । जो बाइडन ने यह भी कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन में अमेरिका की सदस्यता बहाल करेंगे और चीन के साथ परिपक्व नीति अपनाएंगे। जोसेफ बाइडन ने साफ कहा है कि वह यह सुनिश्चित करेंगे कि चीन अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन और सम्मान करे।

जोसेफ बाइडन ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात कर भारत के साथ रिश्तों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने हिंद प्रशांत इलाके को लेकर डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियों को जारी रखने का भी संकेत दिया। यदि जो बाइडन ट्रम्प की हिंद प्रशांत नीति को जारी रखते हैं तो साफ हैकि चुनाव प्रचार के दौरान चीन के बारे में जो उद्गार जाहिर किये उस पर डटे रहेंगे। जोसेफ बाइडन ने चीन के राष्ट्रपति शी चिन फिंग को ठग कहा था इसलिये चीन जोसेफ बाइडन से काफी चिढा हुआ है। जोसेफ बाइडन के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्षों ने जोसेफ बाइडन को बधाई दी लेकिन चीन ने कई दिनों तक कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

साफ है कि चीन को पता है कि जोसेफ बाइडन सत्ता सम्भालने के बाद चीन को लेकर क्या रुख अपनाने वाले हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प अमेरिका के ऐसे

पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने चीन को उसकी औकात बताने की हिम्मत की है। इसलिये राष्ट्रपति बाइडन अपने देश में लोगों को और बाकी दुनिया को यह कतई संदेश नहीं देना चाहेंगे कि वह चीन के आगे झुकने लगे हैं। चीन ने जिस तरह दुनिया पर अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दी है और अमेरिका को हटा कर उसका स्थान लेने की रणनीति पर काम कर रहा है काफी कुछ राष्ट्रपति ट्रम्प की वैश्विक नीतियों ने चीन को ऐसा करने का मौका प्रदान किया है। ट्रम्प ने जिस तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन को छोडा तो वह चीन के लिये विश्व रंगमंच पर अपना दबदबा बढाने का मौका दे गए। इसी तरह अमेरिका ने काबुल से अपने पांव खींचने का ऐलान तालिबान से शर्मनाक समझौता कर किया वह अमेरिका जैसी विश्व ताकत के लिये शर्मिंदगी पैदा करने वाली बात है। आखिर जिस तालिबान को अमेरिका ने 2002 में खत्म करने का बीडा उठाया था उसी तालिबान के साथ उसी की शर्तों पर अमेरिका द्वारा समझौता करना चीन के लिये लाभजनक साबित होगा। काबुल से अमेरिका के जाने के बाद चीन उस खाली जगह को भरेगा। हालांकि अफगानिस्तान को लेकर जोसेफ बाइडन ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा है कि वह अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज को पूरी तरह हटा लेंगे या काबुल में अपनी मौजूदगी बनाते हुए वहां की जनतांत्रिक सरकारको बचाने और उसे सत्ता में बनाए रखने में हर सम्भव मदद करेंगे।

जोसेफ बाइडन ने जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी के साथ टेलीफोन वार्ता में अपने देश और देश से बाहर जनतंत्र की रक्षा की बात की है उससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जोसेफ बाइडन अफगानिस्तान में जनतांत्रिक सरकार को अमेरिका का पूरा सहयोग बनाए रखेंगे और अपने संकल्प के अनुरुप काबुल में जनतांत्रिक सरकार को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। निश्चय ही अपने देश और बाहरी दुनिया में जनतंत्र को बचाने के जो संकल्प जो बाइडन ने व्यक्त किये हैं वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के

जोसेफ बाइडन की जनतंत्र के प्रति निष्ठा भारत को लेकर कितनी गम्भीर होगी। पिछले महीनों में जोसेफ बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने या उन्हें असुरक्षित महसूस करने वाली नीतियों के अलावा जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हनन के मसलों को उठाया है इसलिये सत्ता सम्भालने के बाद बाइडन इन मसलों को नजरअंदाज नहीं करेंगे।

लिये चिंताजनक साबित हो सकते हैं।

देखना होगा कि जोसेफ बाइडन की जनतंत्र के प्रति निष्ठा भारत को लेकर कितनी गम्भीर होगी। पिछले महीनों में जोसेफ बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत में अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने या उन्हें असुरक्षित महसूस करने वाली नीतियों के अलावा जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हनन के मसलों को उठाया है इसलिये सत्ता सम्भालने के बाद बाइडन इन मसलों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय इसे भारत के अंदरुनी मामलों में दखल करने की बात कह कर अमेरिकी आरोपों का जवाब देने से बचने की कोशिश कर सकता है। देखना होगा कि बाइडन इन मसलों पर किस हद तक जोर देते हैं कि भारत के साथ रिश्ते नहीं प्रभावित हों।

लेकिन अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ने जिस तरह अपने सामरिक हितों को भारत के साथ जोड कर देखा है उससे लगता है कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घरेलू नीतियों को जरुरत से ज्यादा उछालकर भारत अमेरिका के सामरिक साझेदारी के रिश्तों को प्रभावित नहीं होने देंगे। अमेरिका को पता है कि दुनिया में चीन की दादागिरी को रोकना है तो हिंद महासागर के इलाके में भारत को साथ रखना जरुरी होगा। इसीलिये डोनाल्ड ट्रम्प के अमेरिकी प्रशासन ने हिंद प्रशांत नीति को गम्भीरता से लागू किया और जोसेफ बाइडन के अगले प्रशासन ने भी ट्रम्प की हिंद प्रशांत नीति को आगे बढाने की प्रतिबद्धता जाहिर की है।

अबकी बार बंगाल में बीजेपी सरकार का नारा

मधुरेन्द्र सिन्हा

बिहार का किला फतह करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का जोश बढ़ गया है और पार्टी पूरे उत्साह से नया किला जीतने की तैयारी में जुट गई है। ने केवल कैलाश विजयवर्गीय बल्कि स्वंय अमित शाह भी इस महाअभियान में जुट गए हैं। बीजेपी के लिए यह किला प्रतिष्ठा का प्रश्न है और इस बार पार्टी उत्साहित है क्योंकि उसने लोक सभा चुनाव में शानदार तरीके से 18 सीटें जीतकर एक तरह का कीर्तिमान बनाया था। किसी को इतनी सीटों की उम्मीद नहीं थी लेकिन केन्द्रिय आला कमान ने ऐसी व्यूह रचना की कि इतनी बड़ी तादाद में सीटें बीजेपी की झोली में आ गईं। यह बात इसलिए भी उल्लेखनीय है कि बंगाल में प्रशासन तथा पुलिस पूरी तरह से सत्तारूढ़ के साथ थी और कई मामलों में उन्होंने खुलकर टीएमसी की मदद की थी।

> **बीजेपी के लिए बंगाल प्रतिष्ठा का प्रश्न है और इस बार पार्टी उत्साहित है क्योंकि उसने लोक सभा चुनाव में शानदार तरीके से 18 सीटें जीतकर एक तरह का कीर्तिमान बनाया था। किसी को इतनी सीटों की उम्मीद नहीं थी लेकिन केन्द्रिय आला कमान ने ऐसी व्यूह रचना की कि इतनी बड़ी तादाद में सीटें बीजेपी की झोली में आ गईं। यह बात इसलिए भी उल्लेखनीय है कि बंगाल में प्रशासन तथा पुलिस पूरी तरह से सत्तारूढ़ के साथ थी और कई मामलों में उन्होंने खुलकर टीएमसी की मदद की थी।**

फिलहाल पार्टी ने चुनाव का बिगुल बजा दिया है और बिहार चुनाव के पूरी तरह से खत्म होने के पहले ही गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दो दिनों के दौरे पर जा पहुंचे। उन्होंने अपने अभियान की शुरूआत बांकुड़ा से की जहां आदिवासी जनसंख्या काफी है। पिछले लोक सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां की दोनों लोक सभा सीटें जीत ली थीं। अमित शाह ने इस बात के लिए बंगाल सरकार को आड़े हाथों लिया कि उसने केन्द्रीय योजनाओं को राज्य में लागू नहीं होने दिया। उनका फायदा राज्य के करोड़ों लोगों को नहीं मिल सका है और वे इनसे वंचित हैं। इन योजनाओं में आदिवासियों के लिए मकान बनाने की भी योजना है जिससे बड़ी तादाद में आदिवासियों के मकान नहीं बन पाए। इसके अलावा पीएम मोदी की सबसे चर्चित योजना किसान सम्मान निधि की राशि किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। अमित शाह ने यह मुद्दा उठाया

और बताया कि बंगाल के किसानों को हर साल मिलने वाली 6,000 रुपए की राशि से वंचित रखा गया है जो अन्यायपूर्ण है। एक ओर तो ममता बनर्जी किसानों के हित की बातें करती हैं तो दूसरी ओर वे किसानों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर ताला लगाकर बैठी हैं। वे नहीं चाहती हैं कि बंगाल में किसी भी तरह से केन्द्र सरकार का नाम हो और लोग भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करें। अमित शाह ने 13 जिलों के पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करके यह जता दिया कि वे इस चुनाव के प्रति कितने गंभीर और सक्रिय हैं।

बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ताओं की हत्या

बंगाल बीजेपी के मुताबिक वहां लोक सभा चुनाव से अब तक भारतीय जनता पार्टी के 70 से भी ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है और पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। कई मामलों में तो कार्यकर्ता को मारकर लटका दिया जाता है ताकि वह आत्महत्या का मामला दिखे। पुलिस भी ऐसा ही मामला बनाती है ताकि किसी पर कोई कार्रवाई न हो सके। कई मामलों में तो टीएमसी के दबंग कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों और यहां तक कि उनके कार्यकर्ताओं के घर फूंक दिए लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। अमित शाह ने साफ शब्दों में यह बात कही है और साथ ही राज्य सरकार को चेतावनी भी दी है कि वह हिंसा रोके नहीं तो केन्द्र जरूरी कदम उठाएगा।

कोविड का टीएमसी पर असर

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जो लोक सभा चुनाव में जख्मी होने के बावजूद मजबूत दिख रही थी, कोविड-19 का दंश झेल पाने में लाचार दिख रही है। मुख्य मंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से इसे हैंडल किया उससे न केवल विपक्ष बल्कि उनकी पार्टी के नेता भी पूरी तरह से नाराज हैं। टीएमसी के कई विधायक और कार्यकर्ता कोविड-19 के शिकार होकर परलोक सिधार गए। राज्य की खस्ता हाल स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गईं और यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि वास्तव में कितने लोग बीमार हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह दिखाने की कोशिश की कि राज्य में कोविड-19 से बहुत कम ही लोग मरे हैं। इसके लिए उन्होंने एक समिति बनाई जिसकी अनुशंसा पर ही कोविड से मृतकों के नाम बताए जाते हैं। यह समिति ज्यादातर लोगों की मौत का कारण अन्य बीमारियां जैसे हृदय रोग, किडनी फेल, वगैरह ही बताती है। इस कारण से सही आंकड़े पता नहीं चल पा रहे थे जिससे नागरिकों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और तृणमूल पार्टी में भी अंदरूनी कलह बढ़ने लगी। केन्द्र सरकार के दबाव में ममता बनर्जी ने कुछ आंकड़े बताने की इजाजत तो दी लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। इतना ही नहीं ममता बनर्जी ने राज्य के हिन्दुओं को खुश करने के लिए उनके सबसे प्रिय पर्व दुर्गा पूजा समारोह कुछ शर्तों के साथ आयोजित करने की अनुमति दे दी। लेकिन अदालत ने जनता के पंडालों में जाने पर रोक लगा दी ताकि कोविड-19 महामारी फैलने न पाए।

> सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस जो लोक सभा चुनाव में जख्मी होने के बावजूद मजबूत दिख रही थी, कोविड-19 का दंश झेल पाने में लाचार दिख रही है। मुख्य मंत्री ममता बनर्जी ने जिस तरह से इसे हैंडल किया उससे न केवल विपक्ष बल्कि उनकी पार्टी के नेता भी पूरी तरह से नाराज हैं। टीएमसी के कई विधायक और कार्यकर्ता कोविड-19 के शिकार होकर परलोक सिधार गए।

हाल के एक सर्वे से यह बात सामने आई है कि बंगाल में कोविड-19 को सही ढंग से रोकने में राज्य सरकार की विफलता से जनता ममता बनर्जी से नाराज है जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। 78,000 बूथों में किए गए इस सर्वे से यह बात समाने आई है कि टीएमसी अपनी लोकप्रियता खो रही है और अगल भारतीय जनता पार्टी सही ढंग से अपने संगठन को मजबूत करती है तो उसे इसका लाभ मिलेगा। इस सर्वे ने टीएमसी के कान खड़े कर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी को खुश कर दिया है।

टीएमसी के गढ़ में सेंध

बंगाल की राजनीति का एक दिलचस्प पहलू यह है कि यहां पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टियों के पदाधिकारियों को तोड़कर अपने यहां मिला लेती हैं। सीपीएम ने सबसे यह प्रयोग किया, फिर टीएमसी ने सीपीएम के कार्यकर्ताओं को तोड़ा और अब यही काम भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है। उसने भी तोड़-फोड़ का यह काम जारी रखा है और बड़ी तादाद में टीएमसी के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को अपने यहां जगह दे रही है। पिछले दिनों यह हवा भी उड़ी थी कि टीएमसी के लोकप्रिय नेता और सांसद सौगत राय पार्टी छोड़ रहे

> मुकुल राय ने तो यह भी दावा किया था कि विधान सभा चुनाव के पहले टीएमसी के 107 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ 3 ही विधायक पार्टी छोड़कर आए हैं। इसके अलावा 56 पार्षदों ने भी पार्टी छोड़ दी है जिससे संगठनात्मक तौर पर टीएमसी को धक्का लगा है।

ओवैसी का शंखनाद

हैदराबाद के मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। इस बार बिहार के सीमांचल में उन्हें जबर्दस्त सफलता मिली। उनकी एएमआईएमआईएम को पांच सीटें मिलीं जिससे आरजेडी को बहुत धक्का लगा।

पार्टी को यकीन था कि वहां के मुस्लिम जो मूलतः बांग्लादेशी हैं, उन्हें ही वोट देंगे लेकिन ओवैसी ने अपने जबर्दस्त भाषणों से वहां के लोगों का दिल जीत लिया। इस विजय के साथ ही उन्होंने यह घोषणा भी कर दी है कि उनकी पार्टी बंगाल में भी चुनाव लड़ेगी। यह ममता दीदी की नींद उड़ा देने के लिए काफी था।

दरअसल बंगाल में बांग्लादेशी वोटरों की तादाद बहुत है और ममता बनर्जी को यह चिंता सता रही है कि कहीं ये वोटर ओवैसी के साथ न चले जाएं। दरअसल बांग्लादेशियों की मानसिकता बदलने लगी है और वे अब स्वतंत्र तरीके से वोट देने लगे हैं क्योंकि सत्तारूढ़ दल के साथ मिलकर उन्होंने पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड जैसे महत्वूर्ण दस्तावेज बनवा लिये हैं। अब उन्हें ठिकाना मिल गया है और इसलिए उनकी सोच भी बदल गई है।

ममता बनर्जी इस बात को अच्छी तरह से समझती हैं। लेकिन उनकी समस्या यह है कि मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए वे अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकतीं क्योंकि वहां हिन्दु उनके इस तरह के कदमों से नाराज रहने लगे हैं। लेकिन वे राजनीति की माहिर खिलाड़ी हैं और कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगी।

हैं। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि चुनाव में बहुत कम समय है और ऐसे में स्थानीय नेता बनाना और स्थापित करना मुश्किल है। इसलिए पार्टी तोड़-फोड़ की राजनीति कर रही है ताकि उसे मंजे हुए और अनुभवी नेता मिल सकें। यह समय की मांग है और रणनीति का तकाजा भी। पार्टी ने पहले भी टीएमसी के कई मजबूत नेताओं को अपनी ओर मिलाया था जिसमें मुकुल राय, अर्जुन सिंह जैसे मजबूत नेता शामिल रहे हैं। मुकुल राय ने तो यह भी दावा किया था कि विधान सभा चुनाव के पहले टीएमसी के 107 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन अभी तक सिर्फ 3 ही विधायक पार्टी छोड़कर आए हैं। इसके अलावा 56 पार्षदों ने भी पार्टी छोड़ दी है जिससे संगठनात्मक तौर पर टीएमसी को धक्का लगा है। आने वाले समय में टीएमसी के कई पदाधिकारी पार्टी छोड़ देंगे इस बात की पूरी संभावना है क्योंकि ममता बनर्जी की किसी की नहीं सुनने की आदत से वे परेशान हैं। ममता बनर्जी पार्टी को कसकर रखती हैं और पदाधिकारियों को जरा भी भाव नहीं देतीं हैं। दूसरी ओर पार्टी के दबंग कार्यकर्ताओं को खुली छूट है। पूरे बंगाल में हजारों

ममता बनर्जी ने मुस्लिम खासकर लाखों बांग्लादेशियों को राज्य में न केवल पनाह दिया बल्कि तमाम सुविधाएं भी दिलवाई। नतीजा यह हुआ कि वे उनके पक्के वोटर बन गए। उनकी इस तुष्टिकरण की नीति से हिन्दुओं को काफी नाराजगी रही और वे भाजपा की ओर मुखातिब हुए।

स्पोर्ट्स क्लब हैं जो सड़कों के किनारे मुहल्लों में हैं। इन्हें हर महीने खेल भत्ता मिलता है। लेकिन यहां कैरम बोर्ड के अलावा और कोई खेल नहीं होता। ये क्लब दरअसल पार्टी के दबंग कार्यकर्ताओं के अड्डे हैं जहां पार्टी की गतिविधियां खासकर वोटरों को डराने का काम होता है। ये क्लब पार्टी के लिए बहुत बड़ा आधार हैं और इनसे ही वह उन वोटरों खासकर वृद्ध लोगों पर नियंत्रण रखती है जो टीएमसी को वोट नहीं देना चाहते हैं।

सिर्फ बीजेपी ही नहीं, ममता के हैं और भी शत्रु

ममता बनर्जी के सामने सिर्फ बीजेपी की चुनौती नहीं है। उसे एक बड़ी चुनौती है सीपीएम की जो लगातार 34 साल तक साल बंगाल की सत्ता पर काबिज रही है। यह पार्टी अभी भी काफी मजबूत है और विधान सभा चुनाव में टीएमसी को कड़ी टक्कर दे सकती है। गांवों में अभी भी पार्टी के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता मौजूद हैं जो जरूरत पड़ने पर दबंगई दिखा सकते हैं। सीपीएम के सपोर्टर बड़े पैमाने में मुस्लिम वोटर थे जो बाद में टीएमसी में चले गए। कम्युनिस्टों को उखाड़कर ही ममता बनर्जी बड़े लुभावने वादों के साथ सत्ता में आईं लेकिन बाद में वे साम्प्रदायिक राजनीति करने लगीं। उन्होंने मुस्लिम खासकर लाखों बांग्लादेशियों को राज्य में न केवल पनाह दिया बल्कि तमाम सुविधाएं भी दिलवाईं जिसका नतीजा यह हुआ कि वे उनके पक्के वोटर बन गए। उनकी इस तुष्टिकरण की नीति से हिन्दुओं को काफी नाराजगी रही और वे भारतीय जनता पार्टी की ओर मुखातिब हुए। मुसलमानों का बंगाल के कई जिलों में बहुमत है और एक जिले में तो मुस्लिम आबादी 52 प्रतिशत से भी ज्यादा है।

कांग्रेस के सामने अस्तित्व का संकट

अपनी अंदरूनी खींचतान से परेशान कांग्रेस आगामी चुनाव में क्या कर पाएगी, यह देखना बाकी है। पार्टी का केन्द्रिय नेतृत्व हिला पड़ा है और राहुल गांधी के पास कोई समाधान नहीं है।

बंगाल के चुनाव के लिए पार्टी के पास कोई प्लान दिख नहीं रहा है, हालांकि अधीर रंजन वहां से ही सांसद हैं। कांग्रेस ने 1977 में यहां सत्ता गंवा दी थी और उसके बाद से वह यहां हाशिये पर है। आज उसके पास सिद्धार्थ शंकर रे जैसा कोई नेता नहीं है।

प्रशांत किशोर का प्लान

चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी ममता बनर्जी को सलाह दे रहे हैं। सच तो यह है कि उनकी ही सलाह पर ही ममता बनर्जी ने हिन्दुओं को खुश करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें दुर्गा पूजा समितियों को 50-50 हजार की नकद राशि देना भी शामिल है। इसके अलावा प्रशांत किशोर कई और तरह की रणनीति बना रहे हैं। दरअसल प्रशांत किशोर को लाने के पीछे ममता बनर्जी की यह रणनीति है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में 2014 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी काम कैसे करती है और उसकी कमजोरियां क्या हैं।

ममता बनर्जी के सामने सिर्फ बीजेपी की चुनौती नहीं है। उसे एक बड़ी चुनौती है सीपीएम की जो लगातार 34 साल तक साल बंगाल की सत्ता पर काबिज रही है।

अब बिगुल बज चुका है। कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियां रणभूमि में जाने की तैयारी में हैं। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है जबकि तृणमूल भी कम नहीं है और अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए ममता बनर्जी किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। उनके पास पूरा प्रशासन है और पूरी पुलिस व्यवस्था। आने वाले महीनों में स्थिति साफ होने लगेगी लेकिन यह तय है कि एक बहुत संघर्षपूर्ण चुनाव की पटकथा लिखी जा रही है जिसमें हिंसा भी जमकर होगी।

“ प्रशांत किशोर को लाने के पीछे ममता बनर्जी की यह रणनीति है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में 2014 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्हें अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी काम कैसे करती है और उसकी कमजोरियां क्या हैं।

सहकारिता में हुआ उलटफेर, प्रधानमंत्री के करीबी दिलीप संघानी बने एनसीयूआई के नए अध्यक्ष

आलोक कुमार

देश के सहकारिताओं की सर्वोच्च संस्था नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (एनसीयूआई) यानीभारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की कमान अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पुराने विश्वस्त दिलीप संघानी के हाथों में आ गई है। यह सहकारिता आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ की अनुषांगी इकाई सहकार भारती और भारतीय जनता पार्टी बीते छह सालों से इस पद पर अपने विश्वस्त को लाने के इंतजार में थी।गुजरात के वरिष्ठ सहकारी नेता दिलीप संघानी राज्य में दो बार कैबिनेट मंत्री, तीन बार विधायक,चार बार लोकसभा सदस्य और अमरेली जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष हैं। संघानी के महत्व को इस लिहाज से भी समझा जा सकता है कि गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से पहले 1995 से 2000 तक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिल्ली का आवासीय पता तत्कालीन सांसद दिलीप भाई संघानी का सरकारी आवास 7, हरिशचंद्र माथुर लेन ही हुआ करता था।

राष्ट्रीय सहकारी संघ के निर्वाचित निदेशकों ने सर्वसम्मति से संघानी को नया अध्यक्ष चुन लिया है। वह समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के निवर्तमान सदस्य डॉ चंद्रपाल सिंह यादव की जगह लेंगे। बीते दस साल से एनसीयूआई के अध्यक्ष रहे डॉ. यादव राजनीति में मुलायम सिंह यादव परिवार के विश्वस्त और कृषक भारती सहकारी फर्टिलाइजर लिमिटेड (कृभको) के अध्यक्ष हैं।

सहकारिताओं की शीर्ष संस्था के निदेशकमंडल की चुनाव में इसबार भी बहुतायत में गैरभाजपा नेता जीतने मेंसफल रहे। लेकिन होशियारी से संघानी एनसीयूआई के अध्यक्ष की कुर्सी पर हासिल करने में सफल रहे। इस सफलता के बावजूद संघानी को समाजवादी,कांग्रेस व राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक

पृष्ठभूमि के बहुतायत वाले निदेशकमंडल के साथ ही फिलहाल काम करना होगा। हालांकि राजनीतिक प्रतिबद्धता को छिपाने की कोशिश में अक्सर सहकारी नेता यह जुमला गढते रहे हैं कि सहकारी उद्यमिताओं का राजनीतिक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं रहा है।

गौरतलब है कि वर्षों से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के जब्त में रहे सहकारी आंदोलन को अपने असर में लेने के लिएभारतीय जनता पार्टी को आज भी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र के सहकारी आंदोलन में शरद पवार का जलबा बरकरार है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को सहकारी संस्थाओं से उतारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बिहार में लालू राज के खात्मे के पंद्रह साल बाद भी प्रदेश के सहकारी आंदोलन पर उनके विश्ववस्तों का कब्जा कायम है। राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद सदस्य डॉ. सुनील कुमार सिंह बिस्कोमान के अध्यक्ष हैं। वह एकबार फिर एनसीयूआई के निदेशक निर्वाचित होने में सफल रहे, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे स्वर्गीय तपेश्वर सिंह के पौत्र विकास सिंह को इसबार फिर कॉप्स के जरिए एनसीयूआई का निदेशक बना लिया गया।

दिल्ली की सियासत से कांग्रेस रुखसत हुए सात साल बीत गए,मगर कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के विश्वस्त रहे पूर्व विधायक बिजेन्दर सिंह का सहकारिता में जलबा बरकरार है। वह न सिर्फ राष्ट्रीय नेफेड समेत कई राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष हैं बल्कि एकबार फिर एनसीयूआई के उपाध्यक्ष बनने में सफल रहे। जबकि कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले गुजरात के सहकारी नेता जीएच अमीन को इसबार एनसीयूआई के उपाध्यक्ष का पद गंवाना पड़ा। इसी तरह लेबर कोऑपरेटिव संघों से आने वाले एनसीयूआई के निदेशक के लिए हंगामेदार चुनाव हुआ। उसमें बिजेन्दर सिंह के करीबी सदाशिवन नायर ने भाजपा नेता अशोक डबास को महज एक वोट के अंतर से चुनाव हरा दिया। एनसीयूआई के 18 में 16 निदेशकों को बिना किसी चुनाव के आम सहमति से चुन लिया गया।आम सहमति से जीतने वालों में ज्यादातर गैर भाजपा पृष्ठभूमि वाले सहकारी नेता हैं। सरकारी कोऑप्स के जरिए नए निदेशक बनने सफल रहे मध्यप्रदेश के भाजपा नेता अरुण तोमर कहते हैं कि यह संघ समर्थक विचारधारा वालों को सहकारिता में असरदार पद दाखिल होने की अच्छी पहल है। इससे आने वाले दिनों में सहकारिता की मुसीबतों का तेजी से हल होगा।

गौरतलब है कि सहकारी संघ में गैरभाजपा नेताओं की गहरी पैठ की वजह से एनसीयूआई को हाल के वर्षों में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। एनसीयूआई से शिक्षण व प्रशिक्षण की देखरेख करने वाली विभागीय इकाई एनसीसीटी को भिन्न संस्था के तौर पर रजिस्टर्ड करवा दिया गया। उसके खिलाफ एनसीयूआई को अदालत का रुख करना पड़ा। मामला दिल्ली उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। सरकार से सहकारी संघों की सर्वोच्च संस्था एनसीयूआई के तनातनी का असर सहकारिता से जुड़ी अन्य गतिविधियों पर पड़ता रहा है। इसकी वजह से सहकारिता को मौलिक अधिकार में शामिल करने वाली संविधान संशोधन विधेयक को लागू करवाने का काम बीते आठ वर्षों से रुका पड़ा है। इसको चुनौती देने वाली याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अब भाजपा के वरिष्ठ नेता दिलीप संघानी के एनसीयूआई के अध्यक्ष बन जाने से भाजपा समर्थकों में खुशी की लहर है। वहीं सहकारी आंदोलन से केंद्र सरकार की तनातनी और अन्य कई व्यवधानों के खत्म होने की उम्मीद बढ गई है। अगले पांच सालों के लिए एनसीयूआई का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले गुजरात के दिग्गज कोऑपरेटर दिलीप सिंघानी 1995 से सहकारी आंदोलन में सक्रिय हैं। फिलहाल वह इंडियन पोटाश लिमिटेड के निदेशक, नैफस्कॉब के अध्यक्ष, नेफेड और इफ्को के उपाध्यक्ष हैं।

The Next Generation Wall Putty

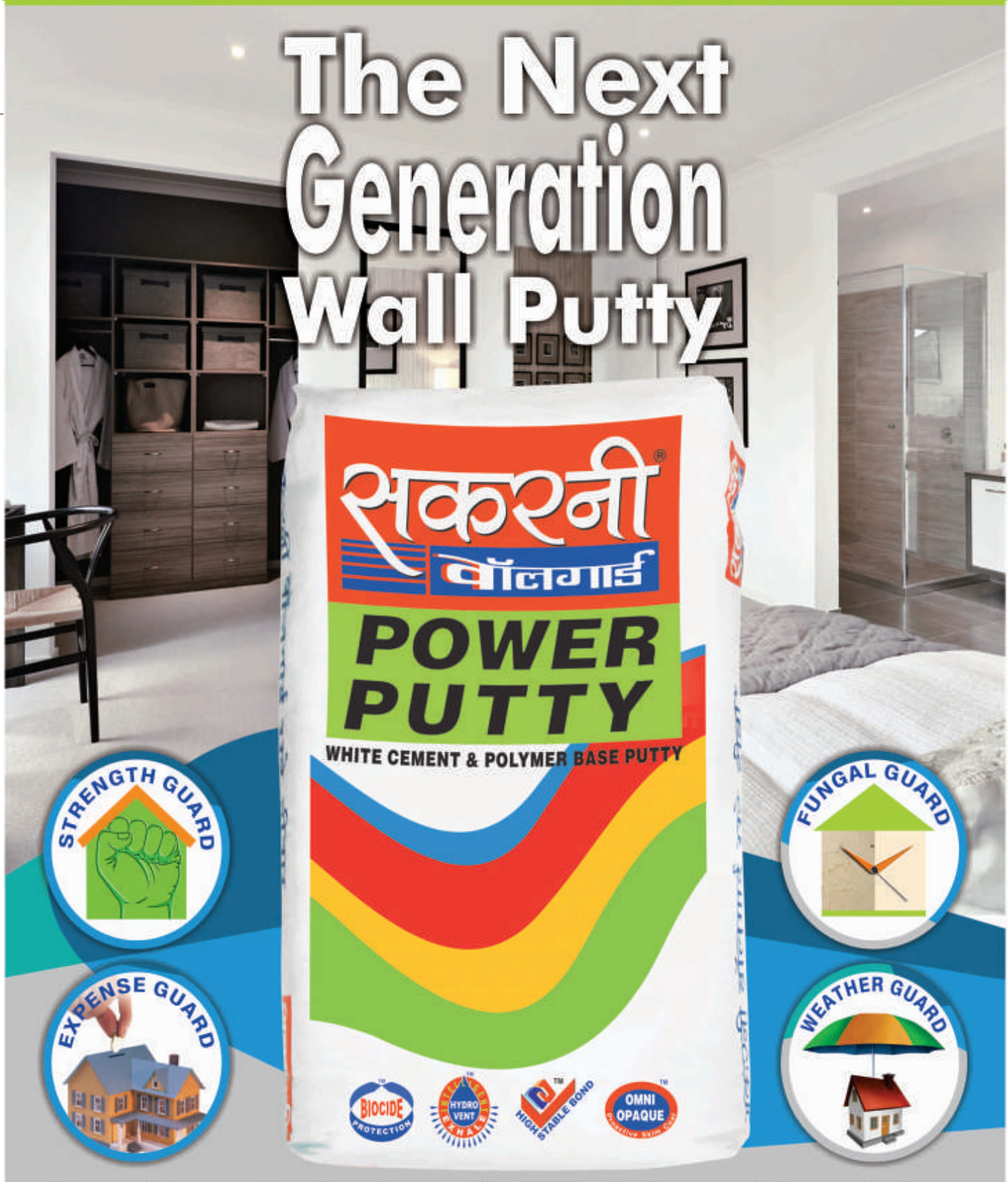

Complete protection for walls. Extremely good for coloring.

SAKARNI PLASTER INDIA PVT. LTD.
Off: 446/337, Srinagar Extn., Shakur Basti, Delhi-110034, Ph.: 27181083, 27182922, Mobile: 9810177365
Work: G138, Industrial Area Phase II Nimrana, District Alwar, Rajasthan, E-mail: ashokgupta18032@gmail.com,
Customer Care: +91 9810018032

यूपी में भी हाथ मिला सकते हैं माया-ओवैसी

अजय कुमार

बिहार विधान सभा चुनाव नतीजों ने उत्तर प्रदेश की सियासत में भी हलचल तेज कर दी है। खासकर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटरों के सबसे बड़े 'ठेकेदार' समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की नींद उड़ी हुई है। मुस्लिम वोटों के लिए हाथ-पैर मार रही कांग्रेस की उम्मीदों को भी ग्रहण लगता दिख रहा है। चिंता का कारण बिहार विधान सभा चुनाव में पांच सीटें जीत कर सबको चौका देने वाली ओवैसी की 'ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन' (एआईएमआईएम) पार्टी बनी हुई है। बिहार विधान सभा चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन काफी चैकाने वाला रहा, जिस तरह से मुस्लिम वोटरों ने असुद्दीन ओवैसी की पार्टी पर विश्वास जताया उससे एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता तेजस्वी यादव का सत्ता हासिल करने का सपना चकनाचूर हो गया तो दूसरी तरफ बिहार के नतीजों ने उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी का पंख फेलाने का मौका दे दिया। ओवैसी ने बिहार में भले ही पांच सीटें जीती हों,लेकिन उसका असर अभी से यूपी में महसूस किया जाने लगा है। ओवैसी की पार्टी बिहार की जीत का जश्न यूपी में भी मना रही है।

> **इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में मिलकर विधान सभा चुनाव लड़ने वाली मायावती-ओवैसी की पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में भी साथ-साथ नजर आएं। ओवैसी की पार्टी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र की पांच सीटों में जीत दर्ज कर अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया है।**

बात इससे आगे की कि जाए तो इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में मिलकर विधान सभा चुनाव लड़ने वाली मायावती-ओवैसी की पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में भी साथ-साथ नजर आएं। ओवैसी की पार्टी ने बिहार के सीमांचल क्षेत्र की पांच सीटों में जीत दर्ज कर अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 1.24 फीसदी वोट एआईएमआईएम को मिले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा था और उसे सिर्फ 0.5 फीसदी मत ही हासिल हो पाया था। ओवैसी ने सीमांचल के अलावा कोसी और मिथिलांचल में भी अपना प्रभाव छोड़ा है।

ओवैसी की पार्टी आरजेडी के माय (मुस्लिम-यादव) समीकरण में भी बड़ी सेंधमारी की हैं। सीमांचल की राजनीति को जानने वाले वाले कहते हैं कि इस चुनाव में पहली बार ओवैसी की पार्टी ने अमौर, वायसी, जोकीहाट, बहादुरगंज और कोचाधामन सीट पर जीत हासिल की है। इससे पहले उपचुनाव में पार्टी ने किशनगंज की सीट जीतकर बिहार में अपना खाता खोला था। ऐसा नहीं कि मुस्लिम आबादी बहुल इस इलाके में एआईएमआईएम पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन अन्य चुनावों में इसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली थी। इस चुनाव में पार्टी ने भले ही पांच सीटें जीती हैं, लेकिन शेष जगहों पर इसने महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए परेशानी बढ़ा दी। बिहार में ओवैसी की पाटी 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, इनमें से ज्यादातर पर सात नवंबर को मतदान हुआ था।

बिहार में ओवैसी की पार्टी ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट का हिस्सा थी,जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी शामिल थे। इसीलिए यूपी में भी ओवैसी-माया के हाथ मिलाने की चर्चा हो रही है। यहां एक और कारण की चर्चा भी जरूरी है, जब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती सपा प्रमुख अखिलेश से बुरी तरह से नाराज हो गईं थीं।

नाराजगी का आलम यह था कि पिछले दिनों उन्होंने यहां तक कह दिया था कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी बीजेपी का भी समर्थन कर सकती है। हालांकि बाद में मायावती अपने बयान से पलट गई थीं।

दरअसल,बीएसपी के कुछ विधायकों के समाजवादी पार्टी से मिल जाने के बाद मायावती ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधान परिषद चुनाव के संदर्भ में हाल में अपना एक वीडियो बयान जारी किया था,जिसमें उनका कहना था,'जब यहां एमएलसी के चुनाव होंगे तो सपा के दूसरे उम्मीदवार को हराने के लिए बसपा अपनी पूरी

ताकत लगा देगी और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके (सपा) उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी या अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को अपना वोट क्यों न देना पड़ जाए, तो भी देंगे।' अगर ओवैसी-माया साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखना मुश्किल हो जाएगा।

यूपी में करीब 18 प्रतिशत आबादी मुस्लिमों और 23 प्रतिशत आबादी दलितों की है। अगर दलित और मुस्लिम एक झंडे के नीचे आ गए तो भाजपा-समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबका खेल बिगड़ सकता है। क्योंकि वोट कटवा कही जाने एआईएमआईएम ने बिहार विधानसभा चुनाव में पांच सीटों पर जीत का परचम लहराने के बाद यह साबित कर दिया है कि अब उसकी पहचान सिर्फ वोटकटवा पार्टी तक सीमिति नहीं रखी जाए। वैसे, करीब 18 प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाले यूपी पर ओवैसी की नजर काफी पहले से है, लेकिन वह यहां अभी तक जड़े नहीं जमा पाई है। बिहार में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर शानदार प्रदर्शन के बाद ओवैसी यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ाने जा रही हैं।

बात समाजवादी पार्टी के साथ लम्बे समय से साथ खड़े मुस्लिम वोटरों की कि जाए तो पिछले कुछ वर्षो

अगर ओवैसी-माया साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक को साधे रखना मुश्किल हो जाएगा। यूपी में करीब 18 प्रतिशत आबादी मुस्लिमों और 23 प्रतिशत आबादी दलितों की है। अगर दलित और मुस्लिम एक झंडे के नीचे आ गए तो भाजपा-समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सबका खेल बिगड़ सकता है।

में मुस्लिम वोटरों का समाजवादी पार्टी के प्रति विश्वास कई बार डगमगाया है। मुस्लिम वोटरों को अखिलेश में वह बात नहीं दिखती है जो मुलायम सिंह में थी। मुलायम सिंह यादव जब तक सक्रिय रहे, वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं से मुलाकात का नियमित सिलसिला बनाए रखते थे, यह सिलसिला कुछ समय तक अखिलेश राज में भी चला, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा को करारी हार मिलने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी सियासत का रूख काफी हद तक मोड लिया था। वह मुस्लिम वोट हासिल करने के लिए हिन्दुओं की नाराजगी मोल लेने से बचने लगे थे,लेकिन बिहार विधान सभा चुनाव के नतीजों के बाद काफी कुछ बदल गया है। इसीलिए ओवैसी यूपी में अपनी ताकत दिखाना शुरू करें इससे पहले ही समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को रिझाने के लिए मैदान में कूदने की तैयारी कर रही है।

इस क्रम में अखिलेश यादव सबसे पहले जेल में बंद आजम खान की रिहाई के लिए आंदोलन शुरू कर सकते है।

अखिलेश अपनी पार्टी और स्वयं को आजम के साथ खड़ा दिखाकर मुसलमानों में यह संदेश देने की कोशिश करेगी कि वह ही मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी है।

बहुत कठिन है डगर कांग्रेस की

किशोर कुमार मालवीय

एक राजा था जो बहुत ही आशावादी था। वह असम्भव को सम्भव बनाने में यकीन रखता था। ये अलग बात है कि उनके प्रयोग व्यवहारिक नहीं होते थे। एक दिन राजा ने घोषणा कर दी कि वह अपने राजमहल के प्रांगण में एक हाथी को आसमान में उड़ाएगा। ऐसा करने से पहले राजा ने अपने सभी मंत्रियों और दरबारियों को अपनी इच्छा बताई कि वह हाथी उड़ाना चाहते हैं। सभी मंत्री और दरबारियों ने एकमत से कहा कि अगर राजा चाहते हैं तो हाथी जरुर उड़ेगा। पर राजपुरोहित ने कहा कि हाथी उड़ ही नही सकता। उड़ने के लिए पंख होना चाहिए और उड़ने से पहले तेज दौड़ने की कला आनी चाहिए। राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी। दरबारियों ने भी इसे बादशाह की बेअदबी माना। राजपुरोहित को राजद्रोही मानते हुए देशनिकाला दे दिया गया। फिर हाथी उड़ाने की योजना को अमल में लाने के लिए कार्यक्रम तय कर दिया गया। राज्य में मुनादी करा दी गई। तय दिन और समय पर प्रजा राजमहल के प्रांगण में इस चमत्कार को देखने इकट्ठा हो गई। लेकिन हाथी नहीं उड़ा।

> **पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी दुविधा में है। जो जनता को पसंद है कांग्रेस उसे नापसंद करती है। मसलन, कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले का देशभर ने समर्थन किया लेकिन कांग्रेस विरोध करने वालों के साथ खड़ी हो गई। कश्मीरी नेताओं के गुप्कर गैंग के साथ खड़ी हो गई। लव जेहाद पर अलग अलग राज्यों में बन रहे कानून को बहुसंख्यकों का समर्थन प्राप्त है लेकिन आदत से मजबूर कांग्रेस ने इसका भी विरोध कर दिया।**

ये काल्पनिक कथा है जिसकी रचना मैने अभी-अभी की है। इसकी प्रेरणा मुझे कांग्रेस से मिली है। पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस में भी हाथी उड़ाने की कोशिश हो रही है। काल्पनिक कथा के राजा और कांग्रेस आलाकमान में एक बुनियादी फर्क है। राजा ने नाकाम कोशिश के बाद हाथी उड़ाने का फैसला छोड़ दिया लेकिन कांग्रेस में हाथी उड़ाने की कोशिश आज भी लगातार जारी है, तमाम नाकाम कोशिशों के बावजूद। हाथी ने कह दिया है कि वह न तो उड़ सकता है और न ही उड़ना चाहता है। पर राजा मानने को तैयार नहीं।

बिहार चुनाव में भयानक पराजय के बाद कांग्रेस में एक बार फिर बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बगावत करने वाले नेताओं में ज्यादातर वही लोग हैं जो पार्टी में ग्रुप-23 के नाम से जाने जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुखर हैं कपिल सिबल और गुलाम नबी आजाद। इस ग्रुप का गठन तब हुआ था जब राजस्थान में उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दिया था। तब सचिन ने भी गहलोत के काम करने के तरीकों और आलाकमान की उदासीनता का मामला उठाया था। लेकिन पार्टी ने उनकी मांगो को तवज्जो देने के बजाय कुछ नेता उन्हें भारतीय जनता पार्टी का शुभचिंतक बताने लगे। कईयों ने तो उनके भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। तभी कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष (कार्यकारी) सोनिया गांधी को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग के साथ साथ संगठन में व्यापक फेरबदल की मांग कर डाली थी। इन मांगों में अध्यक्ष पद का चुनाव भी शामिल था। उस पत्र में 23 लोगों के दस्तखत थे।मांग तो नहीं मानी गई, अलबत्ता ग्रुप के कुछ नेताओं को दरकिनार करने का काम जरुर शुरू हो गया।

कांग्रेस की ये पुरानी बीमारी है जो हर पराजय के बाद सतह पर आ जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद बागियों को फिर से मौका मिल गया। व्यक्तिगत निष्ठाओं पर टिकी इस पार्टी में जब भी विरोधी आवाज उठती है, उसे गांधी परिवार के वफादार एकजुट होकर दबा देते हैं। कांग्रेस में शायद ही कोई हो जो संगठन के प्रति वफादार हो। पहले तो वफादारी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के प्रति होती थी लेकिन अब वफादारी भी बंट गई है। कोई सोनिया गांधी के प्रति वफादार है तो कोई राहुल के प्रति। कई नेताओं की वफादारी प्रियंका गांधी वडरा की ओर शिफ्ट हो गई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह व्यक्ति परिक्रमा पर चल रही है।

कांग्रेस की असली मुसीबत बाहरी नहीं अंदरुनी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्हें काफी मनाया गया कि वह इस्तीफा वापस ले लें लेकिन वह नहीं माने। फिर उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाने की कोशिश

हुई लेकिन वह तैयार नहीं हुए। राहुल ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को सौंप देना चाहिए। लेकिन पार्टी के नेताओं की परिवार भक्ति और व्यक्तिगत वफादारी ने ऐसा नहीं होने दिया। ऊपर से सोनिया गांधी का पुत्रमोह। वह आज भी राहुल के अध्यक्ष बनने की राह देख रही है कि आज नहीं तो कल राहुल बाबा मान जाएंगे। इसलिए अंतरिम रुप से सोनिया ने ही अध्यक्ष की कुर्सी सम्भाल ली। वैसे, सारे फैसले राहुल और उनकी टाम ही ले रही है। लेकिन ये वैकल्पिक और अंतरिम व्यवस्था कब तक चलेगी। ये सवाल कुछ नेताओं के मन में समय समय पर उठते रहते हैं जो अध्यक्ष के चुनाव की मांग के रुप में सामने आते हैं और जिन्हें कांग्रेस के वफादार नेता बगावत का नाम देते हैं। पिछले कुछ चुनावों- उप चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन ने ऐसी बगावत को हवा दी है।

एक सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा अगर कोई और अध्यक्ष बनता है तो पार्टी टूटने का खतरा है। इतिहास गवाह है कि गैर गांधी अध्यक्ष के काल में पार्टी में अनुशासन धराशायी हो गई और विभाजन तक कि स्थिति आ गई। सीताराम केसरी से लेकर पी. वी. नरसिंह राव तक पार्टी में स्वीकार्य नहीं हुए। पार्टी में कई नेता खुद को अध्यक्ष के दावेदार मानते हैं और समय समय पर उनकी महत्वाकांक्षाएं भी जाग जाती हैं। लेकिन कपिल सिबल, पी. चिदम्बरम और उनके पुत्र कार्ती चिदम्बरम अगर अचानक पार्टी में आत्मचिंतन की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि वे अध्यक्ष बनना चाहते हैं। बिहार चुनाव में जिस तरह कांग्रेस ने खुद को एक क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के समक्ष समर्पण कर दिया था और जिस तरह राष्ट्रीय जनता दल ने मुश्किल सीटें कांग्रेस को दी उससे पार्टी में बहुत से लोग आहत हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस द्वारा जीती सीटें भी आरजेडी या वामपंथी दलों को दे दी गई। पार्टी ने अयोग्य लोगों को टिकट दिए और सारे फैसले दिल्ली से थोपे गए। दरअसल कांग्रेस बिहार में अति आत्मविश्वास का शिकार हो गई थी। चिदम्बरम-सिबल की चिंता है कि आने वाले चुनाव में इन गलतियों की पुनरावृति न हो क्योंकि बंगाल और तमिलनाडू में

असली समस्या वे नहीं हैं जो कांग्रेस में विरोध की आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति और 10 से 5 बजे तक काम करने की आदत उसे हार की ओर ले जाती है। भाजपा ने जहां बंगाल और तमिलनाडू के लिए अभी से काम करना शुरू कर दिया है वहीं कांग्रेस में इन राज्यों की चर्चा तक नहीं हो रही है। ऊपर से गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के पांच सितारा कल्चर की बात कर दुखती रग पर हाथ रख दिया।

जल्द चुनाव होने हैं जहां क्षेत्रीय दलों से गठबंधन और सीटों का बंटवारा होना है।

लेकिन असली समस्या वे नहीं हैं जो कांग्रेस में विरोध की आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस की रणनीति और 10 से 5 बजे तक काम करने की आदत उसे हार की ओर ले जाती है। भाजपा ने जहां बंगाल और तमिलनाडू के लिए अभी से काम करना शुरू कर दिया है वहीं कांग्रेस में इन राज्यों की चर्चा तक नहीं हो रही है। ऊपर से गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के पांच सितारा कल्चर की बात कर दुखती रग पर हाथ रख दिया।

कांग्रेस की सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि उनके पास ऐसे नेताओं की कमी है जिनके जनता सा सीधे सम्बन्ध हों। कांग्रेस की सबसे बड़ी नीति निर्धारण समिति कांग्रेस कार्य समिति में भी ज्यादातर लोग वही हैं जो चुनाव जीतने-जीताने की क्षमता नहीं रखते। आलाकमान से बेहतर सम्बन्धों के चलते कार्य समिति या राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। ढंग के वक्ता तक नहीं हैं जो पार्टी प्रवक्ता की भूमिका निभा सके। प्रियंका चतुर्वेदी, ज्योतिर्रादित्य सिंधिया और खुशबू सुंदर पार्टी की उदासीनता से दुखी होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। लेकिन इन सबसे भी पार्टी को कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि काबिल लोगों को कुछ लोग जानबूझकर नहीं रोकते, असुरक्षा की भावना की वजह से।

पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर भी दुविधा में है। जो जनता को पसंद है कांग्रेस उसे नापसंद करती है। मसलन, कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले का देशभर ने समर्थन किया लेकिन कांग्रेस विरोध करने वालों के साथ खड़ी हो गई। कश्मीरी नेताओं के गुप्कर गैंग के साथ खड़ी हो गई। लव जेहाद पर अलग अलग राज्यों में बन रहे कानून को बहुसंख्यकों का समर्थन प्राप्त है लेकिन आदत से मजबूर कांग्रेस ने इसका भी विरोध कर दिया। सिर्फ तुष्टीकरण की वजह से।

मुसलमानों को खुश करने के चक्कर में कांग्रेस ने खुद को हिन्दू विरोधी पार्टी बना दिया। सरकार के हर फैसले का विरोध करने से पहले कांग्रेस ये नहीं सोचती कि इसके परिणाम क्या होंगे। केवल विरोध के लिए विरोध करना कांग्रेस के लिए घातक साबित हो रहा है। इसके बावजूद मुसलमान उसके साथ नहीं है। भारत के मुसलमान कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी या ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर ज्यादा भरोसा करते हैं। यानि जिनके लिए आपने हिन्दुओं को बैरी बना लिया, उन्होंने भी आपका साथ नहीं दिया। बिहार का हाल का चुनाव इसका ताजा उदाहरण है।

पार्टी में संकट के समय संकटमोचक की भूमिका निभाने वाले दिग्गज नेता अहमद पटेल की मृत्यु ने तो पार्टी को और संकट में डाल दिया है। एक वही थे जो महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर सोनिया गांधी को मशविरा दिया करते थो और उनकी सुनी भी जाती थी। लेकिन अब पार्टी में सरफुटव्वल की नौबत आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं।

भाजपा के 'कांग्रेस मुक्त भारत' का सपना खुद कांग्रेस पूरा करेगी अगर पार्टी में 'सारे घर के बदल डालो' वाला सुधार नहीं हुआ तो। इसके लिए कठोर इच्छाशक्ति की और परिवार मोह से ऊपर उठकर कड़े कदम उठाने की जरुरत है।

चुनौतियों का पहाड़, कैसे टिकेगें नीतीश कुमार

सुभाष चन्द्र

> सात की संख्या बेशक नीतीश कुमार के लिए लकी साबित होती हो, लेकिन सातवीं पार मुख्यमंत्री की पारी उनके लिए आसान नहीं दिखती है। यह पहली बार हुआ है कि वे छोटे भाई की भूमिका में हैं। उनके सखा सुशील मोदी नहीं हैं और विपक्ष के रूप में राजद सशक्त हुआ है। चुनावी मंचों से जो बातें जनता के लिए कहीं, लोग उसे अमलीजामा पहनाने की मांग कर रहे हैं। क्या पहले की तरह राजकाज चला पाएंगे नीतीश कुमार ?

नीतीश कुमार का नाम जब भी लिया जाता है, एक गंभीर और मितभाषी नेता का चेहरा सामने आता है। बीते पन्द्रह वर्षों में 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। उम्र के इस पड़ाव पर मानो स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो चला है। जिसकी झलक विधानसभा के चुनावी मंचों पर साफ दिखी। जानकारों का कहना है कि 7 की संख्या उनके लिए सहायत साबित हुई है, लेकिन इस बार सातवीं पारी की मुश्किलें बढ़ती दिखती हैं। 7 निश्चय, 7 वादे और जब मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया था, तो 7 नंबर बंगले में जाकर रखना, उनके 7 प्रेम को दशार्ता है।

मगर, इस बार पहली बार वे मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा में छोटे भाई की भूमिका में हैं। संख्या बल के कारण। बड़े भाई की भूमिका में भाजपा है। बिहार के संस्कार में बड़ा भाई आदेश देता है, जिसे पूरा करना छोटे भाई का कर्तव्य माना जाता है। क्या इस चरित्र का निर्वाह कर पाएंगे नीतीश कुमार ? विपक्ष के रूप में राजद और नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव अभी से हमलावर हैं, क्या इससे आसानी से पार पा लेगे ? संकटमोचक के रूप में इनके साथ उपमुख्यमंत्री के रूप में सुशील मोदी नहीं हैं। भाजपा ने एक के बदले दो-दो उपमुख्यमंत्री बनवा दिया है। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में भाजपा ने अपने नेता विजय सिन्हा को कमान दे दी है।

बिहार में राजग के एक घटक जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के मुखिया नीतीश कुमार ने हाल में ही जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे तब उन्हें यह गवार्नुभूति अवश्य हुई होगी कि वे देश के किसी राज्य में सर्वाधिक सात बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने का रिकार्ड बनाने जा रहे हैं परंतु नीतिश कुमार को यह अनुमान निश्चित रूप से नहीं रहा होगा कि शीघ्र ही उनकी सरकार के साथ प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः कहावत भी चरितार्थ होने जा रही है। सत्ता की राजनीति के चतुर खिलाड़ी नीतिश कुमार ऐसा सोच भी कैसे सकते थे कि उन्हें अपनी सरकार के नवनियुक्त शिक्षा मंत्री को उनके पदभार ग्रहण करने के मात्र दो घंटे के अंदर ही भ्रष्टाचार के कथित आरोपों के कारण मंत्रिपद से इस्तीफा देने का निर्देश देने के लिए विवश होना पड़ेगा। यह भी शायद अपने आप में एक रिकार्ड है कि जदयू के नवनिर्वाचित विधायक डॉ मेवालाल चौधरी ने 16 नवंबर को मंत्रिपद की शपथ ली,19 नवंबर को राज्य के शिक्षा मंत्री का पदभार ग्रहण किया और मात्र एक घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने उन्हें अपने कार्यालय में बुलाकर उनसे दो दो टूक शब्दों में तत्काल मंत्रिपद छोड़ने के लिए कह दिया। दरअसल, मेवालाल चौधरी पर पहले से भ्रष्टाचार के आरोप थे और उन्होंने इसके बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शपथ लिया। उनके शपथ लेते ही तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष हमलावर हो गया और घड़ी दर घड़ी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछना शुरू कर दिया। विपक्ष की सक्रियता देख बैकफुट पर आए नीतीश कुमार ने संभवतः दबाव बनाकर इस्तीफा मांगा होगा।

मेवालाल चौधरी के इस्तीफे की खबर आने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा- 'मा. मुख्यमंत्री जी, जनादेश के माध्यम से बिहार ने हमें एक आदेश दिया है कि आपकी भ्रष्ट नीति, नीयत और नियम के खिलाफ आपको आगाह करते रहें। महज एक इस्तीफे से बात नहीं बनेगी। अभी तो 19 लाख नौकरी,संविदा और समान काम-समान वेतन जैसे अनेकों जन सरोकार के मुद्दों पर मिलेंगे। जय बिहार,जय हिन्द।'

नीतिश कुमार ने भ्रष्टाचार के आरोपी एक मंत्री को तत्काल

अपनी सरकार से हटाकर एक रिकार्ड बनाया हो परंतु इस फैसले के लिए वे किसी तारीफ के हकदार नहीं हैं बल्कि उन्हें तो अब इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि क्या मेवालाल चौधरी को अपनी सरकार में शामिल करते समय यह जानकारी नहीं थी कि अतीत में कुलपति के रूप में उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा चुके हैं जिनसे वे अभी तक बरी नहीं हुए हैं। नीतिश कुमार निसंदेह अब असहज स्थिति का सामना कर रहे होंगे परंतु मुख्यमंत्री के रूप में उनके इस कार्यकाल की शुरूआत जिस तरह हुई है उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि उनका यह कार्य काल निरापद नहीं होगा।

इस पूरे प्रकरण ने मुख्यमंत्री नीतिश कुमार को बचाव की मुद्रा में ला दिया है। राजद के नेता तेजस्वी यादव नीतिश सरकार से शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी की विदाई को अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं तो यह कतई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिर यह मनचाहा अवसर तो उन्हें नीतिश कुमार ने ही उपलब्ध कराया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि नीतिश कुमार इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। शायद मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की कटु स्मृतियां अभी तक उनके मस्तिष्क में ताजा हैं जब उनकी सरकार में संबंधित विभाग की मंत्री मंजू वर्मा का वे काफी समय तक बचाव करते रहे परंतु अंत में उन्हें मंजू वर्मा को अपनी सरकार से हटाने पर विवश होना पड़ा लेकिन तब तक

सरकार की काफी किरकिरी हो चुकी थी। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि नीतिश कुमार के लिए यह कार्य काल निरापद न होने के संकेत अभी से मिलने लगे हैं। विधानसभा में जदयू से भाजपा की सीटें ज्यादा होने के बावजूद मुख्यमंत्री पद भरे ही उन्हें मिल गया हो परंतु भाजपा को दो उपमुख्यमंत्री पद और विधानसभा सभा अध्यक्ष पद देने के लिए उन्हें जिस तरह विवश होना पड़ा है उससे यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि उन्हें इस कार्यकाल में कितने समझौते करना पड़ेंगे।

इस बार कम सीटें हासिल करने की वजह से नीतीश कुमार के लिए सरकार चलाने और खुलकर फैसले लेने की आजादी पहले जैसी नहीं होने वाली है। इसलिए नीतीश कुमार को अपने नियंत्रण में रखकर सरकार चलाने की चुनौतियों का भी सामना करना होगा।इसके अलावा बिहार की सत्ता संभालने के बाद नीतीश पहली बार मजबूत विपक्ष का सामना करेंगे। बता दें कि इससे पहले तक बिहार में विपक्ष काफी कमजोर स्थिति में रहा है। लेकिन इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में है। नीतीश को घेरने के लिए पहली बार विपक्ष में कम से कम 115 विधायक रहेंगे। ना केवल तेजस्वी बल्कि ओवैसी की पार्टी के मुद्दों का सामना करना भी नीतीश के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।इसके अलावा नीतीश के सामने अपनी खोई इमेज को वापस पाने की भी चुनौती है। इस बार चुनाव में उनके खिलाफ लोगों की नाराजगी साफ देखने को मिली। चुनाव के दौरान सत्ताविरोधी लहर साफतौर पर देखने को मिली। लोग नीतीश के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। ऐसे में अब नीतीश कुमार के पास सत्ता संभालने के बाद अपनी खोई हुई सुशासन बाबू की छवि को फिर से मजबूत करने की चुनौती होगी।

नीतीश कुमार पूरी मजबूती और बिना हस्तक्षेप के काम करने वाले सीएम माने जाते रहे हैं। आलोचक उनकी शैली को बिना किसी से विचार किए फैसला लेने वाले सीएम रहने का भी आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन इस बार उनके सामने ऐसी खुली आजादी कतई नहीं होगी। सरकार के अंदर उनकी हिस्सेदारी भी कम होगी। कैबिनेट में बीजेपी के अधिक मंत्री होंगे। इसके अलावा जीतन मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी को भी एक-एक पद मिल सकता है। इस तरह फिर से सीएम बनने वाले नीतीश कुमार को अपने नियंत्रण में रखकर शासन करने की चुनौती रहेगी। याद रखें कि 2015 में जब आरजेडी अधिक सीट लेकर सरकार में हिस्सेदार हुई तो कुछ महीने बाद ही कई मसलों पर वे असहज हो गये थे। अब सवाल है कि उसके आगे भाजपा क्या करेगी? भाजपा अब बिहार में अपना सामाजिक आधार बड़ा करेगी। ध्यान रहे भाजपा कभी भी बिहार की पार्टी नहीं रही है। भारतीय जनसंघ का भी बिहार में बड़ा आधार नहीं था। जब झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था तो बिहार में भाजपा को दक्षिण बिहार यानी मौजूदा झारखंड की पार्टी माना जाता था। उसके जो 40-50 विधायक कभी जीतते थे तो ज्यादातर उसी इलाके से होते थे। तभी जब झारखंड अलग हुआ तो पहली सरकार भाजपा की बनी थी। वह भी नीतीश कुमार की बदौलत ही हुआ था। तब भाजपा नीतीश के साथ मिल कर लड़ी थी और झारखंड में नीतीश की पार्टी के छह विधायकों के समर्थन से उसकी सरकार बनी थी। असल में, बिहार में भाजपा को वैश्यों की पार्टी माना जाता था। जब लालू प्रसाद के उभार के बाद कांग्रेस का पतन हुआ और भूमिहार, ब्राह्मण व राजपूतों ने एक साथ कांग्रेस को छोड़ा तब जाकर भाजपा को थोड़ा वोट आधार मिला। लेकिन वह भी अकेले राजनीति करने के लिए पर्याप्त नहीं था क्योंकि एकीकृत बिहार में सवर्णों की आबादी 12 फीसदी से ज्यादा नहीं थी। तभी भाजपा को हमेशा किसी न किसी कंधे की जरूरत पड़ी। इस काम में नीतीश कुमार का कंधा भाजपा के बहुत काम आया। अब नीतीश के सहारे भाजपा इस मुकाम पर पहुंच गई है और वह नीतीश के बनाए जमीनी आधार और सामाजिक समीकरण के ऊपर नरेंद्र मोदी के चेहरे की मदद से पिछड़ा और अतिपिछड़ा आधार मजबूत कर सके।

वैसे भाजपा की यह राजनीति दोधारी तलवार की तरह है। इसी चुनाव में अगड़ों के बीच यह मैसेज था कि उनके लिए जैसे भाजपा वैसे राजद। इस नैरेटिव का थोड़ा बहुत नुकसान इस बार भाजपा को उठाना पड़ा है। अगर वह पिछड़ों और अतिपिछड़ों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगी तो उसके सवर्ण मतदाता नाराज होंगे। ध्यान रहे विभाजन के बाद बिहार में सवर्ण मतदाताओं की संख्या 17-18 फीसदी तक पहुंच गई। यह एक बड़ी संतुलनकारी ताकत है। अगर इसका रूझान राजद और कांग्रेस की ओर गया तो संतुलन बदल सकता है क्योंकि उनके पास पहले से मुस्लिम-यादव का 30 फीसदी का एक मजबूत वोट आधार है। इस बार इसके ऊपर उसे पांच फीसदी वोट मिले हैं। इसमें अतिपिछड़ी जातियां भी हैं और सवर्ण भी।

नैतिकता की दुहाई देने में कभी पीछे न रहने वाले नीतीश कुमार बिहार विधानसभा चुनाव-2020 के नतीजे आने के बाद से काफी झेंप रहे हैं। वह पिछले दिनों मीडिया से मुखातिब थे। जद(यू) के कुछ पुराने नेता हैं। दो पूर्व राज्यसभा सदस्य भी हैं, वह तो देखना चाहते थे कि नीतीश कुमार चुनाव में 43 सीटें पाने के बाद क्या लाइन लेते हैं? हालांकि एक राज्यसभा सदस्य ने कहा कि नीतीश दिखावे का ढोंग करते हैं। इसका एक उदाहरण पहले जीतन राम मांझी को सीएम बनाना और फिर उन्हें पद से उतारकर दोबारा मुख्यमंत्री बनना था। दूसरा उदाहरण पूरी तरह यू टर्न लेकर महागठबंधन में जाना और उसे छोड़कर एनडीए में लौटना है। सही बात यह है कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद ही नहीं स्वीकारना चाहिए। कभी नीतीश के करीबी रहे सूत्र का कहना है कि लेकिन मुख्यमंत्री का पद ऐसा है कि कोई भी नैतिकता ताक पर रखी जा सकती है।

बिहार जल्द खोज लेगा अपना विकल्प: मनोज झा

राजद के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार चुनाव नतीजों को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, 40 सीटें पाकर कोई कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है। चुनाव में नीतीश को बुरी तरह हार मिली है और उन्हें खुद इस बारे में सोचना चाहिए था। जदयू के मुखिया नीतीश के पास बहुत कम बहुमत है। यहां तक कि राजग और भाजपा को भी मानना चाहिए कि अगर यह बदलाव के लिए जनादेश नहीं होता तो नीतीश की पार्टी सिर्फ 40 सीटें नहीं जीतती। आप (नीतीश) कम बहुमत पर हैं। कम बहुमत वाली सरकार लंबे समय तक नहीं चल सकती है। बिहार अपना विकल्प तलाश लेगा, जो सहज होगा। नए विकल्प में एक सप्ताह, दस दिन या एक महीना लग सकता, लेकिन ऐसा निश्चित रूप से होगा। उन्होंने कहा कि यह हैरान करने वाला है कि भाजपा 74 सीटें जीत गई, जबकि वह बिहार चुनाव में चेहरा भी नहीं थी। उन्हें भी इसकी उम्मीद नहीं रही होगी।

दो कट्टर विचारधाराओं का टकराव

गोविन्द ठाकुर

बिहार विधानसभा चुनाव में असद्दुदीन ओवैसी के उदय और बीजेपी की स्टाईक रेट ने भारतीय लोकतंत्रीय राजनीति को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे आने वाले समय में भारत की लोकतंत्रीय राजनीति दो कट्टर विचारधाराओं के बीच बंटकर रह जाऐगी। हिंदुत्व की राजनीति को इसका इंतजार जमाने से था।

बिहार की राजनीति को लेकर जानकारों की राय अमुमन रहती है कि बिहार की राजनीति देश को समय-समय पर एक नई दिशा देती रही है। इसबार के हुए चुनाव ने भी एक संकेत दे दिया है कि चाहे मुफलिसी जितनी भी हो मगर राजनीति में वे जाति धर्म के झंडे को उठाए रखेंगे। लाख कोशिश करने के बाद भी महागठबंधन और तेजस्वी का भूतकाल ने पीछे नहीं छोड़ा और उनका तमाम लोक लुभावन ऐजेंडे को बिहारियों ने नकार दिया। धर्मनिरपेक्ष की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार ने बीजेपी की ऊंगली पकड़ कर सरकार तो बना ली मगर उनकी पार्टी की नींव हिल गई। अब सवाल उठता है कि इस चुनाव ने इसबार क्या संकेत दिया; तो जबाव यही है कि बिहार ने इसबार दो कट्टर विचारधाराओं को समर्थन देकर भारतीय लोकतंत्रीय राजनीति को चेताया है कि अगर नहीं संभले तो अपनी पतन के तुम खुद जिम्मेदार होगे।

बिहार के सीमांचल में ओवैसी ने पांच सीट जीतकर यह संकेत दे दिया है कि वह वोट-कटवा नहीं है बल्कि उभरते हुए वह विचारधारा है जो देश को दो धाराओं में बांट सकती है। आजादी की लड़ाई के समय भी

> गलत वे हैं जो इस तरह की राजनीति करने वाले को समर्थन देती है और गलत वे पार्टियां भी हैं जो देश की आवाम की नजरों में कमजोर होती दिख रही है। इसमें कोई शक नहीं कि जब इस तरह की कट्टरता को आवाम समर्थन देती है तो फिर देश की बुनियादी मुद्दों के लिए कोई जगह नहीं होती है।

कांग्रेस को इसी तरह के दो कट्टरवादी विचारधाराओं का समना करना पड़ा था। मगर लोगों का विश्वास कांग्रेस के साथ रहा और देश आजाद हो गया। मुस्लिम लीग की स्थापना का मकसद ही मुस्लिम परस्ती और अलग देश की मांग थी। और ऐसा ही कुछ हाल हिंदू महासभा का रहा था। खैर हम बात ओवैसी की पार्टी की कर रहे हैं। बिहार में करीब उन्हें पांच फीसदी वोट मिले जिसके बाद ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि वह अब बंगाल और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी मुकाबला करेंगे। इसका मतलब यही हुआ कि बिहार में महागठबंधन को सत्ता से दूर करने के बाद वह ममता बनर्जी और उत्तर प्रदेश के संभावित गठबंधन को मुश्किल में डालेंगे। ओवैसी के इस कदम से बीजेपी को सीधा फायदा मिलता है जैसे कि बिहार में हुआ है । हालांकि ओवैसी का यह प्रयास किसी भी लिहाज से गैर-संवैधानिक नहीं है मगर जो संदेश जा रहा है वह भारतीय

संवैधानिक लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस तरह के प्रयास यही दिखा रहे हैं कि दो कट्टर विचारधारा मिलकर उदारवादी लोकतंत्रीय राजनीति को हासिए पर धकेल रहीं हैं। ओवैसी के ऐजेंडे पर विचार करें तो यही साफ होता है कि देश के मुस्लिम एकजुट हों और एक मुस्त वोट करें। यह विचार वैसा ही है जैसा कि हिंदू वोट बैंक के लिए कट्टर हिदुत्व की रीजनीति की ओर से की जा रही है। दोनों का यह प्रयास देश की राजनीति को दो ध्रुव करने की है। चुनावी राजनीति में इसमें किसी का कोई दोष नहीं है मगर आजाद भारत के ताने-बाने को जरुर झकझोड़ कर रख देगा। ओवैसी सटीक बातें और मुद्दे उठाते हैं; साथ ही बीजेपी पर हमला बोलते हैं जिससे बीजेपी के पक्ष में वोट बैक का ध्रुवीकरण होता है।

ओवैसी को समर्थन की असल समस्या है कि मुस्लिम को लगता है कि वह देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रह गया है जो आने वाले समय में और भयावह होने वाला है। इसी का फायदा ओवैसी उठा रहे हैं और मुस्लिम राजनीति का प्रतीक बनना चाह रहे हैं। इसमें दोष ओवैसी की नहीं है दोष उन मुस्लिमों का है जो इस तरह की राजनीति को समर्थन दे रहे हैं।

मुसलमानों में डर इस कदर हावी दिख रहा है कि वे परंपरागत राजनीति छोड़कर कट्टर विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले मुसलमानों ने हैदराबाद को छोड़कर कहीं भी मुस्लिम परस्ती को वोट नहीं किया था मगर महाराष्ट्र में प्रकाश एंबेडकर को साथ लेकर ओवैसी ने अच्छी सफलता पा ली, फिर बिहार में पांच सीट पर विजयी रहे।

इस तरह की राजनीति से हिंदू-मुस्लिम भेद की खाई और चौड़ी होती जा रही है जिसे पाटने वाली उदारवादी विचारधारा कमजोर होगी। मुस्लिम हक की लिहाज से देखें तो इस तरह की राजनीति ना ही देश की हित में है और ना ही मुसलमानों के हक में। हिंदू-बहुसंख्यकों ने बीजेपी को समर्थन देकर अपना पक्ष जाहिर कर दिया। अब मुस्लिमों के एक पक्ष ने ओवैसी को समर्थन देकर लोकतंत्र की राजनीति पर

लगभग प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। ऐसे में सेक्युलर राजनीति को चाहिए कि वे अपने-आप को बदले और इस खतरे से निपटे, नहीं तो सेक्युलर राजनीति के लिए अब अधिक समय नहीं बचा हैं।

क्या देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पार्टी बनाने की कवायद हो रही है- दो- तीन विधानसभाओं के नतीजें पर गौर करें तो साफ दिख रहा है कि मुसलमान अपने लिए नेता ढुंढ रहे हैं। पहले ये कांग्रेस को पूर्ण समर्थन दिया करते थे, मगर 1992 के बाद गैर-कांग्रेसी और गैर-बीजेपी को समर्थन देने लगे। वी पी सिंह, मुलायम सिंह, लालू यादव या किसी गैर कांग्रेसी को समर्थन दिया मगर अब वे अपने ही कट्टर और मुस्लिमपरस्त विचारधारा वाले नेता को समर्थन दे रहे हैं। देखने वाली बात है कि ओवैसी ने बिहार के बाद बंगाल और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बात कही है मगर वह असम में चुनाव नहीं लड़ेगें। इसका मतलब यही हुआ कि वह असम में मुस्लिमपरस्ती की राजनीति करने वाले बदरुददीन अजमल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगें। इससे असम में मुस्लिम वोट बैंक नहीं बटेंगे और अजमल कमजोर भी नहीं होंगे।

ओवैसी केरल में भी चुनाव नहीं

“ ओवैसी को समर्थन की असल समस्या है कि मुस्लिम को लगता है कि वह देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर रह गया है जो आने वाले समय में और भयावह होने वाला है। इसी का फायदा ओवैसी उठा रहे हैं और मुस्लिम राजनीति का प्रतीक बनना चाह रहे हैं। इसमें दोष ओवैसी की नहीं है दोष उन मुस्लिमों का है जो इस तरह की राजनीति को समर्थन दे रहे हैं।

लड़ेंगे। वहां पहले से ही इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग इस ऐजेंडे को लेकर राजनीति करती आ रही है। मतलब साफ हुआ कि ओवैसी सिर्फ वहीं राजनीति करेंगे जहां हिंदू उदारवादी लोकतांत्रिक पार्टियां राजनीति करती हैं। जैसे बंगाल में ममता बनर्जी, उतर-प्रदेश में अखिलेश यादव की सपा, कांगेस और बसपा, फिर महाराष्ट्र में कांग्रेस-एनसीपी-शिवसेना अघाड़ी। ओवैसी के इस राजनीति को गौर से देखेंगे तो दूर की कौड़ी दिखने लगेगी जो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि ये दो कट्टर विचारधारा देश की लोकतांत्रीय राजनीति को धर्मीक कट्टरता में विभाजित कर आमने-सामने खड़ा करने की जुगत में है।

इसमें दोष इनका नहीं है। ये चुनावी राजनीति के लिहाज से गलत भी नहीं हैं । गलत वे हैं जो इस तरह की राजनीति करने वाले को समर्थन देती है और गलत वे पार्टियां भी हैं जो देश की आवाम की नजरों में कमजोर होती दिख रही है। इसमें कोई शक नहीं कि जब इस तरह की कट्टरता को आवाम समर्थन देती है तो फिर देश की बुनियादी मुद्दों के लिए कोई जगह नहीं होती है।

दिल्ली में खुद हवा को सांस लेने में तकलीफ

संदीप ठाकुर

दिल्ली में कुदरत ने ऐसी आंखमिचौली शुरू की कि आंखों में जलन शुरू हो गई। धुंध की चादर ने एक बार फिर से दिल्ली को इस कदर जकड़ा कि सांस फूलने लगी। प्रदूषण के स्तर में एक बार फिर ऐसा इजाफा हुआ कि दिल्लीवालों का दिल ही बैठा जा रहा है। दरअसल, राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में दबे-पांव प्रदूषण ने वापसी की है। हुआ ये कि हवा की रफ्तार कम हो गई जिससे प्रदूषण के कण को हौसला मिल गया और फिर आबोहवा में घुल-मिलकर इसने हवा ही खराब कर दी। देश की राजधानी दिल्ली के लिए अब यह आम बात होती जा रही है। हर साल नवंबर के महीने में दिल्लीवासियों की आंखें जलने लगती हैं, फेफड़े चोक हो जाते हैं और लोगों का खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस तरह दिल्लीवासियों के लिए सर्दियों की शुरूआत होती है। इस साल भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन इस बार कोरोना का कहर भी बरपा है। प्रदूषित हवा कोरोना को बढ़ाने में शायद एक तो करेला, दूजे चढ़ा नीम का काम कर रहा है।

दिल्ली में स्वच्छ हवा का व्यापार शुरू

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना काल में यदि सबसे अधिक डिमांड किसी भी चीज की बढ़ी है तो वह है स्वच्छ हवा। हवा यानी प्योर ऑक्सीजन। जो देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर यानी गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद में उपलब्ध नहीं है। सरकार साफ हवा को लेकर मौसम और कुदरत के भरोसे बैठी है। इसलिए जो हवा उपलब्ध है वह सांस लेने लायक नहीं है। क्योंकि यहां की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो गई है। इसलिए जरुरत मंद लोग डिब्बा बंद हवा खरीद रहे हैं।

> देश की राजधानी दिल्ली के लिए अब यह आम बात होती जा रही है। हर साल नवंबर के महीने में दिल्लीवासियों की आंखें जलने लगती हैं, फेफड़े चोक हो जाते हैं और लोगों का खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इस तरह दिल्लीवासियों के लिए सर्दियों की शुरूआत होती है। इस साल भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। लेकिन इस बार कोरोना का कहर भी बरपा है।

ताकि शरीर में ऑक्सीजन का लेबल बना रहे। सवाल अपने आप से पूछिए कि क्या आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस देश की राजधानी में किसी भी जगह पर स्वच्छ हवा के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं ना। लेकिन फिलहाल देश की राजधानी दिल्ली में स्वच्छ हवा के लिए कीमत चुकानी पड़ रही या फिर बाजार में हवा को प्यूरीफाइ करने वाले उपकरण खरीदने पड़ रहे हैं। स्वच्छ हवा का व्यापार शुरू हो गया है। दिल्ली के साकेत के सेलेक्ट सिटी मॉल में एक ऑक्सीजन बार खोला गया है, जिसका नाम oxy pure है। इस बार में फ्लेवर्ड ऑक्सीजन बेचा जा रहा है। कीमत 10 से 15 मिनट का 250 से 300 रुपए। यहां पर आने वाले ग्राहकों का कहना है कि इसके प्रयोग से काफी अच्छा महसूस होता है। लोग यहां आने को इसलिए मजबुर हैं ताकि शरीर में ऑक्सीजन का लेबल बना रहे। इतना ही नहीं यदि आप बार तक जाने की जहमत भी उठाना नहीं चाहते तो पास पड़ोस के किसी अच्छे मेडिकल शॉप में चले जाएं। वहां ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर 500 से 600 रुपए में मिल जाएगा।

साफ हवा को लेकर सरकार भगवान भरोसे

प्रदूषण की चादर से ढकी राजधानी दिल्ली की हवा बेहद जहरीली हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबसे प्रदूषित शहरों की यह लिस्ट जारी की है। प्रदूषित शहरों की इस लिस्ट में यूपी का गाजियाबाद शहर दूसरे तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा फरीदाबाद, वाराणसी, गया, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, मुजफ्फरपुर, श्रीनगर, गुरुग्राम, जयपुर, पटियाला और जोधपुर के नाम भी इस सूची में शामिल है। सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में दिल्ली टॉप नंबर पर है। वैसे तो राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके 12 हो महीने खतरनाक प्रदूषण की चपेट में रहने लगे हैं। हालात इतने गंभीर हैं कि दिल्ली की हवा सात गुनी जहरीली पाई गई है। पिछले तीन-चार सालों से यही हो है कि अक्तूबर-नवंबर-दिसंबर के महीने में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर को भी पार कर जाता है और शहर गैस चैंबर में तब्दील होने लगता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा है जो इस समस्या से राहत दिलाने में कारगर हो सके। और यह समस्या सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों की है।

पराली जलाने का दस्तूर कोई नया नहीं

दिल्ली और इसे सटे राज्यों में प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार पंजाब और हरियाणा को माना जा रहा है, जहां किसान हर साल खेतों में पराली जलाते हैं और इस पराली का धुआं उत्तर भारत के बड़े हिस्से में फैल जाता है। हालांकि पिछले तीन साल में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्ती दिखाई और जिम्मेदार सरकारों को झकझोरा। लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात वाला रहा। और प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। प्रधानमंत्री के साथ गत 24 नवंबर को हुई वीडियो बैठक में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना के मामले की सबसे बड़ी वजह पराली को ही बताया। उन्होंने कहा कि पराली की वजह से प्रदूषण और प्रदूषण के कारण कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। अतीत खंगाला जाए तो पराली जलाने की समस्या कोई आज की नहीं है। किसान हर फसल काटने के बाद नई फसल के लिए खेतों को साफ करने के लिए पराली जलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को निर्देश दे रखे हैं कि किसानों को किसी भी सूरत में पराली न जलाने दी जाए और उन्हें पराली के निपटान के विकल्प सुझाए जाएं। अगर किसान पराली जलाते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाए। ऐसा लगता है कि इस तरह के निर्देश कागजों तक ही रह जाते हैं। या फिर प्रदूषण कम करने को लेकर सरकार गंभीर नहीं है।

प्रदूषण के चपेट में किशोरावस्था

सर गंगाराम अस्पताल द्वारा किए गए अध्ययन में दावा किया है कि दिल्ली के युवाओं के फेफड़े अब काले पड़ने लगे हैं। अस्पताल के सर्जन डॉ. अरविंद कुमार का कहना है कि कई मरीजों के फेफड़ों में ब्लैक स्पॉट नजर आते हैं, जो पीएम 2.5 के कण शरीर में जाने के बाद दिखाई देते हैं। अभी तक इस तरह के ब्लैक स्पॉट मैच्योर लोगों में ही नजर आते थे। इस बार प्रदूषण का विकराल रूप टीनेजर्स (किशोरावस्था) को भी नहीं बख्श रहा।

डॉ. कुमार का कहना है कि लगभग 150 फेफड़ों में कैंसर ग्रस्त मरीजों पर ये अध्ययन किया गया। इसके अनुसार जो

लोग स्मोक करते हैं और जो नॉन स्मोकर हैं, उन दोनों में फेफड़ों का कैंसर समान था। यानी, 50 प्रतिशत फेफड़े कैंसर स्मोक की वजह से और 50 प्रतिशत लंग्स कैंसर नॉन स्मोकर को था। कैंसर इन्हें प्रदूषण की वजह से हुआ था। गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अकेले नहीं जो इस बात को कह रहे हैं। मैक्स अस्पताल के डॉ. रजनीश मल्होत्रा, सफदरजंग अस्पताल के डॉ. जुगल किशोर, एम्स के डॉ. नवल ने भी सहमति जताई है। इनका कहना है कि उनके पास रोजाना कई ऐसे मरीज आ रहे हैं जिन्हें जहरीली हवा के चलते हार्ट में परेशानी हो रही है। इस प्रदूषित हवा का असर शरीर के प्रत्येक हिस्से में पड़ता है और हार्ट भी इनमें से एक है। जब हम इस वातावरण में सांस लेते हैं तो पीएम 2.5 के कण शरीर में जाते हैं और यह हार्ट, लंग्स जैसी चीजों पर जम जाते हैं जिसकी वजह से सांस लेने में परेशानी होती है। हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि इसमें अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स भी आ चुके हैं। ये पीएम 2.5 से भी छोटे हैं। इन्हें पीएम 1 भी कहा जाता है। ये अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स सीधे ब्लड में घुलकर पूरे शरीर में चले जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि इसे किसी तरह की दवा, योगा या अन्य चीज से बाहर नहीं निकाला जा सकता।

कोविड संक्रमण के फैलने का कारण प्रदूषण भी

बतौर विशेषज्ञ कोविड संक्रमण को और भी खतरनाक बनाने में वायु प्रदूषण भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल के न्यूरोलॉजी निदेशक और प्रमुख डॉ. प्रवीण गुप्ता का मानना है कि 'प्रदूषण को स्ट्रोक और हृदय रोग की मुख्य वजह के रूप में पहचाना गया है, जो स्ट्रोक के जोखिम वाले कारकों या दिल की कोई बीमारी में 25 प्रतिशत तक जोखिम बढ़ाते हैं।' उन्होंने कहा, 'उच्च स्तर के वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से आंखों में जलन, गले में घरघराहट, खांसी, सांस लेने में समस्या हो सकती है। वायु प्रदूषण फेफड़ों और हृदय को भी प्रभावित कर सकता है। स्मॉग से आंखो में जलन, थकान, माइग्रेन, सिरदर्द, चिंता और डिप्रेशन भी हो सकता है।' डॉ गुप्ता ने कहा कि यह त्वचा को खराब भी कर सकता है और एलर्जी संबंधी समस्या और बालों की समस्याएं पैदा कर सकता है।

दिल्ली-एनसीआर के बाशिंदे रोज 30 सिगरेट पीते हैं

दिल्ली और आसपास की हवा फिर बिगड़ चुकी है। सरकार क्यों और काहे पर अटकी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक के हिसाब से यदि देखें तो विगत कुछ सालों से अक्तूबर-नवंबर-दिसंबर में दिल्ली की हवा ऐसी हो जाती है कि यहां के बाशिंदे रोज 30 सिगरेट पीने के बराबर धुआं अपने अंदर भरते रहते हैं। इस बार भी हालात वैसे ही हो गए हैं। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने से लेकर, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और फैक्ट्री से लेकर पटाखों तक से होने वाले प्रदूषण तक, वो सब कुछ हो रहा है, जो दिल्ली का दम घोंटता है। सांस के साथ उनके फेफड़ों में जहर आहिस्ता-आहिस्ता पैबस्त होता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या दिल्ली अपनी हवा को साफ कर पाएगी? हवा के प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं - पार्टिकुलेट मैटर यानी पीएम, सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन. पार्टिकुलेट मैटर यानी वो काला धुआं जो गाड़ियों और कारखानों से निकलता है। साथ ही वो खाना बनाने के लिए जलाई जाने वाली लकड़ी से भी पैदा होता है। यही पीएम पराली जलाने से भी हवा में घुलता है। कारों से सल्फर डाई ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन के तौर पर प्रदूषण फैलाने वाले केमिकल निकलते हैं। यानी लॉकडाउन के समय जो लाभ हुआ था, वह अब गायब हो चुका है। वजह पराली जलाना मानी गई है।

साफ हवा के मामले में चीन आगे,भारत पीछे

बहरहाल, कारण चाहे जो हो, असल मुद्दा है कि अपने लोगों को साफ-सुथरी हवा में रखने में अपना देश फिलहाल नाकाम है। दुखद यह है कि औद्योगिक रूप से अधिक विकसित और अधिक आबादी वाले चीन की तुलना में भी भारत की स्थिति बदतर है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर (सोगा)-2020 रिपोर्ट से सामने आया है कि वायु प्रदूषण से होने वाली सालाना मौतों में चीन और भारत अव्वल देश हैं।

दुनिया में होने वाली उन कुल मौतों में इन दोनों देशों का हिस्सा 58 फीसदी है। चीन में पिछले साल करीब 14.2 लाख लोगों की मौत के पीछे वायु प्रदूषण से जुड़ी बीमारी एक वजह थी, वहीं भारत में इन मौतों का आंकड़ा 9.80 लाख रहा। मगर रिपोर्ट से ये भी साफ है कि सबसे अधिक मौतों के बावजूद प्रदूषण से लड़ने में चीन भारत की तुलना में बेहतर स्थिति में है। जानकार चीन में अधिक मौतों के पीछे वहां की बुजुर्ग आबादी को वजह मानते हैं।

सोगा की रिपोर्ट में 30 सर्वाधिक प्रदूषित देशों में के बीच भारत नंबर एक पर है। चीन ने अपनी रैंकिंग में काफी सुधार किया है और वह 29वें नंबर पर है। उपग्रह से मिली तस्वीरें बताती हैं कि पिछले सात सालों में चीन में हालात सुधरे हैं। वहां अब पीएम 2.5 का स्तर 45 से 75 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जबकि भारत में यह स्तर औसतन 85 माइक्रोग्राम से अधिक रहता है। गौरतलब है कि चीन ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पहली व्यापक पंचवर्षीय योजना 2013 में लागू की और उसके बाद तय लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार कोशिश जारी रखी।

पिछले एक दशक में चीन में पीएम 2.5 का स्तर 30% गिरा है। इसके लिए चीन ने कोयला छोड़कर अपने पावर प्लांट गैस आधारित बनाए। चीन ने अपने बिजलीघरों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उम्दा तकनीक भी फिट की है। प्रदूषण पर काबू की तमाम कोशिशें रिहायशी और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में लागू की गईं। यही कारण है कि आज चीन का उत्सर्जन भारत से चार गुना है, लेकिन वहां की हवा भारत के मुकाबले करीब ढाई गुना अधिक साफ है। ये तुलना हमारे लिए काम की है। इसलिए अगर चीन अपनी हवा सुधार सकता है, तो आखिर भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता?

धर्मेंद्र मिश्रा

दिल्ली पुलिस में तैनात रहे डीसीपी के आगे बौने हुए आयकर व ईडी जैसे महकमें

रसूखदार अरबपति आईपीएस का मायालोक

भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में दागी दिल्ली पुलिस के आईपीएस सत्यवीर कटारा एक बार फिर अपने मायालोक के कारण सुर्खियों में है। उनके खिलाफ आईपीएस एसोसिएशन में शिकायत की गई है। तीन साल पहले आयकर विभाग की छापेमारी में कटारा की 17 शैल कंपनियों और अरबों रूपए की 11 संपत्तियों का पता चला था। आयकर विभाग ने तब दावा किया था कि कटारा के परिवार की शैल कंपनियों के फर्जी बिलों से करीब पांच लाख अमेरिकी डॉलर की रकम का भुगतान विदेश में हुआ है। दिलचस्प बात ये है कि मनी लॉड्रिंग और फेरा के इस मामले की जांच ईडी से कराने की जगह बाद में आयकर विभाग ने पूरे मामलें में ही लीपापोती कर दी।

बताया जाता है कि आरोप है कि आरएसएस से जुड़े एक कद्दावर राष्ट्रीय नेता को अपना करीबी बताने वाले कटारा खाकी वर्दी की आड़ में काली कमाई से लगातार अपने कुबेर का खजाना भरते रहे और किसी ने उनके उपर नजर टेढी करने की जहमत भी नहीं उठाई।

मथुरा के रहने वाले भारत भूषण शर्मा ने आईएएस एसोसिएशन में जो शिकायत की है उसके मुताबिक 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी सत्यवीर कटारा का कई बार विवादों में घिरने के बावजूद आजतक कोई जांच एजेंसी बाल बांका नहीं कर सकी जिसके कारण वे यहां से वहां नियुक्ति पाते रहे।

> **कटारा के घर तथा कारोबारी ठिकानों पर 9 सितंबर 2017 को जब आयकर विभाग ने छापा मारा था तो वे दिल्ली पुलिस की मलाईदार ब्रांच लाइसेंसिंग विभाग के डीसीपी थे। आयकर विभाग ने छापे में उनकी 17 शैल कंपनियां होने का दावा किया था । अकेले दिल्ली के पॉश इलाकों में ही उनकी 11 बेशकीमती संपत्तियों का खुलासा हुआ था।**

बता दें कि कटारा के घर तथा कारोबारी ठिकानों पर 9 सितंबर 2017 को जब आयकर विभाग ने छापा मारा था तो वे दिल्ली पुलिस की मलाईदार ब्रांच लाइसेंसिंग विभाग के डीसीपी थे। आयकर विभाग ने छापे में उनकी 17 शैल कंपनियां होने का दावा किया था । अकेले दिल्ली के पॉश इलाकों में ही उनकी 11 बेशकीमती संपत्तियों का खुलासा हुआ था। आरोप लगा था कि सत्यवीर कटारा ने बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की है। उनके खिलाफ छापे में मनी लांड्रिग के सबूत भी मिले थे। आयकर विभाग ने दावा किया था कि उन्होंने फर्जी बिलो से 5 लाख अमेरिकी डालर अमेरिका भेजा।

दिल्ली पुलिस के ही अधिकारी बताते है कि उन दिनों लाईसेंसिंग विभाग में भ्रष्टाचार अपने चरम पर था। हर चीज के रेट फिक्स थे। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि आयकर विभाग के छापे के बावजूद सत्यवीर कटारा को न तो निलंबित किया गया न ही बर्खास्त।

आईपीएस एसोसिएशन को कटारा के काले कारनामों का शिकायती पत्र लिखने वाले बी बी शर्मा ने ही पहले आयकर विभाग को भी कटारा की काली कमाई कमाई का पुलिंदा भेजा था। उसी के बाद रसूखदार आईपीएस के यहां मजबूरन छापा मारा था। लेकिन कार्रवाई से पहले ही कटारा के शुभचिंतको ने छापे की खबर लीक कर दी थी। आरोप है कि इसी के चलते कटारा ने अधिकांश सबूत अपने ठिकानों से हटा दिए। इसके बावजूद आईटी विभाग को जो कुछ मिला था वो भी चौंकाने वाला था। अगर किसी साधारण व्यक्ति की एक भी शैल कंपनी या विदेशों से लेन देन अथवा आय से अधिक संपत्ति का पता चलता है तो ईडी और सीबीआई जैसे महकमें उसे सड़क पर ले आते हैं।

लेकिन 17 शैल कंपनी और करीब 400 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का खुलासा होने के बावजूद इस रसूखदार आईपीएस का बाल भी बांका नहीं हो सका।

आयकर विभाग ने करोड़ो की टैक्स चोरी होंने का भी दावा किया था। आयकर विभाग ने छापे की कार्रवाई में जिस तरह के दस्तावेज बरामद होंने का दावा किया था उसमें होना तो ये चाहिए था कि सत्यवीर कटारा की काली कमाई की जांच ईडी और सीबीआई से करायी जाती। आयकर विभाग ने तो ये भी दावा किया था कि बोगस कंपनिया बनाकर जिस तरह फंड को विदेशी खातों में ट्रांसफर किया गया उसने आरबीआई की गाइडलाइन का भी उल्लंघन किया।

सत्यवीर कटारा के ससुर श्याम शर्मा, पत्नी पल्लवी एवं गौरव शर्मा

शिकायतकर्ता ने आरटीआई के जरिए भी आईपीएस सत्यवीर कटारा उनकी पत्नी पल्लवी कटारा सास, ससुर व साले की संपत्तियों से जो जानकारी हासिल की वो चौंकाने वाली है।

लेकिन हैरानी की बात ये है कि इन तमाम धांधलियों के बावजूद आयकर विभाग ने ही कुछ समय बाद इस मामले का ठंडे बस्ते में डाल दिया।

इससे इन आरोपों का बल मिलता है कि सत्ता में बैठे बेहद प्रभावशाली लोगों का कटारा को वरदहस्त प्राप्त है। आजीवन बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता रहे शिकायतकर्ता भारत भूषण शर्मा भ्रष्टाचार के खिलाफ दम भरने वाली मोदी सरकार में इस कार्रवाई से बेहद आहत है। इसीलिए उनके आरोपों में सच्चाई नजर आती है कि आरएसएस से जुड़े एक कद्दावर राष्ट्रीय पदाधिकारी के दबाव में कटारा के खिलाफ चल रही जांचो को कूडे के ढेर में डाल दिया गया। इतना ही नहीं सत्ता में रसूख के दम पर कटारा ने अपने निलंबन की कार्रवाई को भी रूकवा लिया।

अलबत्ता इसके बाद उन्हें दिल्ली पुलिस में कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं सौपी गई। दिलचस्प बात ये है कि शिकायतकर्ता को आयकर विभाग ने आज तक ये नहीं बताया कि किन कारणों से कटारा के खिलाफ जांच में आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई और क्या आय से अधिक संपत्ति के मामलें में उन पर कोई पेनल्टी लगाई गई।

साधारण परिवार के कटारा कैसे बने कुबेर

मूल रूप से यूपी के अलीगढ के रहने वाले सत्यवीर कटारा दानिप्स कैडर के अधिकारी है। 1996 में उन्हें आईपीएस कैडर मिला।

एक सामान्य परिवार के सत्यवीर कटारा 26 साल पुलिस की नौकरी में कैसे चार सौ करोड की संपत्ति के मालिक बन गए, किस तरह उनके ससुर श्याम शर्मा, सास राधा शर्मा, साला गौरव शर्मा, मध्य वर्ग से निकलकर करोड़ो की फैक्ट्रियों और संपत्तियों के मालिक बन गए, कैसे कटारा ने अपनी पत्नी वे अन्य रिश्तेदारों के नाम पर दिल्ली से लेकर देश विदेश तक में करोड़ो की संपत्तियां बना ली गई और इन सबको अंजाम देने के बाद कैसे उन्होंने खुद को पाक साफ बचाकर रखा। कटारा के इस मायालोक पर दिल्ली पुलिस या आयकर विभाग का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं हैं।

आयकर विभाग के छापे के बाद प्रकाश में आई शैल कंपनियां

फॉरशान हैल्थे केयर प्रा. लि. अकाया एंटरप्राइजेज, फरीदाबाद, ईशान हैलथ केयर प्रा. लि. , पनॉश ग्लोाबल प्रा.लि., ग्रेनों प्रोजेक्टजस प्रा.लि., जय शिवा इन्फ्रा प्रोजेक्टड प्रा.लि., जेएंडडी इन्फ्रा प्रोजेक्ट स प्रा. लि., जेवी मैडीकल सर्विसेंज प्रा.लि., आईएए कंस्ट्र क्श न प्रा.लि., टैक्नोंर इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रा. लि., रतन मैडीकोज प्रा. लि., जीबीके प्रोजेक्ट प्रा. लि., सार्क प्रोजेक्ट प्रा. लि., बीएससी प्रोजेक्टं प्रा. लि., आरआर एक्सिम प्रा.लि.

शिकायतकर्ता का आरोप है कि दो महीने पूर्व तबादले के बाद दिल्ली से अरूणाचल में पहुंचे आईपीएस कटारा के हरियाणा के एक पूर्व कांग्रेस सांसद और दो शीर्ष व्यापारिक घरानों से करीबी संबंध हैं, जिन्होंने उन्हें ये संपत्ति बनाने में मदद की। आरोप ये भी कि कटारा के करीबी रिश्तेदार उनकी पांच से अधिक कंपनियों में निदेशक, शेयरधारक या भागीदार के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी अधिकांश कंपनियों में डाइरेक्टर तो उनकी पत्नी पल्लवी है, लेकिन सभी कंपनियों का कामकाज कटारा खुद संभालते हैं।

आईपीएस एसोसिएशन को भेजे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि कटारा 1 मिलियन डॉलर के निवेश के साथ टाइम्स स्क्वायर, मैनहट्टन, यूएस के पास, हकीमियन होटल प्रोजेक्ट के 60 निवेशकों में से एक है। अमेरिकी निवेश के अलावा, राजधानी दिल्ली के पॉश सैनिक फार्म और लगभग 50 गायों के साथ एक गौशाला फार्म के मालिक भी। इसी गौशाला के जरिए वे खुद को गौभक्त बताकर सत्तारूढ पार्टी व संघ के नेताओं की नजर में हीरो बने हैं।

दिल्ली के ग्रेटर कैलाश और बिजवासन जैसे इलाकों में उनके बेशकीमती बंगले उत्तर प्रदेश के नोएडा और इलाहाबाद और फरीदाबाद के पास सूरजकुंड में उनके पास आलीशान फ्लैट का तो आयकर विभाग ने ही खुलासा किया था। उनकी लक्जरी वाहनों के बेड़े में देशी गाडियों के साथ बेशकीमती बीएमडब्ल्यू और ऑडी एसयूवी कारे और हार्ले-डेविडसन जैसी कीमती मोटरसाइकिल भी शामिल बताई गई थी।

कैसे करते है कारोबार

आयकर विभाग के छापे में पता चला था कि दिल्ली में बदरपुर के एक ही पते पर कटारा ने कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस, मैडिकल सुरक्षा उपलब्ध कराने वाले कई शैल कंपनियां बनाई हुई थी। जिनमें उनके भाई और बहन हेमलता शर्मा व लव शर्मा के अलावा अलग-अलग फर्म में दूसरे रिश्तेदार भागीदार थे। कटारा कथित तौर पर कॉरपोरेट सॉल्यूशंस के एक्सिस बैंक, लाजपत नगर शाखा और विजय बैंक, नेहरू प्लेस शाखा के बैंक खातों लिए खुद अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे। उनकी शैल कंपनियां सिर्फ कागजों पर चलती थी। लेकिन उनके बिलों पर अमेरिका तक में भुगतान हुए। जिसके बाद सीधा मामला ईडी को मनी लॉंड्रिंग का दर्ज करना चाहिए था।

शिकायतकर्ता का ये भी आरोप है कि कटारा ने अपनी काली कमाई का निवेश अपने ससुराल वालों के साथ उनकी संपत्तियों और कारोबार में किया। उनकी पत्नी पल्लवी कटारा ग्रेटर कैलाश के जिस एस-231 बंगले में रहती है उसी

की कीमत 35 करोड से अधिक बतायी जाती है। शिकायतकर्ता का ये भी आरोप है कि कटारा अपनी काली कमाई को लेकर विदेश में बसने की चाह रखते है। इसी नीयत से उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अमेरिका से ग्रीन कार्ड वीजा का आवेदन भी किया लेकिन सफल नहीं हो सके, लेकिन अपने मंशा को पूरी करने के लिए वे अपने बड़े बेटे का पहले ही विदेश में सैटल कर चुके है, जो उनकी विदेशी कंपनियों और बैंक खातों को हेंडल करता है।

शिकायतकर्ता ने आरटीआई के जरिए भी आईपीएस सत्यवीर कटारा उनकी पत्नी पल्लवी कटारा सास, ससुर व साले की संपत्तियों से जो जानकारी हासिल की वो

अब तक प्रकाश में आयी आईपीएस कटारा की संपत्तियां

1. एस-231 फर्स्ट फ्लोर, ग्रेटर कैलाश-2, दिल्ली ।
2. सैनिक फार्म दिल्ली में ढाई हजार वर्ग गज का फार्म हाउस
3. सैनिक फार्म में 2000 वर्ग गज में गाय दूध की डेरी
4. यूपी के अलीगढ स्थित गांव चुहरपुर गुभाना में खसरा संख्या 163, 163 / 2, 163 / 3 व 135 आदि।
5. बी 21/22 विक्रम कालोनी रामघाट रोड, अलीगढ में कोठी
6. गौरव इंटरनेशनल व मंत्रा बैंकट हॉल, गुलर रोड अलीगढ़
7. 15 एकड़ जमीन बुलंदशहर यूपी
8. दिल्लीं में ओमेक्स के 4 शोरूम
9. नोएडा सेकटर 47 में 450 वर्ग गज में तीन मंजिला मकान
10. हरियाणा के बहादुरगढ, झज्जर में 1.4 एकड जमीन
11. यूपी के मेरठ में दूध की एक डेरी
12. दिल्ली के कापसहेडा (देवराला) में 29 बीघा जमीन
13. हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सकुरपुर की गली नंबर 10 में 850 वर्ग गज का एक प्लाट
14. फरीदाबाद में 5 एकड जमीन
15. फरीदाबाद में 2 एकड जमीन पर 250 गायों की डेरी
16. यूपी के इलाहाबाद में स्तुति शिक्षा संस्था के नाम पर 80 बीघा जमीन
17. ग्रेटर कैलाश पार्ट वन के ई 26 के फर्स्ट फ्लोर पर एक फ्लैट
18. दिल्ली के मैदानगढ़ी स्थित छतरपुर रोड़ पर 795/71 नंबर प्लाट
19. बदरपुर के मोल्डबंद एक्सटेंशन की गली नंबर 73 में एक प्लाट
20. दिल्ली के कालकाजी मैन मार्किट में प्लाट नंबर एफ-8 के फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट
21. गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में ओमेगा-1 सेक्टर के पाकेट 2 स्थित शॉपिंग काम्पलैक्स में शॉप नंबर 10

ऐसी बहुत सी बेनामी संपत्तियां है जिनका आयकर विभाग खुलासा ही नहीं कर सकी थी।

चौंकाने वाली है। (देखें बॉक्स)

दिल्ली के विभिन्न जिलों के साथ यातायात और लाइसेंसिंग जैसे विभाग में तैनात रहे सत्यवीर कटारा वर्दी का इस्तेमाल ड्यूटी करने के लिए कम अपने धंधों को चलाने के लिए ज्यादा करते रहे हैं। कटारा भले ही अपने नेककामों से अपनी पहचान ना बना पाए हों लेकिन वर्दी का गलत इस्तेमाल कर बदनाम होंने में उन्होंने कई बार सुर्खियां बटोरी हैं। कटारा निर्भया कांड के बाद उस वक्त भी वे सुर्खियों में आए थे जब वे डीसीपी पीसीआर थे। उस वक्त उनसे उप राज्यपाल तेजेन्द्र खन्ना ने नोटिस देकर कारण पूछा था कि किन कारणों से उन्होंने अपनी ड्यूटी पर लापरवाही बरती। दरअसल, ये बात सुर्खियों में आई थी कि जिस वक्त निर्भया कांड की पीडित लडकी को बचाने के लिए पीसीआर को कॉल की जा रही थी और पीसीआर नदारद थी। उस वक्त कटारा एक पांच सितारा होटल में सुरा और सुंदरी की पार्टी में मदहोश थे। बाद में उन्होंने सवाल उठने पर अपनी तिकडमों से खुद को वारदात वाले दिन छुट्टी पर होंने के सबूत दे दिए थे, लेकिन दबी जबान आज भी दिल्ली पुलिस के अफसर इस खेल के पीछे की कहानी चटखारे लेकर बताते हैं।

2012 में जब वे पीसीआर में ही थे तब उनके खिलाफ दिल्ली के एक डाक्टर वीरेन्द्र भाटी ने पटियाला हाउस कोर्ट के माध्यम से धोखाधडी का मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि कटारा ने अपने पद और वर्दी का गलत इस्तेमाल कर उनकी मैडीकल कंपनी में भागीदार होते हुए फर्जी दस्तावेजों से हड़प ली थी । इस मामलें में उनकी पत्नी पल्लवी को भी आरोपी बनाया गया था।

कई मामलों में कटारा से पीडित शिकायतकर्ता ने अब आईपीएस एसोसिएशन को पत्र के साथ उनकी करतूतों का पुलिंदा भेजकर अपील की है। उन्होंने कहा है जब तमाम सारी संवैधानिक जांच एजेंसिया कटारा के आगे पानी भर रही है। तब अपनी साख बचाने के लिए सत्यवीर कटारा जैसे भ्रष्ट अधिकारी को सजा दिलाने के लिए उन्हें अपने स्तर से पहल करते हुए सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। ताकि आईपीएस जैसे गरिमामयी ओहदे का सम्मान बरकरार रहे।

बहरहाल देखना होगा कि सफेद हाथी बन चुकी आईपीएस एसोशिएसन इस मामलें में कितनी दिलचस्पी लेगी। लेकिन अगर शिकायतकर्ता के आरोप सच है, तो कटारा की वाकई सत्ता के गलियारों में गहरी पैठ है और उनकी काली कमायी का मायावी संसार समझने की जरूरत है।

रविवार की तरफ से सत्यवीर कटारा के दिल्ली व अरूणाचल के संपर्कों पर उनका पक्ष लेने की कोशिश की गई लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

SWISS®

SWILEC®

Our solutions drive you better

Download Our App **SAP SWISS** From Google Play App Store

W : www.sapswisssolutions.com E : info@sapswisssolutions.com F : www.facebook.com/sapswiss

Our related trademarks / labels / artistic works, are used individually as well as in association & combination with one another in the name and style of Swiss Auto Products serving since 1974.

SWISS AUTO PRODUCTS SWISS SWILEC SWILEC

इरा झा

देवगुड़ी का मसला महंगा न पड़ जाए

छत्तीसगढ़ के मुख्यमत्री भूपेश बघेल ने आदिवासियों के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आदिवासी बहुल राज्य के प्रमुख होने के नाते उन्हें अपने मतदाताओं का खयाल है ये बहुत अच्छी बात है। इसी संकल्प के तहत उन्होंने बस्तर इलाके में देवगुड़ी याने आदिवासी देवस्थलों के जीर्णोद्धार के लिए कुछ धनराशि देने का फैसला लिया है।

यह धनराशि बस्तर के सभी जिलों की 143 पंचायतों के लिए रखी गई है। इस राशि के लिए संबद्ध पंचायतें देवगुड़ियों के लिए मरम्मत की मद में पैसे के लिए आवेदन कर सकेंगी। वे नई देवगुड़ियों के निर्माण लिए भी पैसा मांग सकेंगी।

वैसे सुनने में तो यह बेहद कल्याणकारी कदम है। आदिवासी आस्था पर नक्सलियों का जोर नहीं चल पाएगा और अगले चुनाव तक भूपेश सरकार आदिवासियों को नक्सली गिरफ्त से बाहर निकालकर अपने वोट बैंक में तब्दील करने में कामयाब हो जाएगी। इस पूरी कवायद को इसी अंदाज में प्रसारित प्रचारित भी किया जा रहा है।

पर आदिवासी किस तरह नक्सल प्रभाव में हैं शायद सरकार को इस बात का पूरा अंदाज भी नहीं है। इस आदेश के जारी होने के बाद जिस एकमात्र देवगुड़ी का जीर्णोद्धार हुआ है पहले तो वह कम नक्सल प्रभाव वाला क्षेत्र है। दूसरे यहां उन देवती कर्मा और उनके बेटे छवींद्र ने जीर्णोद्धार की शुरूआत की है जो सत्तारूढ़ दल की विधायक हैं और उनके बेटे को राज्यमंत्री का दर्जा हासिल है।

ये दोनों ही आदिवासी नेता महेद्र कर्मा के पत्नी और बेटे हैं जो नक्सली हिंसा में मारे गए थे। तबसे इनके आसपास भारी सुरक्षा बंदोबस्त रहता है। ये दोनों देवगुड़ी में साफ –सफाई करवाकर उन आदिवासियों के लिए शौचालय इत्यादि की व्यवस्था करने जा रहे हैं जो पक्के शौचालयों के नाम पर ही खौफ खाते हैं। उन्हें शौचालयों में जाना पसंद नहीं। वे प्राकृतिक माहौल में रहना चाहते हैं। बस्तर में इसके लिए पर बडा आंदोलन हो चुका है। सरकार पक्के शौचालयों का प्रलोभन देकर जंगल काटने जा रही थी तब आसना की सब्जी बेचने वाली महिलाओं ने चिपको जैसा आंदोलन चलाकर सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया था।

खैर, यह जाहिर है कि जिन नेताओं ने जीर्णोद्धार की शुरूआत

> **सरकार के लिए यह जानना जरूरी है कि चार किताबें पढ़कर या बस्तर का सैर सपाटा कर एक किताब लिखकर कोई कम से कम बस्तर के आदिवासियों का जानकार नहीं हो सकता। वैरियर एल्विन बनने के लिए बड़ी तपस्या की जरूरत है।**

की उनके लिए यह आसान नहीं रहा होगा।

दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार इस तरह यह संदेश देना चाहती थी कि आदिवासियों को उनका यह फैसला बहुत पसंद आया है और इस मामले में वो नक्सलियों के किसी फरमान की परवाह नहीं करेंगे। उसे भरोसा था कि आदिवासी आस्था के मामले में नक्सली भी दखल नहीं देंगे। पर सरकार का यह अंदाज गलत निकलता लग रहा हैं। नक्सली इस बात से बेहद नाराज हैं। उन्होंने दो दिन पहले फरमान जारी कर कहा है कि देवगुड़ी पर सरकार का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी इसके लिए पहलकदमी करेगा उसे नक्सली जमीन में जिंदा गाड़ देंगे।

सोचिए आदिवासी की हालत सांप छछूंदर जैसी है। वो किसकी मानें किसे सुने। सरकार तो बहुत दूर बैठी है। ऐसी हालत में नक्सलियों के हुक्म की नाफरमानी आदिवासी क्यों करेगा। नतीजा ये है कि देवगुड़ियों के

जीर्णोद्धार के लिए सरकार की बजाय अब नक्सलियों को आवेदन भेजे जा रहे हैं।

बस्तर के कलेक्टर दीपक सोनी के अनुसार ने हर गुड़ी को इस मद में सात लाख रूपए दिए जाएंगे। इस तरह बस्तर की सांस्कृतिक विरासत को और समृद्ध किया जा रहा है। ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि बस्तर के इन देवस्थलों का सभी जायजा ले सकें।

पर यह बस्तर के कलेक्टर का बिल्कुल मुगालता है कि जीर्णोद्धार के बाद हर किसी को आदिवसी धर्मस्थल में जाने की इजाजत मिल जाएगी। शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि बस्तर की आदिवासी संस्कृति पूरी दुनिया से हटकर है। आदिवासियों के लिए आस्था निहायत निजी और भावनात्मक मसला है। इन आस्था केंद्रों में वो बाहरी तो दूर गैर जाति के आदिवासी भाइयों को तक नहीं को जाने की इजाजत नहीं देते।

मुझे याद है 1966 में आदिवासी संस्कृति का शोधार्थी कौतुहलवश देवगुड़ी के अहाते में घुस गया था तो आदिवासियों ने जबरदस्त बवाल काटा था। और प्रशासन को दखल देना पडा था।

बस्तर दशहरा और विजय दशमी के शुभ अवसर पर विधायक व संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र के 24 पंचायतों में देवगुड़ी निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत 1-1 लाख की राशि में से प्रथम किस्त की राशि का 40-40 हजार रुपए रविवार को पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच तथा ग्राम पुजारियों को दिया गया।

वैसे आदिवासी देवगुड़ी के लिए ऐसी राजनीति पहल भी पहली बार नहीं हो रही है पर हर बार सरकार को अपने कदम थामने पड़े हैं।

पहली बार आदिवासी नेता अजित जोगी ने आदिवासियों के लिए बहुत से फैसले लिए थे। इनमें देवगुड़ियों के जीर्णाद्धार के मद में धनराशि आबंटित की गई थी। इसे आदिवासियों ने अपनी आस्था में दखलंदाजी के तौर पर लिया था। गांव–गांव बात फैल गई थी नतीजा अजीत जोगी को बस्तर अंचल में करारी हार मिली उनकी सरकार नहीं बनी।

माना ये जाता है कि आदिवासी पहचान के लिए विवादास्पद रहे जोगी से बस्तर के बाशिंदे नाराज हो गए थे। फिर भी अजीत जोगी अपनी आदिवासियत की दुहाई देते नहीं थकते थे। उनकी पहल पर ही रमन सिंह सरकार ने भी हर गुड़ी के लिए एक लाख रूपए देने का फैसला किया था और अब न जाने कैसे भूपेश बघेल को इन देवगुड़ियों का खयाल आ गया। पर उनका भी अनुमान गलत है। आदिवासी देवगुडियों के मसले पर भी नक्सलियों का मान रखेंगे। नक्सलियों का फरमान तो है ही जिससे वो घबराते हैं। पर उनसे आदिवासियों का लिहाज का भी नाता है। वो बखूबी जानते हैं कि वक्त पडने पर नक्सली उनके काम आ सकते हैं। सलवाजुडूम की भयंकर प्रताडना हो या नगा फोर्सेस का आतंक या फिर बोधघाट पर कुरबान किए जा रहे उनके जंगल उन्हें इन्हीं की तरफ ही देखना पडेगा। सरकार के नेता उनके पास सिर्फ वोट मांगने आते हैं। वो जंगल की परेशानियों से उन्हें बचा नहीं सकते। सरकार चाहे तो भी उन्हें वक्त पर मदद कभी नहीं मिलेगी।

इस तरह लगता है कि सरकार के तरकश से आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के लिए निकला ये तीर बेकार सबित होगा। इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। जिसके सलाहकारों में आदिवासी मामलों के वो जानकार है जिन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं समझा। जिनके पास सिर्फ किताबी जानकारी है। सरकार के लिए यह जानना जरूरी है कि चार किताबें पढ़कर या बस्तर का सैर सपाटा कर एक किताब लिखकर कोई कम से कम बस्तर के आदिवासियों का जानकार नहीं हो सकता। वैरियर एल्विन बनने के लिए बड़ी तपस्या की जरूरत है।

आदेश के जारी होने के बाद जिस एकमात्र देवगुड़ी का जीर्णोद्धार हुआ है पहले तो वह कम नक्सल प्रभाव वाला क्षेत्र है। दूसरे यहां उन देवती कर्मा और उनके बेटे छवींद्र ने जीर्णोद्धार की शुरूआत की है जो सत्तारूढ़ दल की विधायक हैं और उनके बेटे को राज्यमंत्री का दर्जा हासिल है।

सरकार के तरकश से आदिवासी वोट बैंक को लुभाने के लिए निकला ये तीर बेकार सबित होगा। इसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है। जिसके सलाहकारों में आदिवासी मामलों के वो जानकार है जिन्होंने आदिवासी संस्कृति को नहीं समझा। जिनके पास सिर्फ किताबी जानकारी है।

कुलपतियों की स्वायत्तता और जवाबदेही

देवेंद्र सिंह असवाल

पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों (केविवि) के एक कई कुलपतियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शैक्षणिक जगत में चिन्ता का कारण रही है। विश्वविद्यालयों का एक बड़ा धड़ा इसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवश्यक कदम मानता है तो कुछ को आशंका है शैक्षणिक स्वायत्तता क्षीण होने की। विषय चिंताजनक है और इसे सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। कुलपति का पद गरिमामय पद है और शैक्षणिक जगत उसे 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' मानते हैं। प्रत्येक विश्वविद्यालय के गठन अधिनियम और कानून, अध्यादेश और विनियम उपयुक्त स्वायत्तता प्रदान करते हैं ताकि कुलपति अपने दायित्वो का निर्वहन

> **विचारणीय प्रश्न यह है कि कुलपतियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शैक्षणिक स्वतंत्रता को क्षीण करेगी? क्या ये अनुशासनात्मक कार्रवाई उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कुप्रभावित कर उनकी शैक्षणिक गरिमा को धुमिल करेगी?**

कुशलतापूर्वक और दक्षता से निष्पादित करें। परंतु स्वायत्तता, जवाबदेही का अभिन्न अगं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सभी व्यक्ति, चाहे कितने भी उच्च पद पर आसीन हों, जवाबदेह हैं- 'आप कितने भी ऊंचे हों, कानून आपसे ऊपर है।' वास्तव में, पद जितना उच्चा हो, उतना अधिक ही सार्वजनिक नजर और निगरानी का विषय रहता है। भारत का संविधान, कानून के समक्ष समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की गारंटी देता है, यहाँ तक कि भारत के राष्ट्रपति को भी संविधान के उल्लंघन के लिए संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। अतः राज्य के सभी पदाधिकारी अधिकारी जवाबदेह हैं।

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली, दुनिया में दूसरे स्थान पर है, जिसमें 54 केविवि, 411 राज्य विश्वविद्यालय, 123 डीम्ड विश्वविद्यालय और 282 निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यकारी और प्रशासनिक प्रमुख होता है। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति का कार्यान्वयन, संस्थागत सुधार, जांच और अनुसंधान की भावना को पोषित करना, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण और सुशासन के अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाना, कुलपतियों का परम दायित्व है। एक आदर्श कुलपति दूरदर्शी, शिक्षकों का इच्छुक सहयोगी, छात्रों के लिए निरंतर प्रेरणा स्रोत, एक कुशल प्रशासक और विश्व विद्यालय के लिए सक्षम नेतृत्व के दायित्व को सम्पादित करता है। उसकी योग्यता और उसकी ईमानदारी संदेह से परे होनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना उसका दायित्व है कि विश्वविद्यालय अपने अधिनियम, कानून, अध्यादेश और विनियम के प्रावधानों के अनुरूप चले और उनकी पूर्णरूपेण अनुपालना हो। वास्तव में कुलपति के कर्तव्यों की सूची लम्बी और विविध है। वह विश्वविद्यालय का दर्पण एवं प्रतिनिधि भी है। कुलपति का चयन एक विशिष्ट प्रतिक्रिया से किया जाता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयो के मामले में राष्ट्रपति और राज्य विश्वविद्यालयों के मामले में राज्यपाल उनके विजिटर या आगंतुक होते है। खोज समिति (सर्च

कमेटी) द्वारा सुझाए गए पैनल से, जिसमें तीन से पांच सदस्य होते है जो प्रशासनिक अनुभवयुक्त प्रतिष्ठित शिक्षाविद होते हैं, विज़िटर कुलपति को चुनते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जिन कुलपतियों पर प्रशासनिक कार्रवाई हुई वे उसी सरकार द्वारा नियुक्त थे। कुलपतियों के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की महत्वपूर्ण जाँचे मोटे तौर पर चार श्रेणियों में आती है; (क) वित्तीय अनियमितता के आरोप, (ख) कर्तव्यच्युति और अवज्ञा के आरोप, (ग) धन के गलत विनियोग, और (घ) शैक्षणिक धोखाधड़ी। विज़िटर किसी भी कुलपति के विरुध्द स्वेच्छा से अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं करते। शिक्षा मंत्रालय या संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय की सलाह पर ही अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है। कार्रवाई शुरू करने के मूल में होते हैं मीडिया की हेडलाइन्स, विधायकों, छात्रों और शिक्षको की शिकायतें। कुछ मामलों में कुलाधिपति द्वारा कुलपति के खिलाफ जांच की मांग की गई। एसी स्थिति में विजिटर का दायित्व कि प्रशासनिक मंत्रालय शिकायतों की जाँच करे और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिये अपनी सुचिन्तित सिफारिश करे । कुछ मामले उल्लेनीय हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नियुक्तियों में गंभीर अनियमितता और वित्तीय नियमों के उल्लघंन के लिए विश्व भारती के कुलपति को बर्खास्त करने की मंजूरी दी। पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति को अकादमिक धोखाधड़ी के लिए हटा दिया गया था। महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के वीसी ने इस्तीफा दे दिया जब सरकार ने उनसे सवाल पूछे उनकी उपाधियों के सम्बन्ध में। संसद में वित्तीय और अकादमिक अनियमितताओं के बारे में सवाल उठने पर सार्वजनिक शिकायतों के बीच, केंद्र सरकार दंडात्मक कार्रवाई शुरू करने से पहले ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वीसी ने इस्तीफा दे दिया। इसी तरह गढ़वाल विश्वविद्यालय और मणिपुर विश्वविद्यालय के कुलपतियों को वित्तीय अनियमितताओं और ड्यूटी से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण पदच्युत हुये। त्रिपुरा विश्वविद्यालय के वीसी ने उस समय इस्तीफा दे दिया जब एक स्टिंग ऑपरेशन ने उन्हें कथित रिश्वत लेते हुए दिखाया। ऐसे मामलों में जहां कुलपतियों ने अनुमोदित बजट हेड्स के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धनराशि को विनियोजित किया था, शरुवाती पूछताछ के बाद मामले बंद कर कर दिये गये क्योंकि कोई व्यक्तिगत वित्तीय लाभ नहीं हुआ था। हाल ही के एक मामले में, तमिलनाडु सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं, और सेमेस्टर परीक्षाओं में गड़बड़ी और पुनर्मूल्यांकन की शिकायतों के बाद अन्ना विश्वविद्यालय (राज्य विश्वविद्यालय) के वीसी के खिलाफ जांच का आदेश दिया है, हालांकि डीएमके ने कुलपति को बर्खास्त करने की मांग की है। दिल्ली विश्व विद्यालय के 98 वर्ष के इतिहास में, राष्ट्रपति ने, आगंतुक के रूप में, कुलपति को निलंबित कर दिया ताकि गंभीर कदाचार, कर्तव्यों के निर्वहन और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जांच हो सके।

विचारणीय प्रश्न यह है कि कुलपतियों के खिलाफ कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्या विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और शैक्षणिक स्वतंत्रता को क्षीण करेगी? क्या ये अनुशासनात्मक कार्रवाई उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कुप्रभावित कर उनकी शैक्षणिक गरिमा को धुमिल करेगी? स्वायत्तता और अकादमिक स्वतंत्रता विश्वविद्यालयों के उन्नयन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है, और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी माहौल में उत्कृष्टता प्राप्त करने की कुंजी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्वायत्तता पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है और अनत्तोगत्वा, हर महाविद्यालय को स्वायत्त डिग्री देने वाला संस्थान में तब्दील करने को कहती है ताकि भारत पुनः वैश्विक केंद्र के केन्द्र में उभरे। यह समय है कि हमारे विश्वविद्यालय स्वायत्त रहें, वैश्विक प्रतिस्पर्धा के माहौल में काम कर सकें और अपनें श्रेयस्कर उदेश्यो को प्राप्त कर सकें पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ। स्वायत्तता और उत्तरदायित्व सहचर है। 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन' और 'हल्के लेकिन सख़्त नियम' के कथन यही इंगित करते है।

पूर्व आयुक्त सचिव, लोकसभा और एक लेखक

भूमि सुधार

सरकारें बदल गईं, देश की भूमि सुधार नीति नहीं

जून 2016 में उच्च स्तरीय कमेटी बना कर भूमि नीति के प्रारुप को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दो को छोड़कर बाकी सभी मंत्रालय इसके सदस्य हैं। उच्च स्तरीय कमेटी बड़ी गंभीरता से अपना काम कर रही बतायी गयी है। बहरहाल, पिक्चर अभी अधूरी है क्योंकि जब तक नीति का प्रारुप प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच जाता तब तक इसकी कहानी अधूरी रहेगी।

अजय कुमार चतुर्वेदी

बारह साल पहले देश में राष्ट्रीय स्तर की एक समिति गठित की गई, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष बनाए गए, समिति के विचार के लिए मुद्दों और संदर्भ आदि बनाने के लिए 7 उप समूह भी बन गये और सभी समूहों ने अपना - अपना काम भी कर दिया, एक बड़े अधिकारी की अध्यक्षता में बनी एक अन्य समिति ने रिपोर्ट का प्रारुप भी बना दिया.... लेकिन कहानी अभी तक अधूरी है। भूमि और कृषि सुधार पर राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति बनी। 9 जनवरी 2008 को समिति के गठन की अधिसूचना जारी हो गई। नीति से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए सात उप समूह भी बन गये जिन्होंने राष्ट्रीय समिति के संदर्भों पर विचार किया।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान के महानिदेशक की अध्यक्षता में डाफ्ट (प्रारुप) कमेटी भी बन गयी और प्रारुप भी बन गया लेकिन..... प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस समिति को तैयार प्रारुप प्रस्तुत होना है। यह 12 सालों की समिति की यात्रा रिपोर्ट है।

राष्ट्रीय भूमि सुधार नीति

इस गंभीर मुद्दे पर विचार के लिए जो लंबी चौड़ी समिति बनी उसमें सामाजिक मुद्दों के छह केंद्रीय मंत्रालयों के मंत्री, दस राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा कुछ विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे।

समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करके 3 सितंबर 2009 को उस समय के गामीण विकास मंत्री ने प्रधानमंत्री को सौंप दी। रिपोर्ट में कुल 325 सिफारिशें हैं।

इनमें से 99 सिफारिशों को लागू करवाने के लिए राज्यों की सहमति लेने की बात कही गई है, 55 अन्य सिफारिशें राज्यों को मात्र सलाह देने तक सीमित है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर समिति ने 21 सिफारिशें/सुझाव दिए हैं। यह सुझाव भूमि हदबंदी, भूदान, किरायेदारी सुधार (टेनेन्सी), रियासत अधिकार (होमस्टीड राइट्स), वन भूमि, जनजातीय भूमि अलगाव की भावना (ट्राइबल लैंड एलीनियेशन), भूमिहीन घुमंतू जनजातियां, भूमि

मई 2014 में एन डी ए की सरकार सत्ता में आ गयी। नये ग्रामीण विकास मंत्री ने मई 2015 में प्रारुप में कुछ नये मुद्दे शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने नाम बदल कर राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति अथवा राष्ट्रीय भूमि नीति करने को कहा।

अधिग्रहण, सांझी संपत्ति के संसाधन (कामन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज), पडती तथा सरकारी भूमि (वेस्टलैंड एंड गवर्नमेंट लैंड), महिलाओं का भू अधिकार, भूमि प्रबंधन का आधुनिकीकरण, भू-रिकार्ड का कम्प्यूटरीकरण, नक्शों को डिजिटाईज करना, भू-प्रबंधन में पंचायतों की भूमिका, पूर्वोत्तर राज्यों में भूमि प्रबंधन, भू-राजस्व को योजना हेड के तहत रखना, राष्ट्रीय भूमि परिषद गठित करना, भूमि न्यायाधिकरणों का गठन, जिला स्तर पर राजस्व अधिकारी का नया काडर बनाना और भूमि बैंक का गठन किया जाना।

बैठक से पहले ही समझौता हो गया

रिपोर्ट के प्रारुप और मांगे गए सुझावों के परीक्षण की जांच की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने सचिवों की एक समिति को सौंपी और उस समिति से सुझाव देने के लिए कहा गया ताकि उन्हें विचार के लिए राष्ट्रीय समिति में रखा जा सके। नौ बैठकों के बाद सचिवों की समिति ने अपने सुझाव और संसतुतियां अप्रैल 2011 में पी एम ओ को सौंप दी। इसके बाद मयी 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय से समिति की बैठक आयोजित करने को कहा गया और राष्ट्रीय समिति की बैठक 28 अक्टूबर 2011 के लिए निर्धारित हो गई। लेकिन इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना घट गई। ग्रामीण विकास मंत्रालय और जन सत्याग्रह के बीच 11 अक्टूबर 2011 में आगरा में दस मुद्दों पर एक समझौता हो गया। अब इस नयी सहमति और मुद्दों पर विचार के लिए मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक नई टास्क फोर्स (कार्य बल) एक साल बाद बनाई। इस टास्क फोर्स न जोरदार अध्ययन करके तमाम सुझावों के साथ जून में राष्ट्रीय भूमि सुधार पालिसी - 2013 का प्रारुप तैयार कर दिया। इसमें फिर कुछ सुधार किया गया और 24 जुलाई 2013 को पालिसी का संशोधित प्रारुप बना। प्रारुप राज्यों को भेज कर उनसे सुझाव मंगाए गये।

सरकार बदल गई

इतनी लंबी चौड़ी कवायद के बाद भी तत्कालीन यू पी ए सरकार के प्रधानमंत्री इस समिति की बैठक नहीं आयोजित करवा पाए। मई 2014 में एन डी ए की सरकार सत्ता में आ गयी। नये ग्रामीण विकास मंत्री ने मई 2015 में प्रारुप में कुछ नये मुद्दे शामिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने नाम बदल कर राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति अथवा राष्ट्रीय भूमि नीति करने को कहा।

ताजी जानकारी के मुताबिक जून 2016 में उच्च स्तरीय कमेटी बना कर भूमि नीति के प्रारुप को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दो को छोड़कर बाकी सभी मंत्रालय इसके सदस्य हैं। उच्च स्तरीय कमेटी बड़ी गंभीरता से अपना काम कर रही बतायी गयी है। बहरहाल, पिक्चर अभी अधूरी है क्योंकि जब तक नीति का प्रारुप प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच जाता तब तक इसकी कहानी अधूरी रहेगी।

AHAAR®

Nutrition For Your Family

Breakfast to Dinner

ISO 22000:2005 FOOD SAFETY

fssai 10012011000842

Ahaar Consumer Products (P) Ltd.

G-37, Group Industries, Lawrence Road, Delhi-35

Ph.: 011-27195002/3/4, Fax : 011-27186220

email : ahaarconsumer@gmail.com, info@ahaar.com

Website : www.ahaar.com

AHAAR®

विराट की कमी भारत के लिए कितनी 'विराट'?

सत्येन्द्र पाल सिंह

मॉडर्न क्रिकेट के सबसे बड़े हीरो हैं टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली। सामने जितना बड़ा प्रतिद्वंद्वी अपने नाम के मुताबिक उसके खिलाफ उतना ही 'विराट' प्रदर्शन। विराट को मुश्किलों के बीच राह बनाना खूब आता है। उन्हें हार का कभी खौफ नहीं रहता। वह जीत और सिर्फ जीत के लिए खेलते हैं। विराट एक दशक से कुछ ही ज्यादा के क्रिकेट करियर में अपने कौशल, जीवट और निष्ठा से नित नई बुलंदियां चूम रहे हैं। क्रिकेट के हर फॉर्मेट में गियर बदल कर खेल कर खेलने में भी उनका कोई जवाब नहीं है। विराट दुनिया के उन विरले बल्लेबाजों में से एक हैं जिनका क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में औसत 50 रन से अधिक का है। यही उन्हें दुनिया के नए बेताज 'क्रिकेट बादशाह' के रूप में स्थापित करता है। सुनील गावसकर, विव रिचडर्स, ब्रायन लारा, एलन बॉर्डर से लेकर अपने आदर्श सचिन तेंडुलकर जैसे धुरंधर क्रिकेटरों तक को विराट ने अपना मुरीद बनाया है। आज दुनिया के हर नौजवान क्रिकेटर का आदर्श बन गए हैं गुरु राजकुमार शर्मा के सबसे काबिल शागिर्द विराट कोहली। विराट यूं तो क्रिकेट का हर स्ट्रोक बखूबी खेलना जानते हैं लेकिन उनके कवर ड्राइव और फ्लिक लाजवाब होते हैं। तेज दौड़ रन चुराना भी उन्हें खूब आता है।ऑस्ट्रेलियाई टीम को उनके अंदाज में जवाब देने मे बतौर कप्तान और बल्लेबाज विराट कोहली का कोई जवाब नहीं है। विराट को ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्लेजिंग करने से भी इसलिए कतराते हैं क्योंकि वह उन्हें पलट कर उसी अंदाज में जवाब में देते हैं।

पुजारा और रहाणे में है ऑस्ट्रेलिया से बाजी छीनने का दम

ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में शिकस्त देकर उसके खिलाफ 71 बरस में टेस्ट सीरीज जिताने वाले पहले भारतीय कप्तान हैं विराट कोहली। बतौर कप्तान विराट ने यह कारनामा भारत को उसके 2018-19 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर मेजबान टीम के खिलाफ चार टेस्ट की सीरीज में 2-1 से जीत दिलाकर किया था। यह पहला ऐसा मौका था कि जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया से उसके घर में तीन मैचों की टी-20 सीरीज एक-एक से ड्रा कराने के बाद, उससे चार टेस्ट मैचो की सीरीज 2-1 तथा तीन वन डे मैचों की सीरीज भी 2-1 से जीती। यह ऐतिहासिक कामयाबी भारत को विराट की कप्तानी में ही मिली थी। विराट की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके घर में फिर तीन वन डे, तीन टी-20 और चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए पहुंच चुकी है। भारत के कप्तान विराट कोहली 'पितृत्व अवकाश' के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की सीरीज के एडिलेड के पहले डे नाइट टेस्ट के बाद स्वदेश लौट आएंगे। विराट अपने पहले बच्चे के जन्म के समय अपनी पत्नी अनुष्का के साथ भारत में रहना चाहते हैं। लाख

टके का सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी तीन टेस्ट मैचों में बतौर कप्तान और बल्लेबाज विराट की कमी भारत के लिए कितनी 'विराट' होंगी? विराट के पहले टेस्ट के बाद भारत वापस लौट जाने के फैसले से फिलहाल दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया की बांछे खिल गई हैं। गेंद से छेड़छाड़ करने के कारण एक साल के प्रतिबंध के कारण पिछली बार बाहर रहने वाले डेविड वॉर्नर और स्टीव स्मिथ की अब भारत के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में वापसी हो गई है। इन दोनों की टीम में वापसी से कई दिग्गज मेजबान आस्ट्रेलिया का टेस्ट सीरीज में पलड़ा भारत से भारी मान रहे हैं पर यह आधा सच ही है। इन दिग्गजों को यह नहीं भूलना चाहिए कि विराट की गैरमौजूदगी में भी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में अपने घर में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को टेस्ट मैच में धूल चटा चुकी है। यह दशार्ता है कि विराट की गैरमौजूदगी में रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जैसे भारतीय बल्लेबाजों में अपने खेल का स्तर उंचा उठा ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत प्रतिद्वंद्वी के हाथ से टेस्ट में बाजी छीनने का दम है। ऐसे में इस बार टेस्ट सीरीज पिछली टेस्ट सीरीज से ज्यादा रोचक और रोमांचक होने की आस जरूर की जा सकती है।

विराट फिर रख सकते हैं टेस्ट सीरीज जीत की नींव

बेशकभारत को 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया से उसके घर में चार टेस्ट मैचों की सीरीज जिताने में बतौर कप्तान और बल्लेबाज विराट का योगदान 'विराट' रहा था। खुद विराट की नजर में किसी भी क्रिकेटर को सही ढंग से आंकने का पैमाना टेस्ट क्रिकेट ही है। विराट की सबसे बड़ी ताकत खुद बेहतरीन प्रदर्शन की कूवत के साथ बतौर कप्तान पूरी टीम से बेहतरीन प्रदर्शन कराने की क्षमता है। विराट यदि पिछली टेस्ट सीरीज की तरह एडिलेड (डे-नाइट) में इस बार भी भारत

को सीरीज का पहला टेस्ट जिताने में कामयाब रहे तो वह फिर उसकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार दूसरी बार टेस्ट सीरीज जिताने की नींव रख देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत अपना दूसरा टेस्ट उसी मेलबर्न मैदान पर खेला है जो उसके लिए खासा 'लकी' रहा है। भारत ने 1977 और 1981 में सुनील गावसकर और चेतन चौहान तथा 2019 में विराट कोहली और पुजारा की बेहतरीन बल्लेबाजी से मेलबर्न में दमदार अंदाज में टेस्ट जीते हैं। बेशक विराट कोहली अपने आपमें एक 'टीम' हैं लेकिन इतिहास गवाह है कि चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, लोकेश राहुल, रोहित शर्मा मयंक अग्रवाल, नौजवान ऋषभ पंत, शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ में हालात के मुताबिक अपने खेल का स्तर उंचा उठा कर भारत को फिर टेस्ट सीरीज में जिताने की कूवत है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार रहा है विराट का रिकॉर्ड

विराट ने अब तक 86 टेस्ट मैच खेल कर 27 सेंचुरी और 22 हाफ सेंचुरी की बदौलत 53.62 की औसत से 7240 रन बनाए हैं। भारत के सचिन तेंडुलकर दुनिया में सबसे ज्यादा दो सौ टेस्ट खेल कुल 15921 रन बना रन बनाने में आज भी शीर्ष पर कायम हैं। वहीं भारत के लिए टेस्ट में रन बनाने में फिलहाल विराट छठे नंबर हैं। फिलहाल सचिन के रिकॉर्ड के करीब पहुंचने का दम यदि भारत के किसी बल्लेबाज में है तो वह केवल और केवल विराट ही हैं। विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 19 टेस्ट खेल कर सात सेंचुरी और चार हाफ सेंचुरी सहित कुल 1604 रन बनाए हैं। विराट ने 12 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसकी धरती पर खेले और इनमें छह सेंचुरी और तीन हाफ सेंचुरी सहित बनाए कुल 1274 रन बनाए। उनका यह दमदार प्रदर्शन यह बयां करता है कि विराट टीम इंडिया के लिए बेहद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में बेहद अहम हैं।

ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतरीन अंतिम एकादश चुनना बड़ी चुनौती

एक दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमों के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती पिच और टेस्ट के मिजाज बेहतरीन एकादश का चयन है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत के खिलाफ बेहतरीन अंतिम एकादश चुनना बड़ी चुनौती होगा क्योंकि उसने अपनी टीम में पांच नए चेहरों को जगह दी है। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ी परेशानी टेस्ट में डेविड वॉर्नर के सलामी जोड़ीदार को लेकर है। खुद कप्तान पेन और वॉर्नर चाहते हैं फिलहाल रंगत पाने को जूझ रहे जो बर्न्स ही टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पारी का आगाज करें। वहीं ऑस्ट्रेलिया चयनकर्ता नौजवान विल पुकोवस्की को वॉर्नर के सलामी जोड़ीदार के रूप में देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी डेविड वॉर्नर, स्मिथ, लबुशेन और कप्तान टिम पैन पर ही निर्भर है। रफ्तार के साथ यॉर्कर और उछाल से पिछली बार टेस्ट सीरीज के भारत के सबसे कामयाब गेंदबाज रहे अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (21 विकेट) व मोहम्मद शमी (16 विकेट) के साथ इस बार नवोदित नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज नई गेंद से धार और रफ्तार से गेंदबाजी कर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को सांस नहीं लेने देंगे।

इनके साथ फिट होकर इशांत शर्मा के भी टीम के जुड़ जाने की उम्मीद से टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी और विविधतापूर्ण हो जाएगी। भारत के पास टेस्ट सीरीज में कमी है तो केवल बाएं हाथ का तेज गेंदबाज की है। साथ स्पिन ऑलराउंडरों- रवींद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन खासतौर पर निचले क्रम में हेड, कमिंस और स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया के लंबे मैदानों पर लंबे स्ट्रोक और बड़ा स्कोर करने का मौका नहीं देंगे। चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव को उसी सूरत में टेस्ट सीरीज में मौका मिल सकता है यदि भारत तीन स्पिनरों के साथ उतरने का फैसला करे।

अब रफ्तार भारतीय बल्लेबाजों के लिए हौवा नहीं

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसके घर में पिछली चार टेस्ट की सीरीज में तीन सेंचुरी सहित चेतेश्वर पुजारा (कुल 521 रन) ने सबसे ज्यादा रन बनाकर, ऋषभ पंत (कुल 350 रन) और कप्तान विराट कोहली (कुल 282 रन) एक -एक सेंचुरी सहित तथा अजिंक्य रहाणे (कुल 282 रन) और हनुमा विहारी (217 रन) ने जीवट से बल्लेबाजी कर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजी की धार कुंद कर भारत को दिलाई जीत थी। विराट की गैरमौजूदगी में केएल राहुल चौथे, कप्तान रहाणे पांचवें नंबर पर उतर कर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को थका सकते हैं। रोहित शर्मा के पहले टेस्ट तक फिट हो जाने को भले ही अगर मगर हो लेकिन भारत के पास उनका भी विकल्प है। संकेत ऐसे हैं कि यदि रोहित पहले टेस्ट तक फिट नहीं हुए थे फिर उन्हीं की मुंबई टीम के श्रेयस अय्यर को एकादश में शामिल किया जा सकता है। यदि जरूरत हुई तो सीमित ओवरों की सीरीज के बाद श्रेयस को ऑस्ट्रेलिया में रोका जा सकता है क्योंकि हेड कोच चाहते है कि रोहित और इशांत जल्द से जल्द टीम इंडिया से जुड़े। विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए बाएं हाथ के ऋषभ पंत ही सबसे बेहतर विकल्प होंगे क्योंकि रिद्धिमाना साहा के टेस्ट सीरीज तक फिट होने को लेकर शंकाएं बरकरार है। यूं भी ऋषभ पंत का ऑस्ट्रेलिया की धरती पर टेस्ट सीरीज में भारत के लिए रिकॉर्ड शानदार रहा है। उवह ताबड़तोड़ ऑस्ट्रेलिया के आक्रमण को बेदम कर सकते हैं। ये सभी इस बार विराट की गैरमौजूदगी में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार फिर अपने बल्ले से जलवा दिखाने को बेताब हैं। इस बार बतौर स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और अश्विन को भारत की अंतिम एकादश में जगह मिलने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया की पिचें भले ही भारत से तेज हों लेकिन अब उतनी तेज नहीं रहीं जितनी कभीं हुआ करती थी। अब रफ्तार भारतीय बल्लेबाजों के लिए हौवा नहीं रही। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, जोश हेजलवुड और कमिंस, पैटिनसन अपनी रफ्तार से भारतीय बल्लेबाजों को डिगा पाएं इसकी उम्मीद कम है। हां ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज स्यां एबॉट जरूर भारत के बल्लेबाजों को थोड़ा चौंका जरूर सकते हैं। भारतीय बल्लेबाजों की आईपीएल की शानदार फॉर्म के मद्देनजर ऑस्ट्रेलिया के तुरुप के ऑफ स्पिनर ल्यॉन (21 विकेट) के पिछली टेस्ट सीरीज के प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद कम है।

आखिर शेयर बाजार में निवेश कैसे करें ?

सुधीर कुमार

शेयर बाजार में फटाफट पैसे दुगुने हो जातें हैं ये बात अक्सर वो लोग करतें हैं, जिन्हे शेयर बाजार का, क ख, ग, नहीं मालूम होता हैं और जो लोग निवेश करते है उनमें अधिकतर ऐसे लोग होते है जो उस दिन को कोसते हैं, जिस दिन उन्होंने शेयर बाजार में अपनी गाढ़ी कमाई निवेश किया था।

आखिर ऐसा क्यों होता है ?

पहली वजह, शेयरों का गलत चयन। दरअसल अधिकतर निवेशक कम मूल्यों के शेयर को ही सस्ता समझ लेते हैं, लेकिन शेयर का मूल्य उसकी कीमत से नहीं बल्कि उसका पी. ई. रेश्यो यानी लाभ कमाने की क्षमता तय करती हैं, उदहारण के लिए एच डी एफ सी बैंक का पी ई अनुपात 27 है, जबकि एक्सिस बैंक का पी ई रेसियो 76 के आस पास है। यानि एच डी एफ सी बैंक का शेयर जिसकी कीमत 1400 रुपए सस्ता है, जबकि एक्सिस बैंक जिसकी कीमत 600 रुपए है वह महंगा है।

क्या है पी. ई. रेश्यो ?

किसी कंपनी के मुनाफे में उसकी कुल शेयरों की संख्या से भाग देने पर ई. पी. एस. निकलता हैं , अर्थात एक शेयर की कमाई और उस ई. पी. एस. से शेयर की बाजार कीमत को भाग देने पर पी. ई. रेश्यो निकलता है।

उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी की शेयर की कीमत 200 रुपए है ,और उसका ई. पी. एस. 20 रूपया है, तो उसका पी. ई. रेश्यो 10 हुआ।

दूसरी वजह , असंतुलित निवेश,

अक्सर निवेशक कम कीमत की शेयरों में अपनी पूंजी का ज्यादा भाग निवेश करते है जबकि अच्छी कंपनी की शेयरों से बचते है या फिर अपनी पूंजी का छोटा हिस्सा निवेश करते है क्यूंकि अच्छी कम्पनियों के शेयर महंगे होते है।

आखिर कैसे करें निवेश ?

सबसे पहली बात, आपका नजरिया लम्बा होना चाहिए, कम से कम दस साल का।

इसके बाद आप अपनी पूंजी को दस भागों में बांट दीजिये , फिर उन पैसों को देश की दस सबसे बड़ी कंपनियों में बराबर भागों में निवेश कर दीजिए यदि उन दस कंपनियों में से आठ कंपनी दिवालिया भी हो जाये तब भी आपको फायदा ही होगा।

> **अगर योजनाबद्ध तरीके से निवेश किया जाये तो न केवल आपकी पूंजी बढ़ती है बल्कि लाभांश के रूप में आपको एक नियमित आय भी प्राप्त होती रहती है।**

उदाहरण के लिए अगर किसी निवेशक ने 2010 में एक लाख रुपए देश की दस बड़ी कम्पनियो में इस फामूर्ले से निवेश किया होता, तो आज उनके निवेश का क्या हाल है आइए इसको समझते है।

गौरतलब है की दस साल पहले रियल एस्टेट पुरे उफान पर था ,जबकि सरकारी कंपनी ओ एन जी सी और भेल देश की सबसे बड़ी कम्पनियाँ हुआ करती थी, लेकिन आज उनकी माली हालत खस्ता है।

अगर योजनाबद्ध तरीके से निवेश किया जाये तो न केवल आपकी पूंजी बढ़ती है बल्कि लाभांश के रूप में आपको एक नियमित आय भी प्राप्त होती रहती है।

JK LAKSHMI CEMENT Ltd.
इंडिया,
अब सोच करो
बुलंद.
बुलंद सोच ही इरादों को हकीकत में
बदलने का हौसला रखती है,
और इसी बुलंद सोच को आकार देता
है जे के लक्ष्मी सीमेंट.
JK LAKSHMI CEMENT
JK LAKSHMI PRO+ CEMENT
www.jklakshmicement.com
facebook.com/JKLakshmiCementLtd
twitter.com/JKLCofficial
Customer Care: 1800 102 5097

क्या भारत में काम करने के अधिकार को गरिमापूर्ण बनाया जा सकता है?

प्रियंका सौरभ

दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं महामारी की दोहरी मार से उबरने के लिए संघर्ष कर रही है, लॉकडाउन से बेरोजगारी बढ़ रही है। मगर बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति को सक्षम करने के लिए और बुनियादी आवश्यकताओं के लिए काम चाहिए। 'काम करने का अधिकार' जीवन को जीने में सक्षम होने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। 'काम करने का अधिकार' शब्द अक्सर बेरोजगारी या काम की उपलब्धता की कमी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। भारत में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नौकरियों का वादा और बेरोजगारी की राजनीति का एक लंबा इतिहास रहा है।

> **काम करने का अधिकार अनिवार्य रूप से पूंजीवाद और कार्य नैतिकता से जुड़ा है, काम करने का अधिकार पूंजीपतियों के विरुद्ध शोषण का अधिकार है और यह पूरी तरह से उचित दृष्टिकोण है। यदि आप वास्तव में मानवता के भविष्य को देख रहे हैं, तो कोई संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपना सकते।**

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काम का अधिकार चर्चा का एक बड़ा विषय था, और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों में काम करने का अधिकार शामिल है। भारत में, हमें काम करने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है वह मनरेगा है। यह काम करने के अधिकार की दिशा में एक कदम है, लेकिन यह एक वैधानिक अधिकार है। मनरेगा के तहत, एक व्यक्ति बेरोजगारी भत्ते की मांग करके अधिकार को पूरा नहीं करने के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहरा सकता है। मनरेगा के तहत, कोई व्यक्ति राज्य को मांग के आधार पर अधिकार को पूरा नहीं करने के लिए जिम्मेदार ठहरा सकता है।

भारत में जीडीपी के अनुपात में गिरावट देखी जा रही है, और ज्यादातर बेरोजगार वृद्धि, श्रम के साथ बाजार के कानूनों से जुडी है। इन परिस्थितियों में यह अधिकार महत्वपूर्ण हो जाता है। 'काम का अधिकार' शब्द अक्सर बेरोजगारी या काम की उपलब्धता की कमी के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। लेकिन इसका एक और अर्थ भी है, जो बिना किसी बाधा के मेरी आजीविका कमाने का अधिकार है। एक तरफ, विस्थापन और फैलाव, और दूसरी तरफ, नई नौकरियां पैदा करने में विफलता ने रचनात्मक तरीके से काम करने के अधिकार की कल्पना करना और इसे कानूनी रूप से लागू करने के लिए और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है।

भारत जैसे देश में अधिक से अधिक स्वचालन से बेरोजगारी बढ़ने की संभावना है। सरकार ने श्रम संगठनों के पास 44 श्रम कानूनों को चार श्रम कानूनों में काट दिया है। श्रमिकों के अधिकारों को कमजोर करने के रूप में आलोचना की गई। भारत में सुरक्षात्मक श्रम कानून श्रम बल के एक छोटे समूह के लिए लागू होते है। बाकी लोगों के लिए, कानूनी सुरक्षा बहुत कम है, जो सुरक्षा के बारे

में बहुत कम जागरूकता और कमजोर कार्यान्वयन है। भारत में सुरक्षात्मक श्रम कानून मौजूद हैं, वे स्थायी सरकारी नौकरियों में लोगों को श्रम बल के ऋणात्मक अधिकार के लिए लागू करते हैं। इसलिए, राज्य की क्षमता में बाधाओं को देखते हुए, जब यह श्रम कानूनों को लागू करने की बात आती है, श्रम बाजार को मजबूत करना यह सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका है कि श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।

एक अच्छा रोजगार गारंटी कार्यक्रम जहां तक काम में 'अधिकार' का सवाल है। यह स्वचालित रूप से श्रमिकों के बेहतर उपचार के लिए स्थितियां बनाता है।

यहां मनरेगा के साथ नए रोजगार के अवसर सृजित करने का विचार है, ताकि जो लोग बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार प्राप्त हो सके और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस गरिमा को काम की परिस्थितियों से माना जाता है, जैसे कि उचित वेतन का भुगतान किया जाना और काम के घंटे को विनियमित करना, और इस काम का उपयोग वे उपयोगी चीजें जैसे कि स्कूल की इमारतों की मरम्मत, सफाई पार्क, और इसी तरह से करते हैं। शहरी स्थानीय निकाय प्रमाणित सार्वजनिक संस्थानों जैसे स्कूलों और विश्वविद्यालयों को पूर्व-अनुमोदित कार्यों के लिए नौकरी के वाउचर जारी कर सकते हैं।

ये संस्थान केवल पूर्व निर्धारित कार्यों के लिए श्रम को किराए पर देने के लिए वाउचर का उपयोग कर सकते हैं - जैसे कि पेंटिंग स्कूल की इमारतें, टूटे फर्नीचर की मरम्मत आदि।

कौशल की एक पूरी श्रृंखला को समायोजित किया जा सकता है। इसलिए, यह एक काम करने योग्य एजेंडा है, लेकिन इसे काम करने योग्य बनाने के लिए हमें न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि राजकोषीय संसाधनों की भी आवश्यकता है। काम का अधिकार न केवल पर्याप्त काम की कमी के बारे में है, बल्कि आम तौर पर शहरी भारत में सार्वजनिक वस्तुओं और परिसंपत्तियों की गहन कमी है। इन सार्वजनिक वस्तुओं को प्रदान करना राज्य की ज़िम्मेदारी है,

अगर योजनाबद्ध तरीके से निवेश किया जाये तो न केवल आपकी पूंजी बढ़ती है बल्कि लाभांश के रूप में आपको एक नियमित आय भी प्राप्त होती रहती है।

और इस अनिवार्यता को रोजगार सृजन कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है, जैसे कि मगनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में करता है।

काम करने का अधिकार अनिवार्य रूप से पूंजीवाद और कार्य नैतिकता से जुड़ा है, काम करने का अधिकार पूंजीपतियों के विरुद्ध शोषण का अधिकार है और यह पूरी तरह से उचित दृष्टिकोण है। यदि आप वास्तव में मानवता के भविष्य को देख रहे हैं, तो कोई संकीर्ण दृष्टिकोण नहीं अपना सकते। काम पूरा होना चाहिए, काम रचनात्मक होना चाहिए, और काम को अपनी जगह पर रखना होगा, विकेंद्रीकृत शहरी रोजगार और प्रशिक्षण मनरेगा के साथ, नए रोजगार के अवसर पैदा करने का विचार है ताकि जो लोग बेरोजगार आसानी से नियोजित हो सकते हैं और एक गरिमामय जीवन जी सकते हैं राज्य द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करके रोजगार उत्पन्न करना यह सुनिश्चित करने का एक शानदार तरीका है कि श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।

महाशय गुलाटी से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां

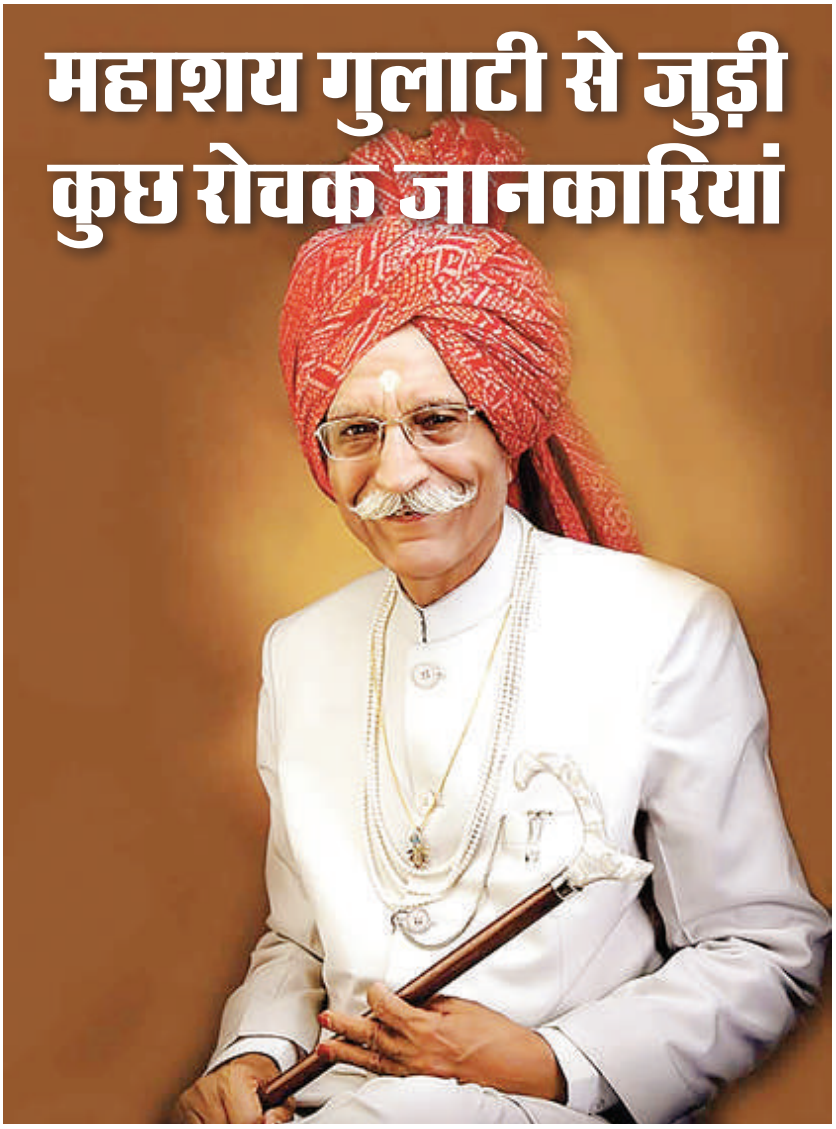

महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था, जहां उनके पिता 'महाशियाँ दी हट्टी' नामक एक दुकान से मसाले बेचने का कार्य करते थे।

वह आर्य समाज के बहुत बड़े अनुयायी हैं।

10 वर्ष की उम्र में, उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा छोड़ दी (जब वह पांचवी कक्षा में थे) और अपने पिता की दुकान पर कार्य करना शुरू कर दिया।

7 सितंबर 1947 को, वह भारत-पाक विभाजन के बाद अपने परिवार के साथ पाकिस्तान से दिल्ली, भारत लौट आए।

उसके बाद, वह दिल्ली के करोल बाग में अपनी भतीजी के घर पर रहने लगे, जहां पानी, बिजली की आपूर्ति नहीं थी।

जब वह दिल्ली आए, तब उनके पिता ने उन्हें 1500 रुपये दिए थे, जिसमें से धर्मपाल गुलाटी ने 650 रुपये का तांगा (घोडा गाड़ी) खरीद लिया और कनॉट प्लेस से करोल बाग तक यात्रियों से 2 आने लेते थे।

उन्हें अपनी आजीविका के लिए पर्याप्त रूप से साबित नहीं होने के कारण अक्सर अपमानित होना पड़ता था। इसलिए उन्होंने अपनी तांगा (घोडा गाड़ी) को बेच दिया और अजमल खान सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान बनाई और अपने परिवार का पुराना कारोबार मसालों को बेचना शुरू किया।

प्रारंभ में सफलता के बाद, उन्होंने वर्ष 1953 में चांदनी चौक में एक और दुकान किराए पर ली, जिसके चलते वर्ष 1959 में उन्होंने स्वयं की फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कीर्ति नगर में जमीन खरीदी, जहां उन्होंने एमडीएच मसालों के साम्राज्य यानि महाशियां दी हट्टी लिमिटेड की स्थापना की, जिसका अर्थ है 'एक महानुभाव आदमी की दुकान' पंजाबी में।

एमडीएच स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाड़ा, यूरोपीय देशों, इत्यादि में मसालों का निर्यात करता है।

वर्तमान में, एमडीएच भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में मसालों की श्रेणी में सबसे बड़े ब्रांडों में से एक के रूप में उभरा है, जिसका 90 साल की उम्र पार करने के बाद भी धर्मपाल गुलाटी स्वयं एमडीएच उत्पादों का विज्ञापन करते हैं।

एमडीएच 50 से भी अधिक विभिन्न उत्पादों को बेचता है।

उनके द्वारा 'महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट' चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत 250 बिस्तरों वाला एक अस्पताल और झोपड़पट्टी के निवासियों के लिए एक मोबाइल अस्पताल चलाया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में 20 स्कूल भी चलाता है। इस ट्रस्ट के द्वारा वित्तीय सहायता भी सामाजिक संगठनों को दी जाती है।

> **एमडीएच स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाड़ा, यूरोपीय देशों, इत्यादि में मसालों का निर्यात करता है।**

एमडीएच संदेश पत्रिका भी चलाता है, जो भारत के पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को प्रदर्शित करता है। वह अपनी सेहत के प्रति काफी सजग रहते हैं, जिसके चलते वह सुबह 5 बजे योगा करते हैं।

उन्होंने अपनी आत्मकथा को जारी किया है, जिसमें उनके प्रारंभिक बचपन से लेकर सफलता के पीछे के रहस्य का खुलासा किया गया है।

अनिल राय गुप्ता

हैवल्स नाम कहां से आया ?

हीर-रांझा की प्रेम कहानी हम सबने सुनी है। यह गाथा झंग की है जो अब पाकिस्तान में है।

ईसा पूर्व 2000 साल पहले इसे झंग सियाल के नाम से जाना जाता था। विभाजन के समय, जिले में ज्यादातर मुस्लिम यहां आकर बस गए। लिहाजा यह पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। पीढ़ियों से रह रहे हिन्दुओं और सिखों को अपना घर और पुश्तैनी जमीन छोड़नी पड़ी। उन्हें भारत का रुख करना पड़ा। कुछ पंजाब और आज के हरियाणा में बसे। कुछ ने दिल्ली की राह पकड़ी।

दिल्ली को आशियाना बनाने वालों में से एक थे हवेली राम गांधी। झंग जिले के चिनिओट के रहने वाले हवेली राम सही मायनों में कारोबारी थे और जिंदगी की फिर से शुरूआत करने में उन्होंने अधिक समय नहीं गंवाया। 1948 में उन्होंने हेवल्स नाम (ब्रांड का असल नाम हैवल-का Havell's था) अधिग्रहण किया। वर्ष 2008 में हमने इसे बदलकर हेवल्स (Havells) कर दिया। इसी नाम से इसे रजिस्टर करवाया गया।

इस बात को लेकर आज भी भ्रम है कि उन्होंने यह नाम कैसे चुना। इसे लेकर कई कहानियां हैं। एक कहानी यह है कि हेवल्स उनके नाम हवेली से बना है। दूसरी कहानी यह है कि हवेली राम या उनके वफादारों में से किसी एक या परिवार के किसी सदस्य ने यूरोप में यह नाम देखा था। वहां बेल्जियम की एक कंपनी का नाम हेवल्स था। उन लोगों ने यह नाम रखने का सुझाव दिया क्योंकि यह नाम हवेली से मिलता-जुलता था। एक और कहानी है कि हवेली राम हॉलैंड की एक कंपनी से बिजली के सामान आयात किया करते थे। उस कंपनी की नाम हेवल्स था। यह भी हो सकता है कि यह तीनों का मिला-जुला स्वरूप रहा हो। बहरहाल तथ्य यह है कि आज भी अधिकतर ग्राहक यह महसूस करते हैं कि हेवल्स विदेशी ब्रांड है।

मैं उनसे कभी मिला नहीं पर वर्षों तक उनके बारे में कई कहानियां सुनीं-कुछ अच्छी, कुछ दुखद। ऐसा लगता है कि हवेली राम एक अच्छे ज्योतिषी थे और सटीक भविष्यवाणियां करते थे। वे अपनी पत्नी के बहुत नजदीक थे और उन्हें भाग्यशाली मानते थे। 1950 के दशक में हवेली राम ने हेवल्स सेल्स कार्पोरेशन की शुरूआत की थी। कुछ पुराने लोगों ने मुझे बताया था कि उद्यम की शुरूआत 1956 में हुई थी।

शुरूआत में हवेली राम ने भारत के अन्य विक्रेताओं की तरह बिजली के कई उत्पाद जैसे स्विचगियर्स, स्टार्टर्स, मीटर आयात किए। यहां उनकी हेवल्स के नाम से ब्रैंडिंग की जाती और फिर बाजार में बेचे जाते थे। उन दिनों बिजली के ये उपकरण भारत में नहीं बनाए जाते थे। सिर्फ 1960 में लार्सन ऐंड टुब्रो ने स्विचगियरों का भारत में उत्पादन शुरू किया था।

> **हवेली राम हॉलैंड की एक कंपनी से बिजली के सामान आयात किया करते थे। उस कंपनी की नाम हेवल्स था। यह भी हो सकता है कि यह तीनों का मिला-जुला स्वरूप रहा हो। बहरहाल तथ्य यह है कि आज भी अधिकतर ग्राहक यह महसूस करते हैं कि हेवल्स विदेशी ब्रांड है।**

1962-63 तक आयात बाजार नाटकीय ढंग से बदल गया। 1963 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने आयात में भारी कटौती का ऐलान कर दिया। इसका मतलब था हवेली राम जैसे आयातकों के सामने मुश्किलों का आना। उनके पास तीन विकल्प थे, या तो कारोबार के आकार को छोटा करें, स्थानीय खरीद करें या फिर हेवल्स नाम से उत्पादन का आगाज करें। हवेली राम ने तीसरा विकल्प चुना जो मील का पत्थर साबित हुआ। उन्होंने फरीदाबाद में एक फैक्ट्री डाल दी। वह उस जमाने की बेहतरीन फैक्ट्री साबित हुई। मशीनें आधुनिक और कार्यकुशल थीं। वह निश्चय ही अपने इलाके की सफल फैक्ट्री रही होगी क्योंकि उस स्थान को हेवल्स चौक कहा जाने लगा था। बहुत साल बाद हमने भी हेवल्स चौक पर एक फैक्ट्री डाली।

अगले अंक में जारी

ये नया है!

कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन पत्नी टीवी एक्ट्रेस सुमोना चक्रवर्ती शो में भूरी के किरदार में नजर आती हैं। सुमोना चक्रवर्ती अक्सर अपनी तस्वीरों के कारण चर्चा में रहती हैं। वह सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं और लगातार अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। अब सुमोना चक्रवर्ती ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें अपने पैरों पर बने टैटू को दिखती नजर आ रही हैं। हालांकि सुमोना की ये तस्वीरें पुरानी हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। उनका बोल्ड अंदाज देख पैंठस दंग रह गए हैं। एक तस्वीर में सुमोना रेड कलर के स्टाइलिश आउटफिट में नजर आ रही हैं और पैरों का टैटू दिखाती नजर आ रही हैं। उनके फैंस तस्वीर पर खूब कमेंट कर रहे हैं।

बिंदासपन की झलक

जैकलीन फर्नांडीस अक्सर इंस्टाग्राम पर अपनी लेटेस्ट और हॉट तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। पैंठस की चहेती जैकलीन के इंस्टाग्राम पर 46 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। इस खास मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर की है जो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है। पैंठस उनकी इन फोटोज को लाइक करने के साथ ही इसे शेयर आर इसपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं एक्ट्रेस ने भी अपने पैंठस को इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया कहा है। जैकलीन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कई टॉपलेस फोटोज शेयर की हैं। तस्वीरों में उन्होंने अपने हाथों में फूलों का एक गुलदस्ता पकड़ रखा है। फोटोज में वाकई जैकलीन बेहद ही खूबसूरत और बोल्ड नजर आ रही हैं। उन्होंने फोटोज पोस्ट करते हुए फैन्स के लिए कैप्शन में लिखा, 'लव यू, थैंक्यू।'

काश वो मिल जाता!

कुछ न कुछ सबकी फेवरेट डिश होती है। अनुष्का शर्मा भी कुछ मिस कर रही हैं। वे इस वक्त प्रेग्नेंट हैं और जल्द ही वह अपने पहले बच्चे को जन्म देंगी। इस दुर्गाष्टमी जब पूरा देश फेस्टिव सीजन की शुरूआत को सेलेब्रेट कर रहा था तब अनुष्का नवरात्रि के अंत में बनने वाले हलवा, पूड़ी और चने से चूक गईं। अनुष्का को मां दुर्गा का प्रसाद नहीं मिल पाया और इसीलिए वह इसे काफी मिस कर रही हैं। एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर हलवा चने और पूड़ी की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'आज इसे बहुत मिस कर रही हूं. और बहुत उदासी के साथ।' अनुष्का ने उदासी वाला इमोजी लगाते हुए अपने इमोशन्स शेयर किए हैं। बता दें कि जब से अनुष्का ने आधिकारिक तौर पर अपनी प्रेग्नेंसी की खबर साझा की है, तभी से उनके फैन्स उनकी प्रेग्नेंसी से जुड़ी हर खबर सोशल मीडिया पर साझा करते रहे हैं।

अच्छी सेहत
अच्छी ज़िंदगी!
PARAM
PREMIUM
DAIRY PRODUCTS
PARAM
PREMIUM
AGMARK
DESI GHEE
Taste of Life
INGREDIENTS - MILK FAT
NET CONTENT: 1L at 45°C
(900g)
Manufactured By:
PARAM DAIRY LIMITED
Desi
Ghee
Granular with Rich Aroma
देशी
घी
Desi
Ghee
Enquiry : 1800 111 115 | www.paramdairy.com

दिसंबर 2020

दिसंबर 2020 का फल चन्द्रराशि के आधार पर किया गया है। जन्मकुंडली में चन्द्रमा जिस राशि में होता है जातक का राशि भी वही होता है जैसे यदि चन्द्रमा मेष राशि में है तो उस व्यक्ति का राशि मेष होगा अत: व्यक्ति को मेष राशिफल देखना चाहिए। वैसे ही नाम के प्रथम वर्ण के आधार पर भी राशि का निर्धारण किया जाता है जैसे यदि आपका नाम म, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू, टे वर्ण से आरम्भ हो रहा है तो आपकी राशि सिंह होगी। आपको अपना राशिफल अथवा भविष्यफल इसी राशि के अनुसार देखे। दिसंबर 2020 का राशिफल अवश्य ही आपको योजनाओ को बनाने में तथा उसका क्रियान्वयन करने में सहायता प्रदान करेगा। इस राशिफल के प्रत्येक शब्द तथा वाक्य विशेष रूप से विचारणीय है।

(चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, अ)

मेष

महिलाओं के सम्पर्क से लाभ होगा। मनमानी प्रवत्तियों से हानि होगी। यशस्त्री कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। गृह, भूमि, वाहन, परिवार का सुख मिलेगा। प्रस्तावित योजना में सफलता, बकाया धन की प्राप्ति, मासान्त में स्वास्थ्य बाधा।

(मा,मी,मु,मे,मो,टा,टी,टु,टे)

सिंह

भाग्य में सफलता का योग बना है। सुख की प्राप्ति होगी। नौकरी में तरक्की तथा उद्योग-धंन्धों में लाभ होगा। उत्तरार्द्ध में पारिवारिक झंझट तथा धन व्यय की आशंका बनेगी। संतान पक्ष से भी चिन्ता का योग है। शत्रु से छुटकारा व लाभ होगा।

(ये,यो,भा,भी,भू,धा,फ,ढ,भे)

धनु

स्वभाव में चिड़चिड़ाहट, उद्विग्नता कार्य व्यस्तता अधिक रहेगी। धन एवं धान्य सम्पत्ति की वृद्धि होगी। अचल सम्पत्ति भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य सुख में कमी, भोजन, शयन में असुविधा, श्रम की अधिकता रहेगी। शत्रुओं पर विजय मिलेगी।

(ई,उ,ए,ओ,वा,वी,वु,वे,वो)

वृषभ

मित्रों की अनुकूलता, आमदनी में कमी से मन खिन्न रहेगा। घरेलु जीवन में अशान्ति, मन ऋण चिन्ता से ग्रस्त रहेगा। सत्कर्म से राहत मिलेगी। मन के विकार भी दूर होंगे। गृह, भूमि, वाहन का सुख मिलेगा। अपने विरोधियों से बना भय दूर होगा।

(पे,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो)

कन्या

नया निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा। गृह परिवार में रोग-बीमारी से मन चिन्ताग्रस्त रहेगा। गृहस्थ जीवन में अशान्ति बनेगी। व्यापार में यथाशक्ति धनोपार्जन करने का प्रयास सफल होगा। मासान्त उत्तम नहीं, खर्च अधिक करना पड़ेगा। यदा कदा स्वास्थ्य में विकार होगा।

(भो,जा,जी,खा,खी,खू,खे,गा,गी)

मकर

छोटे तनाव के कारण महत्त्वपूर्ण लाभ से वंचित रहेगा। मित्रों से विवाद होगा, कार्य सिद्ध न होने देंगे। व्यापार कार्य हाथी की चाल से चलता रहेगा। पर परिवार में विशेष सुख प्राप्त होगा। दौड़-धूप की अधिकता रहेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मास में ऋण का लेन-देन कदापि न करें।

(क,की,कु,घ,ङ,ँ,छ,के,को,ह)

मिथुन

आपके मान-सम्मान की वृद्धि होगी। अधिकारियों से लाभ होगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पारिवारिक हित के लिए प्रयासरत रहेंगे। दिमागी तौर पर किये जा रहे प्रयत्नों से उद्योग-धन्धों में विशेष सफलता मिलेगी और हर्ष भी होगा।

(रा, री, रु, रे, ता, ति, तु, ते)

तुला

स्वास्थ्य में सुधार, मानसिक शान्ति, पुण्य संस्कार की वृद्धि, परिवार, स्त्री, संतान का सहयोग मिलेगा। वाहन सुख, आमोद प्रमोद में लिप्त रहेंगें। उत्तरार्ध में मानसिक अस्थिरता, उद्वेग तथा शरीरिक कष्ट का योग बना है। आथिक उन्नति भी होगी।

(गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दो)

कुंभ

स्वास्थ्य में सुधार होगा। सन्तान सम्बन्धी चिन्ता सतायेगी। आयु एवं जीवन के लिए चिन्तित रहना होगा। मातृपक्ष व पितृपक्ष से कष्ट व चिन्ता बनेगी। संतान पक्ष से भी चिन्ता का योग है। शत्रु से छुटकारा व लाभ होगा।

(ह,हु,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो)

कर्क

मास में स्वास्थ्य की गड़बड़ी तथा व्यय की अधिकता बनी रहेगी। रोजी-रोटी के लिए बहुत मेहनत और एकाग्रता अपनाने से सफलता मिलेगी, अन्यथा पश्चाताप करना पड़ेगा। महिलाओं की मित्रता से सतर्कता बरतें।

(तो,ना,नी,नू,ने,या,यी,यू)

वश्चिक

मासारम्भ में बौद्धिक विकास से शिक्षा सामग्री वाले व्यवसायों को विशेष लाभ, परन्तु तस्कर भय से अकस्मातू हानि की सम्भावना। आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। व्यर्थ खर्च भी होगा।

(दी,दू,थ,झ,दे,दे,च,चि)

मीन

पूर्व मास की अपेक्षा यह मास लाभप्रद होगा तथा शान्ति मिलेगी। पुरानी आजीविका के क्षेत्र में कठोर श्रम संघर्ष द्वारा सामान्य सुविधा बनेगी। यदा कदा स्वास्थ्य में विकार होगा।

कोरोना और डेंगू से बचाव जरुरी तभी मिलेंगी पर्वों की खुशियां पूरी

मच्छर कहाँ पनपते हैं?

डेंगू एवं चिकुनगुनिया फैलाने वाले मच्छर रुके हुए पानी में पनपते हैं और दिन के समय काटते हैं।

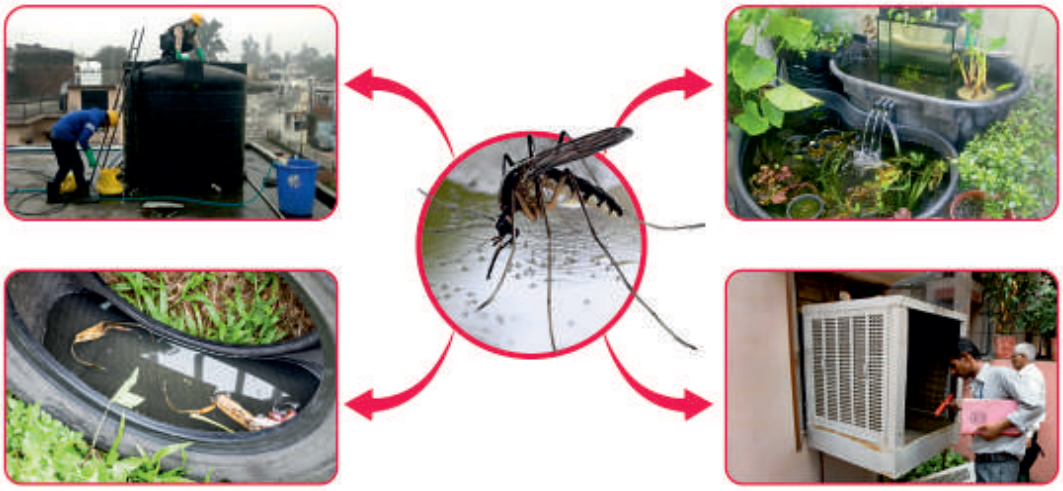

डेंगू से बचने के लिए अपनाएं सरल उपाय जिससे मच्छरों का पनपना पूरी तरह नष्ट हो जाए।

डेंगू से बचाव के उपाय

- सप्ताह में एक बार कूलर, फूलदान, पशु व पक्षियों के पानी के बर्तन इत्यादि को खाली करें, रगड़कर साफ करें एवं सुखा कर ही पुनः पानी भरें।
- पुराने टायर, डिस्पोजेबल कप, नारियल के खोल इत्यादि में पानी जमा न होने दें।
- पानी के सभी बर्तन, टंकी इत्यादि को पूरी तरह ढककर रखें।
- मच्छर द्वारा काटे जाने से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को पूरी तरह ढकें।
- यदि तेज बुखार के साथ सिर दर्द/आँखों के पीछे दर्द, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते और थकान हो तो तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्र पर जाएं।

अधिक जानकारी के लिए अपने नज़दीकी स्वास्थ्यकर्मी/स्वास्थ्य केन्द्र से आज ही सम्पर्क करें।

हमने ठाना है, डेंगू मिटाना है।

दो गज़ की दूरी, मास्क है जरुरी

राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश

RNI No. DELHIN/2016/71433

एक
मास्क लगाए
हर एक

दो
दो गज़ की
दूरी हो

तीन
धोकर
बार-बार हाथ
रखें क्लीन

चार
इम्युनिटी
बढ़ाकर
करें वार

कोरोना की होगी हार!

निःशुल्क एम्बुलेंस के लिए 108 पर कॉल करें

चिकित्सकीय सहायता के लिए कॉल करें हेल्पलाइन 1800-180-5145

आरोग्य सेतु एवं आयुष सुरक्षा कवच एप का प्रयोग करें

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश